

विभाग की संकल्पना

“भारतीय डाक-सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध,
प्रौद्योगिकी परिचालित,
व्यावसायिक दृष्टि से संचालित तथा
प्रगतिशील संगठन”

VISION OF THE DEPARTMENT

*“India Post a socially
committed, technology driven,
professionally managed &
forward looking Organisation”*

अध्याय 1

पुनरीक्षा

प्रस्तावना

1.1 भारतीय डाक व्यवस्था वर्तमान में कई सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है: संचार सेवाएं (पत्र, पोस्टकार्ड आदि), ढुलाई सेवाएं (पार्सल, लाजिस्टिक पोस्ट), वित्तीय सेवाएं (बचत बैंक, मनीआर्डर, अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा, डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी, डाक जीवन बीमा) और प्रीमियम मूल्यवर्धित सेवाएं (जैसे स्पीड पोस्ट, व्यवसाय डाक, रिटेल पोस्ट)। डाकघर बचत बैंक अपने नेटवर्क, खातों और वार्षिक जमा के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा बैंक है।

विभाग के उद्देश्य

1.2 डाक विभाग सभी लोगों को सस्ती कीमतों पर देश में बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके उद्देश्य हैं :-

- जनजातीय, पहाड़ी तथा दूर-दराज के इलाकों सहित देश के सभी भागों में बुनियादी डाक सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करना।
- कार्य-कुशल, विश्वसनीय और किफायती सेवा प्रदान करना।
- बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करना।
- बढ़ते कार्य की मात्रा को कुशलता से निपटाने के लिए सेवाओं का आधुनिकीकरण और इस प्रकार ग्राहक एवं कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि करना।
- एक प्रगतिशील संगठन बनाना, और
- अधिक संसाधन जुटाना तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार लाना।

दायित्व, चुनौतियां और कार्य-नीतियां

1.3 विश्वभर में डाकघर की भूमिका में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल और नई प्रौद्योगिकियां पारंपरिक डाक कार्यकलापों की पूरक बन रही हैं। हर कहीं, डाकघर प्रत्येक देश की सामाजिक, आर्थिक जरूरतों के अनुरूप अनेक जनोपयोगी एवं नई वित्तीय सेवाएं प्रदान करके निरंतर नए व्यवसाय अपना रहा है जिससे उसकी विक्रय क्षमता बढ़ने में मदद मिली है। साथ-ही-साथ डाकघर प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके पारंपरिक सेवाओं को उन्नत बना रहा है, तथा प्राइवेट कुरियर उद्योग से बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं संचार प्रौद्योगिकी में हो रहे निरंतर विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को त्वरित, अधिक विश्वसनीय और अधिक उत्तरदायी सेवा प्रदान करने की चुनौती का सामना करने के लिए नए उत्पाद और सेवाएं शुरू कर रहा है।

1.4 जहां तक समूचे देश में, भू-भाग को ध्यान में रखे बिना, सस्ती कीमतों पर बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करने का संबंध है, भारतीय डाक सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए इसने 31-3-2006 तक 1,55,333 डाकघरों का नेटवर्क स्थापित किया है जिनमें से 1,25,350 शाखा डाकघर हैं जो पूरी तरह ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन डाकघरों के जरिए यह देश में कहीं भी प्रत्येक ग्राहक के घर पर डाक का दैनिक वितरण और लैटर बॉक्सों के जरिए पत्रों का संग्रहण सुनिश्चित करता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर ग्राहकों को अनेक बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें बैंकिंग और बीमा सेवाएं भी शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों के सभी डाकघरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुए डाकघरों के माध्यम से बिल संग्रहण सुविधा प्रदान की जा रही है जबकि शहरी क्षेत्रों में चुने हुए डाकघरों में कतिपय मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। डाक विभाग ने 18 जुलाई, 2005 से देशभर में 'डाक पिकअप सुविधा' की शुरुआत की है। इस सुविधा के अंतर्गत डाक वितरण के समय

Chapter 1

OVERVIEW

Introduction

1.1 The Indian Postal System currently provides a number of services which can be broadly classified into four categories: Communication services (Letters, Post Cards, etc.), Transportation services (Parcel, Logistics Post), Financial services (Savings Bank, Money Order, International Money Transfer Service, Public-Private Partnerships for extending financial service outreach through the post office network, Postal Life Insurance) and Premium Value Added Services (Like Speed Post, Business Post, Retail Post). The Post Office Saving Bank is the largest Bank in India in terms of network, accounts and annual deposits.

Objectives of the Department

1.2 The Department of Posts is committed to provide universal access to basic postal services in the country at affordable prices. The objectives of the Department are to: -

- ensure availability of basic postal services in all parts of the country, including tribal, hilly and remote areas.
- provide efficient, reliable and economic service.
- provide value-added services according to market requirements.
- modernize the services to handle the growing volume of work with efficiency and thereby enhance customer and employee satisfaction.
- be a forward-looking organization, and
- generate more resources and improve financial performance.

Responsibilities, Challenges and Strategies

1.3 The role of the Post Office is undergoing transformation the world over, as electronic mail and new technologies supplement traditional postal activities. Everywhere, the Post Office is increasingly adopting new businesses that help to optimise its retailing strength, by providing a range of public utilities and new financial services that are relevant to the socio-economic needs of each country. It is also simultaneously upgrading traditional services through induction of technology, and introducing new products and services in order to meet the challenges of providing faster, more reliable, and more responsive service to the customer in the face of increasing competition from the private courier industry and continuing advances in communication technology.

1.4 India Post is committed to fulfill the Universal Service Obligation in terms of providing basic postal services throughout the country, irrespective of terrain, at an affordable price. For meeting this requirement it has set up a network of 1,55,333 Post Offices as on 31.3.2006, out of which 1,25,350 are Branch Post Offices catering exclusively to the rural areas. Through these offices it ensures daily delivery of Dak at the doorstep of every customer any where in the country and collection of letters through Letter Boxes. Post Offices in urban and rural areas provide a range of basic postal services to the customers, including banking and insurance services. Bill collection facilities are being extended through all Post Offices in urban areas, and identified Post Offices in rural areas, while certain value added services are being provided in selected offices in urban areas. The Department of Posts has launched 'Pick Up Mail Facility' w.e.f. 18th July, 2005 in the

ही डाकिया साधारण डाक, स्पीड पोस्ट वस्तुएं पिकअप कर लेगा और ग्राहकों को उनके घर पर ही डाक-टिकट और डाक लेखन सामग्री का विक्रय करेगा। 'पिक-अप वोल्यूम' में नियमित वृद्धि हो रही है।

1.5 देश में कहीं भी संचार के सस्ते साधन प्रदान करने के अलावा भारतीय डाक वाणिज्य, उद्योग, सरकार तथा सांस्थानिक निकायों जैसे समाज के विशिष्ट खण्डों की उभरती जरूरतों को भी पूरा करती है जो त्वरित और मूल्यवर्धित सेवाओं की मांग करते हैं। इसके फलस्वरूप, इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राहकों के अनुकूल अनेक उत्पादों और सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके डाक प्रचालन कार्यों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत हुई। ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समय की दृष्टि से संवेदनशील डाक की विभिन्न श्रेणियों की प्रोसेसिंग को प्राथमिकता देना भी आवश्यक हो गया। हाल के वर्षों में भारतीय डाक द्वारा प्रदान की गई मूल्यवर्धित सेवाओं में स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बधाई डाक, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, बिल मेल पोस्ट, ई-पोस्ट और ई-बिल पोस्ट सेवाएं शामिल हैं। 'तत्काल मनीआर्डर' नाम से एक नई वित्तीय सेवा जनवरी, 2006 से शुरू की गई है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ गठजोड़ करके 20 जनवरी, 2006 से डाकघर बचत बैंक खाताधारकों को दुर्घटना मृत्यु कवर प्रदान किया गया है। यह ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के खाताधारकों के लिए काफी आकर्षक है क्योंकि उन्हें अभी तक कोई जोखिम कवर नहीं मिल रहा है।

1.6 ग्राहक को किफायती और व्यवहार्य सेवाएं प्रदान करने की चुनौती भी एक निरंतर चिंता का विषय है। वर्ष 2005-06 के दौरान 62, 333.72 मिलियन रु. के कुल कार्यकारी व्यय की

तुलना में कुल राजस्व 50,234.88 मिलियन रु. था। इस प्रकार 12,098.84 मिलियन रुपए का अंतर रहा। डाक राजस्व में वृद्धि 13.35 प्रतिशत थी। जबकि, पिछले वर्ष के बजट घाटे की तुलना में 12.44 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

1.7 पिछले दशक में वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण के परिणामस्वरूप ग्राहकों की उभरती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डाक विभाग का पूर्णतया समर्पित डाकघरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जो लघु बचत सहित कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे। डाकघरों की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप 'वन-स्टॉप-पोस्ट फाइनेन्स-शॉप' (जिसे डाक वित्त मार्ट कहा जाता है) के रूप में पूर्णतया रिटेलिंग आउटलेट प्रदान किए जाएंगे जहां कुशल स्टाफ द्वारा जमाकर्ताओं को स्थल पर ही निवेश के संबंध में सलाह दी जाएगी।

1.8 प्रभावपूर्ण तरीके से और समयबद्ध कुशल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय डाक ने 8362.7 मिलियन रुपये की बजट सहायता द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसंख्य डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने और एक नेटवर्क के माध्यम से इन सभी डाकघरों का आपस में सहसंबंध स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कर्मचारियों को बेहतर कार्य-वातावरण देने तथा उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ताकि ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि दी जा सके, भारतीय डाक ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 157.2 मिलियन रुपये के परिव्यय से 811 डाकघरों में कार्य-वातावरण को सुधारने की योजना बनाई है तथा 40 मिलियन रुपये के परिव्यय द्वारा 1600 डाकघरों को नई इलेक्ट्रो-मैकेनिकल डिवाइस से उपस्करबद्ध करने का लक्ष्य रखा है।

country. Under this facility the postmen while delivering the Dak will pick up ordinary mails, speed post articles and sale of postage stamps & stationery at the doorstep of customers. There has been a steady increase in the 'Pick Up Volume'.

1.5 Besides providing access to affordable means of communication anywhere in the country, India Post also meets the emerging needs of specific segments of society like commerce, industry, Government and institutional bodies that demand quicker, value added services. This has resulted in the need to customise a number of products and services to meet these requirements and modernise postal operations through induction of technology. It has also become necessary to prioritise the processing of different categories of mail according to time sensitivity to meet customer expectations. The value added postal services offered by India Post include Speed Post, Business Post, Express Parcel Post, Greetings Post, Speed Post Passport Service, Bill Mail Post, e-Post and e-Bill Post. A new financial service of Instant Money Order(iMO) has been introduced w.e.f. January, 2006. Accidental Death Insurance cover to POSB account holders was launched on 20th January, 2006 after tying up with the Oriental Insurance Company Limited (OIC). It is very attractive to account holders of rural and remote areas, as generally they do not have any risk cover whatsoever.

1.6 The challenge of providing cost effective and viable services to the customer is also a matter of constant concern. The total revenue during 2005-06

was Rs. 50,234.88 Million against the net working expenses of Rs. 62,333.72 Million, leaving a gap of Rs.12,098.84 Million. The increase in postal revenue was to the extent of 13.35% whereas there was decrease in the budgetary deficit by 12.44% over the previous year.

1.7 With liberalization of the financial sector in the last decade, the Post Office proposes to meet the rising expectations of its customers by providing dedicated offices rendering a basket of financial services including small savings in line with the International trend of the post office providing exclusive retailing outlets as a One-Stop – Post Finance-Shop (called Postal Finance Marts). Postal Finance Marts are manned by qualified staff to provide on the spot investment advice to depositors.

1.8 With an objective to render quality service in an effective and time bound manner, India Post has laid a target to computerize all Head Post Offices and a large number of Sub Post Offices in urban as well as rural areas and to link all these Post Offices through a network during the 10th Five Year Plan with a budgetary support of Rs. 8362.7 Million. To provide better working environment for the staff and to accelerate their functional efficiency, so as to render greater satisfaction to the customers, India Post has planned to improve ergonomics in 811 Post Offices with an outlay of Rs. 157.2 Million and also to equip 1600 Post Offices with new electro-mechanical operational devices with an outlay of Rs. 40 Million during the 10th Five Year Plan.

अध्याय 2

संगठन

2.1 डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग है। यह विभाग श्री दयानिधि मारन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अधीन काम कर रहा है। डॉ. शकील अहमद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। श्री आई.एम.जी खान, सचिव, डाक विभाग के साथ-साथ महानिदेशक, भारतीय डाक और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड हैं।

मुख्यालय में योजना एवं नीति संबंधी कार्य

2.2 डाक सेवा बोर्ड इस विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय है। इसमें अध्यक्ष और तीन सदस्य हैं। बोर्ड के तीन सदस्यों के पास प्रचालन और विपणन, बुनियादी संरचना तथा वित्तीय सेवाएं एवं कार्मिक प्रकार्यात्मक विभाग हैं। विभाग के संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार इस बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। सचिव, डाक सेवा बोर्ड द्वारा बोर्ड को सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यालय में उप महानिदेशक, निदेशक तथा सहायक महानिदेशक बोर्ड को आवश्यक सहयोग देते हैं।

संगठनात्मक परिवर्तन

2.3 प्रौद्योगिकी की शुरुआत के कारण सामने आई चुनौतियों के प्रत्युत्तर के रूप में हाल में डाक विभाग के संगठनात्मक स्वरूप का पुनर्गठन किया जा रहा है। कार्यात्मक पुनर्गठन इस प्रकार किया गया है ताकि उच्च प्रबंधन की समन्वय एवं मॉनीटरिंग की भूमिका को यथोचित महत्व देते हुए परिवर्तन की संक्रमणकालीन कठिनाइयों से निपटा जा सके। प्रबंधन की सहायता के लिए परम्परागत पिरामिडीय प्रणाली को डैस्क प्रणाली में बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन सुधारों की शुरुआत एक उत्तरदायी, संवेदनशील एवं कार्यकुशल प्रबंधन स्थापित करने के लिए जरूरी सक्रियता के साथ इस प्रणाली को गतिशील बनाने के लिए की गई है।

डाक सर्किल

2.4 डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 22 डाक सर्किलों में बांटा गया है। प्रत्येक सर्किल राज्य का को-टर्मिनस होता है। लेकिन गुजरात सर्किल जिसमें दमन एवं दीव, दादर

एवं नगर हवेली, केरल सर्किल जिसमें लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र, महाराष्ट्र सर्किल जिसमें गोवा; पूर्वोत्तर सर्किल जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा, पंजाब सर्किल जिसमें चंडीगढ़ संघ क्षेत्र, तमिलनाडु सर्किल जिसमें पंडिचेरी, पश्चिम बंगाल सर्किल जिसमें सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, इसके अपवाद हैं। प्रत्येक सर्किल प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/ मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के अधीन है। प्रत्येक सर्किल को परिक्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें फील्ड यूनिटें होती हैं, जिन्हें डिवीजन (डाक/रेल डाक सेवा डिवीजन) कहा जाता है। प्रत्येक परिक्षेत्र पोस्टमास्टर जनरल के अधीन है जो उस क्षेत्र का डाक प्रबंधक होता है। सर्किलों और परिक्षेत्रों में कार्यसंचालन में सहयोग देने के लिए स्टैम्प डिपो, डाक भंडार डिपो तथा मेल मोटर सेवा आदि जैसी अन्य संभार यूनिटें भी होती हैं।

सेना डाक सेवा

2.5 इन 22 सर्किलों के अलावा, सशस्त्र सेनाओं की संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बेस सर्किल भी है। बेस सर्किल अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा के अधीन है। सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में भारतीय डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी होते हैं। सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों के लिए भी 75 प्रतिशत कार्मिक डाक विभाग से लिए जाते हैं और शेष कार्मिक सेना द्वारा भर्ती किए जाते हैं।

प्रचालन यूनिट

2.6 देश भर में डाकघरों को प्रधान, उप तथा शाखा डाकघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण डाक सेवा डाकघर, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उप डाकघर विभागीय डाकघर हैं जो ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में हैं। प्रधान डाकघरों को उनके कार्यभार तथा कर्मचारियों की संख्या के अनुसार पांच श्रेणियों में विभक्त किया गया है, इनमें से सबसे बड़े डाकघर मुंबई और कोलकाता के जनरल पोस्ट आफिस (जी.पी.ओ.) हैं और उनके बाद अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ स्थित जी.पी.ओ. आते हैं।

Chapter 2

ORGANISATION

2.1 The Department of Posts under the Ministry of Communications and Information Technology has Shri Dayanidhi Maran as Minister-in-charge with Dr. Shakeel Ahmad as Minister of State. Shri IMG Khan is the Secretary, Department of Posts, Director General, Department of Posts and Chairman, Postal Services Board.

Planning and Policy Functioning at Headquarters

2.2 The Postal Services Board is the apex management body of the Department, comprising the Chairman and three Members. The three Members of the Board hold functional portfolios of Operations & Marketing, Infrastructure and Financial Services and Personnel. The Joint Secretary and Financial Adviser to the Department is a permanent invitee to the Board. The Board is assisted by the Secretary, Postal Services Board. Deputy Directors General, Directors and Assistant Directors General of the Department provide necessary support to the Board at the Headquarters.

Organisational changes

2.3 The organisational set up of the Department has been undergoing restructuring in recent times as a response to the challenges faced due to induction of technology. The functional restructuring is designed to tackle the transitional problems of change giving due importance to the coordinating and monitoring role of the higher management. Steps have been taken to substitute the traditional pyramidal system with a desk system to support the management. These reforms were introduced to infuse the system with dynamism needed to create a responsive, sensitive & efficient management.

Postal Circles

2.4 For providing postal services, the whole country has been divided into 22 Postal Circles. Each circle is co-terminus with a State except Gujarat Circle which includes Daman & Diu, Dadra and Nagar Haveli; Kerala

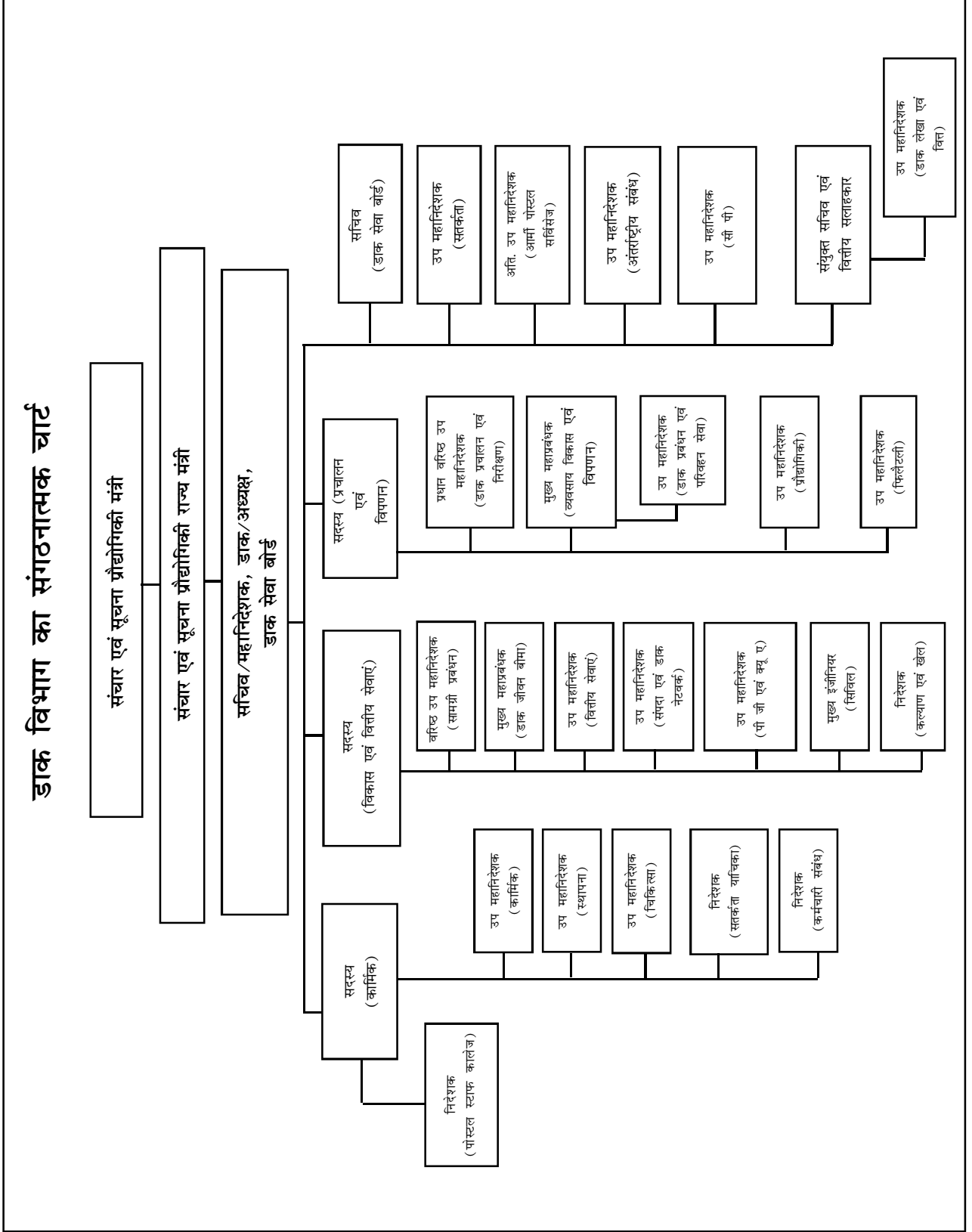
Circle includes the Union Territory of Lakshadweep; Maharashtra Circle includes Goa; North Eastern Circle consists of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura; Punjab Circle includes the Union Territory of Chandigarh; Tamil Nadu Circle includes Pondicherry; West Bengal Circle includes Sikkim and the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands. A Principal Chief Postmaster General/Chief Postmaster General heads each Circle. Each circle is divided into Regions comprising groups of field units, called Divisions (Postal/RMS Divisions). Each Region is headed by a Postmaster General who is the Postal Manager of the area. In the Circles and Regions there are other functional supporting logistical units like Stamp Depots, Store Depots and Mail Motor Service.

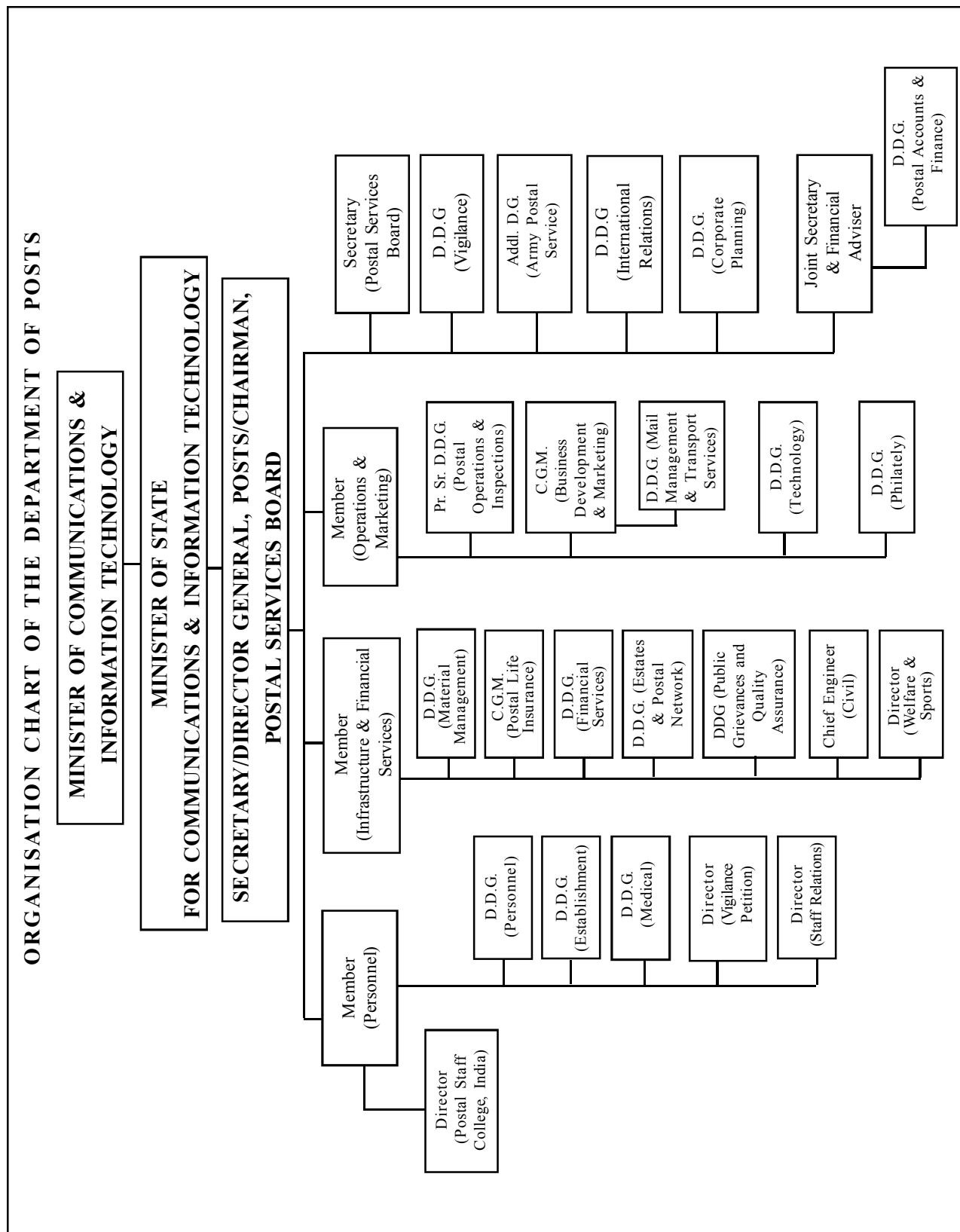
Army Postal Services

2.5 Over and above these 22 Circles, the communication needs of the armed forces are catered to by the Base Circle. The Base Circle is headed by the Additional Director General, Army Postal Service. The officer cadre of Army Postal Services is drawn on deputation from the Indian Postal Service. 75 per cent of the other ranks of the Army Postal Service are drawn from the Department of Posts and the remaining personnel are recruited by the Army.

Operational Units

2.6 Post Offices in the country are categorized as Head, Sub and Branch Post Office. Gramin Dak Sewa Post Offices are located in rural areas. The Sub Post Offices are departmental offices located in both rural and urban areas. Head Post Offices are graded into five categories according to their workload and staff strength, the largest being the General Post Offices (GPOs) at Mumbai and Kolkata, followed by GPOs at Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Kanpur, Lucknow and so on.

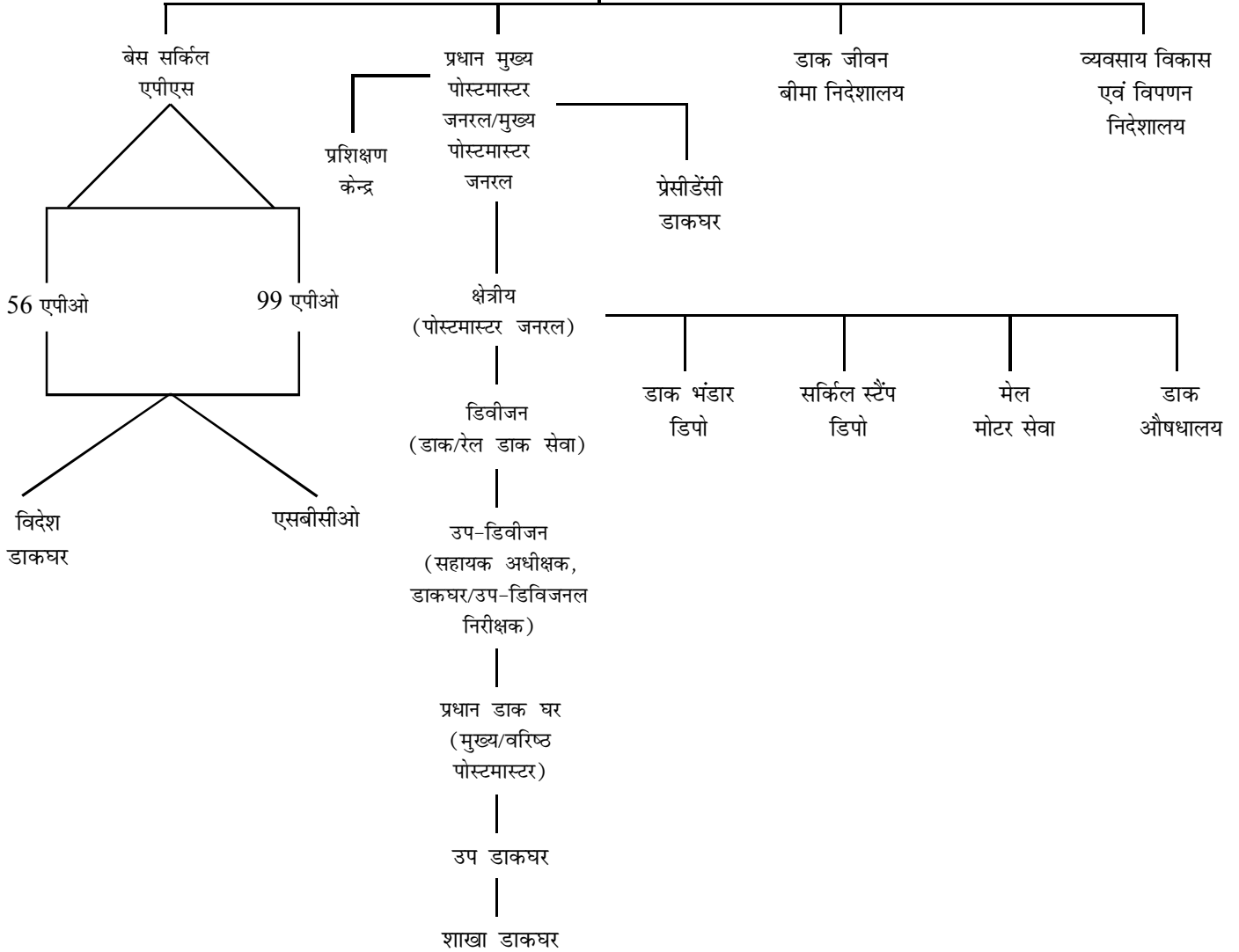




**डाक विभाग
(कार्यात्मक इकाईयां)**

सचिव डाक

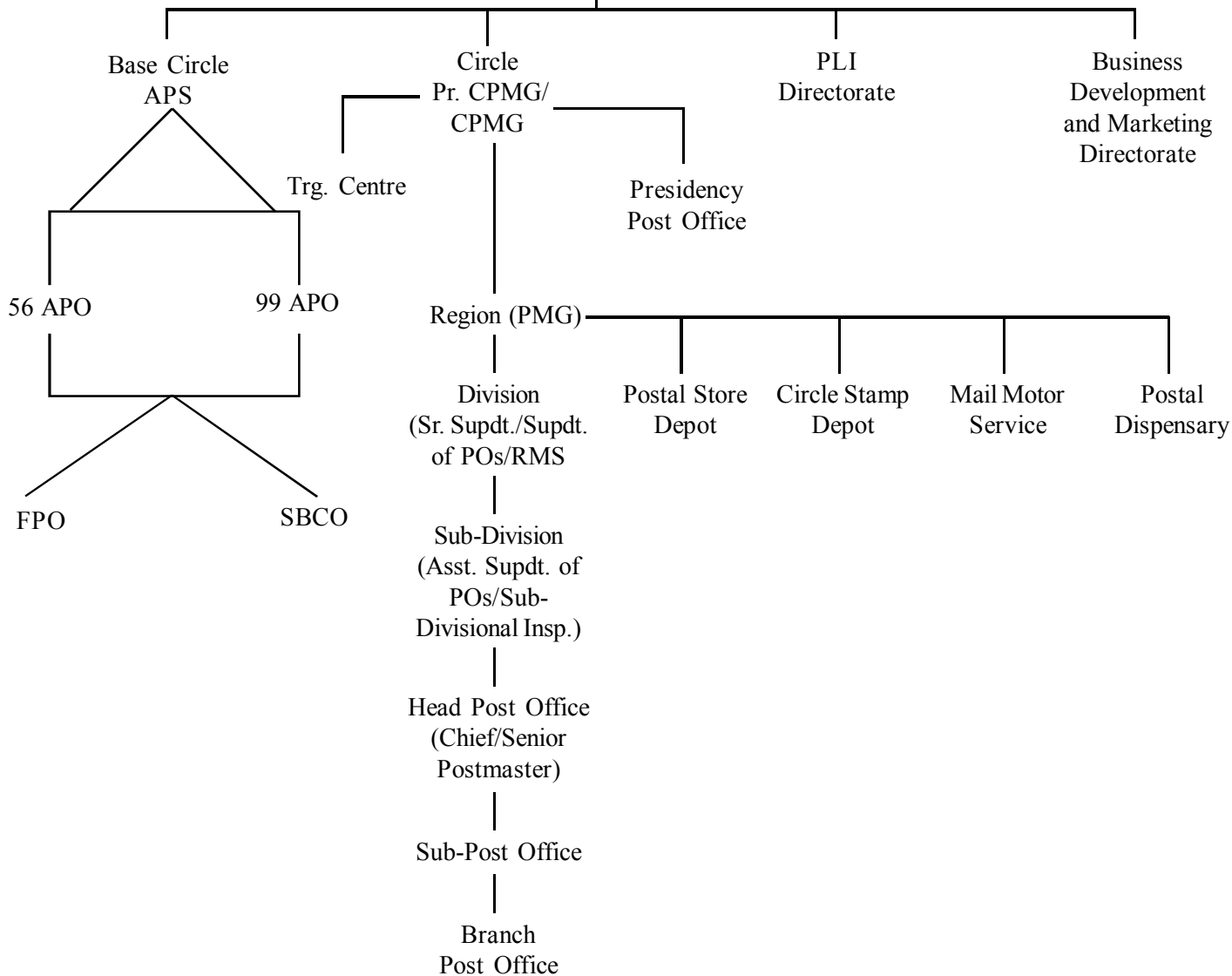
सदस्य



**DEPARTMENT OF POSTS
(Functional Units)**

SECRETARY (POSTS)

MEMBERS



अध्याय 3

डाक प्रचालन

डाक नेटवर्क

3.1 भारत का विश्व में 1,55,333 डाकघरों के साथ सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जिसमें से 89% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 23,344 डाकघर थे जो मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में थे। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात से इस नेटवर्क में 7 गुना वृद्धि हुई है और यह विस्तार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। औसतन एक डाकघर 21.2 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र तथा 6,623 की जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है।

3.2 देश के डाक नेटवर्क का विस्तार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को खोलकर किया गया। अतिरिक्त विभागीय डाकघर अंशकालिक आधार पर कार्य करते हैं जिसमें कार्य अवधि न्यूनतम तीन घंटे और अधिकतम 5 घंटे होनी चाहिए। उन्हें अंशकालिक स्थानीय कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है जिन्हें प्रदत्त सेवा के लिए भत्ता दिया जाता है। दूसरी ओर विभागीय डाकघर आठ घंटे की अवधि के लिए कार्य करता है तथा उन्हें पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है।

3.3 डाकघरों को दूरी, जनसंख्या तथा आय मानदंडों के आधार पर जिन्हें इस प्रयोजन हेतु निर्धारित किया गया है, खोला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए सभी डाकघरों को रियायत दी जाती है तथा यह सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 66.67% से पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में 85% तक दी जाती है। तथापि शहरी क्षेत्रों में डाकघरों को कोई रियायत प्रदान नहीं की जाती क्योंकि उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो, तथा प्रथम वर्ष के पश्चात अपनी लागत से 5% अधिक अर्जित करें।

3.4 डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए डाकघर खोलने के लक्ष्य वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत शुरुआत से रखे गए हैं। योजना सहयोग नए डाकघर खोलने की आवर्ती एवं अनावर्ती लागतों के लिए भी उस योजना अवधि में उपलब्ध था जिसमें वे खोले गए थे। नेटवर्क के विस्तार की नीति में हाल के वर्षों में

कुछ परिवर्तन हुए हैं जिसमें विभाग के घाटे को कम करने पर ध्यान दिया गया है जिसमें 40% से अधिक नेटवर्क में दी जाने वाली रियायत के कारण है। परियोजना हेतु योजना सहयोग योजना लक्ष्यों में कमी के फलस्वरूप कम हो गया है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग भी पर्याप्त रूप से कम हुआ है; साथ ही, 2004-05 से नए डाकघर खोलने के लिए किसी भी निधि का आवंटन नहीं किया गया है। कोई डाकघर खोलने के लिए आवश्यक मैनपावर को भी मौजूदा संसाधनों को पुनःव्यवस्थित करके पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार जनवरी 2003 से सर्किल अध्यक्षों को एक दूसरे के निकट अवस्थित एक या दो कर्मचारी वाले डाकघरों को पुनःव्यवस्थित करने का अधिकार दिया गया है, अर्थात् न्यूनतम निर्धारित दूरी से कम उन क्षेत्रों में जिन्हें डाकघर सुविधाओं की आवश्यकता है। इसी प्रकार जनवरी, 2005 से उन्हें सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक दूसरे के नजदीक स्थित अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को जरूरतमंद क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने की शक्तियां दी गई हैं। इससे विभाग को जरूरतमंद क्षेत्रों की उभरती अपेक्षाओं को पूरा करने और साथ ही नेटवर्क का यौक्तिकीकरण करने में मदद मिली है, जो 10वीं योजना नीति के अंतर्गत आवश्यक है।

3.5 मितव्ययी तरीकों से डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के तरीकों की पहचान हेतु भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। लाइसेंसशुदा स्टैम्प वेन्डर स्कीम, लाइसेंसशुदा पोस्टल एजेंट स्कीम तथा पंचायत संचार सेवा केन्द्र कुछ ऐसे कदम हैं जो इस संबंध में उठाए गए हैं। वर्तमान में, 6604 पंचायत संचार सेवा केन्द्र कार्यरत हैं। जैसे कि आकलन दर्शाता है कि पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का इच्छित प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए, पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखे गए हैं। पहुंच उपलब्ध कराने के लिए, वैकल्पिक साधनों जैसे फ्रैंचाइसी देना, पर भी विचार हो रहा है।

3.6 नेटवर्क का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के माध्यम से वायरलेस-इन-

Chapter 3

POSTAL OPERATIONS

Postal Network

3.1 India has the largest Postal Network in the world with over 1,55,333 Post Offices of which 89% are in the rural areas. At the time of independence, there were 23,344 Post Offices, which were primarily in the urban areas. Thus, the network has registered a seven-fold growth since independence; and the focus of this expansion is primarily in the rural areas. On an average, a Post Office serves an area of 21.2 sq. km and population of 6,623 persons.

3.2 Expansion of the Postal Network in the country, especially in rural areas, was done mainly by opening Extra Departmental Post Offices and on a smaller scale by opening Departmental Post Offices. The Extra Departmental Post Office function on part-time basis for a minimum of three hours and a maximum of five hours. They are manned by part-time locally recruited employees, who are paid an allowance for the services they render. On the other hand, the Departmental Post Offices function for a period of eight hours and are manned by full-fledged departmental employees.

3.3 Post Offices are opened subject to distance, population and income norms fixed for the purpose. In order to fulfill the Universal Service Obligation subsidy is given to all Post Offices opened in rural area, which ranges from 66.67% in normal rural areas to 85% in hilly, tribal, desert and remote areas. However, no subsidy is offered to Post Offices in urban areas, as they are expected to be financially self-sufficient and earn 5% more than their cost after the first year.

3.4 Targets for opening post offices were being given since the inception of the scheme for expansion of the Postal Network under Annual Plans. Plan support was also available for the recurring and non-recurring costs of the new Post Offices during the Plan period in which

they were opened. The strategy for expansion of the network has undergone some modifications in recent years with increasing focus on reducing the deficit of the Department, over 40% of which is attributed to the subsidy on the network. Plan support for the scheme has dwindled substantially as a result of reduction of Plan targets and financial support under Plan has also reduced substantially, with no funds having been allotted for opening new post offices since 2004-2005. The manpower requirements for opening of new Post Offices were met only through redeployment of existing resources. Similarly, since January, 2003, Heads of Circles have been empowered to re-deploy existing single or double handed Post Offices located in close proximity to each other, i.e. at lesser than the minimum prescribed distance, to areas which are in need of Post Office facilities. Similarly, since January, 2005 they have been empowered to relocate Extra Departmental Branch Post Offices located in close proximity in normal rural areas to the needy areas. This has helped the Department to meet the emerging requirements in needy areas, while simultaneously rationalizing the network, as required under the 10th Plan Policy directives.

3.5 Efforts are also being made to identify means of providing postal services through more cost-effective measures. The Licensed Stamp Vendor Scheme, Licensed Postal Agents Scheme, and the Panchayat Sanchar Seva Yojana (PSSY) were some of the initiatives that were taken up in this regard. At present, 6604 Panchayat Sanchar Seva Kendras (PSSKs) are functioning. As assessment indicates PSSKs have not had the desired impact, no targets are now being fixed for opening PSSKs. Alternative means of providing access, such as franchising are also being explored.

3.6 The network is being utilized to provide mobile PCO facility at the doorstep of the customers in rural

लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बीएसएनएल के फ्रेंचाइसी के रूप में ग्रामीण संचार सेवा के अंतर्गत ग्राहकों के द्वार तक मोबाइल पीसीओ सुविधा प्रदान करने के लिए भी हो रहा है।

डाक काउंटर सेवाएं

3.7 डाकघर में डाक प्रचालनों में अन्य सेवाओं के साथ-साथ निम्नलिखित मूल डाक काउंटर सेवाओं का समूचा क्षेत्र शामिल है:-

- डाक-टिकट तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री
- पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग
- बीमाकृत वस्तुओं की बुकिंग
- मूल्यदेय वस्तुओं की बुकिंग
- मनीआर्डर और पोस्टल आर्डरों के माध्यम से धन प्रेषण
- पार्सलों की बुकिंग

3.8 परंपरागत रूप से ये सेवाएं मैनुअल काउंटर्स पर प्रदान की जा रही थीं। ग्राहकों को प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब काउंटर प्रचालनों को उत्तरोत्तर कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि एक ही खिड़की से अधिकाधिक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकें जिससे सेवाएं अधिक अनुक्रियाशील हों और उनमें गलती की संभावना भी कम हो।

3.9 "मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेटों" की श्रेणी के अंतर्गत डाक द्वारा कंपैक्ट डिस्क/फ्लॉपी डिस्क का पारेषण प्रारंभ किया गया। इन उपबंधों के अधीन शब्द मुद्रण से आशय मुद्रण के रूप में मान्य कोई वस्तु अथवा किसी यांत्रिक प्रक्रिया से है जिसका सामान्यतः कई समान (एक जैसी) प्रतियाँ उत्पादित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें मुद्रित पुस्तक या पुस्तकों सहित अथवा रहित काम्पैक्ट डिस्क अथवा फ्लॉपी पर पुस्तक या पुस्तकें शामिल हैं लेकिन इसमें टंकण, किसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार कार्बन प्रतियाँ, कम्प्यूटर मुद्रण, फोटोकापी करना या कोई भी ऐसी प्रक्रिया शामिल नहीं होगी।

तालिका 1 डाक परियात (मिलियन में)			
	2004-2005	2005-2006	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
1. पंजीकृत वस्तुएं	214.18	208.56	(-)2.62%
2. अपंजीकृत वस्तुएं	7146.18	6492.16	(-)9.15%
योग (1+2)	7360.36	6700.72	(-)8.96%

डाक की मात्रा

3.10 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-2006 के दौरान डाक परियात के तुलनात्मक आंकड़े तालिका-1 में दिए गए हैं।

मनीआर्डर सेवा

3.11 पिछले वर्ष के परियात की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पारेषित मनीआर्डर के मूल्य तथा मनीआर्डर परियात के तुलनात्मक आंकड़े तालिका-2 में दिए गए हैं।

तालिका 2 मनीआर्डर परियात तथा मूल्य			
	2004-05	2005-06	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
1. मनीआर्डर परियात (मिलियन में)	101.60	95.79	(-)5.72%
2. पारेषित मनीआर्डरों का मूल्य (रु. मिलियन में)	70521.65	71834.30	(+)1.86%

areas through GDS Employees of Department of Posts, as franchisees of BSNL, using the Wireless in Local Loop (WLL) Technology, under the Gramin Sanchar Seva.

Postal Counter Services

3.7 Postal operations at the post office counter encompass the entire gamut of the basic postal counter services which interalia include:

- (i) Sale of stamps and stationery
- (ii) Booking of registered articles
- (iii) Booking of insured articles
- (iv) Booking of value payable articles
- (v) Remittance of money through money orders and postal orders
- (vi) Booking of Parcels

3.8 Traditionally, these services were being provided at manually operated counters. Considering the vital need for providing the benefit of technology to the customers, the counter operations are now being progressively computerised to provide a greater range of service to the customer from a single window leading to services being more responsive, and error free.

3.9 The transmission of Compact Disks/Floppy Disks by post under the category of 'Book Packets containing Printed Books' was introduced. Under these provisions, the expression printing means any thing capable of being recognized as printing or any mechanical process ordinarily used to produce a number of identical copies including the book or books on compact disk or floppy with or without printed book or books but does not include type writing, carbon copies processed by any mechanical process, computer printing, photocopying or similar process.

TABLE 1			
MAIL TRAFFIC (in Million)			
	2004-2005	2005-2006	Increase/Decrease (in %age)
1. Registered	214.18	208.56	(-) 2.62%
2. Unregistered	7146.18	6492.16	(-) 9.15%
TOTAL (1+2)	7360.36	6700.72	(-) 8.96%

Mail Volume

3.10 Comparative statistics of mail traffic handled during 2005-2006 as compared to previous year is given in Table-1.

Money Order Service

3.11 Comparative statistics of Money Order traffic and the value of Money Orders transmitted, compared with the previous year is given in Table-2.

TABLE 2			
MONEY ORDER TRAFFIC AND VALUE			
	2004-05	2005-06	Increase/Decrease (in %age)
1. Money Order traffic (in Million)	101.60	95.79	(-) 5.72%
2. Value of MOs transmitted (Rs. in Million)	70521.65	71834.30	(+)1.86%

डाक प्रचालन

3.12 डाक प्रोसेसिंग, पारेषण तथा उनका वितरण विभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं। देश की 601319 पत्र पेटियों से पत्रों को एकत्रित किया जाता है। 455 रेल डाक सेवा (आर एम एस) कार्यालयों के नेटवर्क पर इनकी प्रोसेसिंग की जाती है तथा देश भर में सड़क, रेल तथा वायुयान द्वारा इन्हें प्रेषित किया जाता है।

डाक प्रबंधन

3.13 देशभर में अत्यधिक प्रभावी और अधिकतम कुशल डाक पारेषण नेटवर्क स्थापित करने की योजनाओं को व्यावहारिक रूप से लागू किया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभाग ने डाक परियात के विभिन्न भागों का पता लगाया है और प्रत्येक भाग के लिए परियात के निपटान का विशिष्ट तरीका निश्चित किया है। इस प्रकार महानगरों के बीच की डाक के लिए मेट्रो चैनल, राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों के बीच तथा इसके विपरीत के लिए राजधानी चैनल, स्थानीय डाक के लिए ग्रीन चैनल, थोक डाक के लिए

बिजनेस चैनल और समाचार पत्रों तथा आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के लिए पत्रिका चैनल जैसे विशिष्ट चैनल बनाए गए हैं।

3.14 दीपावली, क्रिसमस, रक्षाबंधन तथा नववर्ष जैसे फेस्टिवल सीजन के दौरान डाक की मात्रा में होने वाली आकस्मिक वृद्धि से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। प्रमुख शहरों में, लोगों को उनके पत्र सीधे गंतव्य थैलों में डालने के लिए उचित सुझाव दिया गया जिससे प्रेषितियों को पत्रों का वितरण जल्दी किया जा सके।

डाक पिक अप सुविधा

3.15 किफायती सेवा प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने हेतु डाक विभाग ने 18 जुलाई, 2005 से डाकिये द्वारा डाक पिकअप सुविधा को प्रारंभ किया। स्पीड पोस्ट 'पिकअप वोल्यूम' में लगातार वृद्धि रही थी। स्पीड पोस्ट वस्तुओं की मात्रा अगस्त, 2005 में 28,820 से बढ़कर मार्च, 2006 में 3,48,625 हो गई जो कि बारह गुणा अधिक है। सामान्य डाक की प्राप्ति (पिक-अप)

Mail Operations

3.12 Mail processing, transmission and delivery are the core activities of the Department. Mail is collected from 6,01,319 letter boxes in the country. This is processed by a network of 455 Railway Mail Service Offices, and conveyed by road, rail and airlines all over the country.

Mail Management

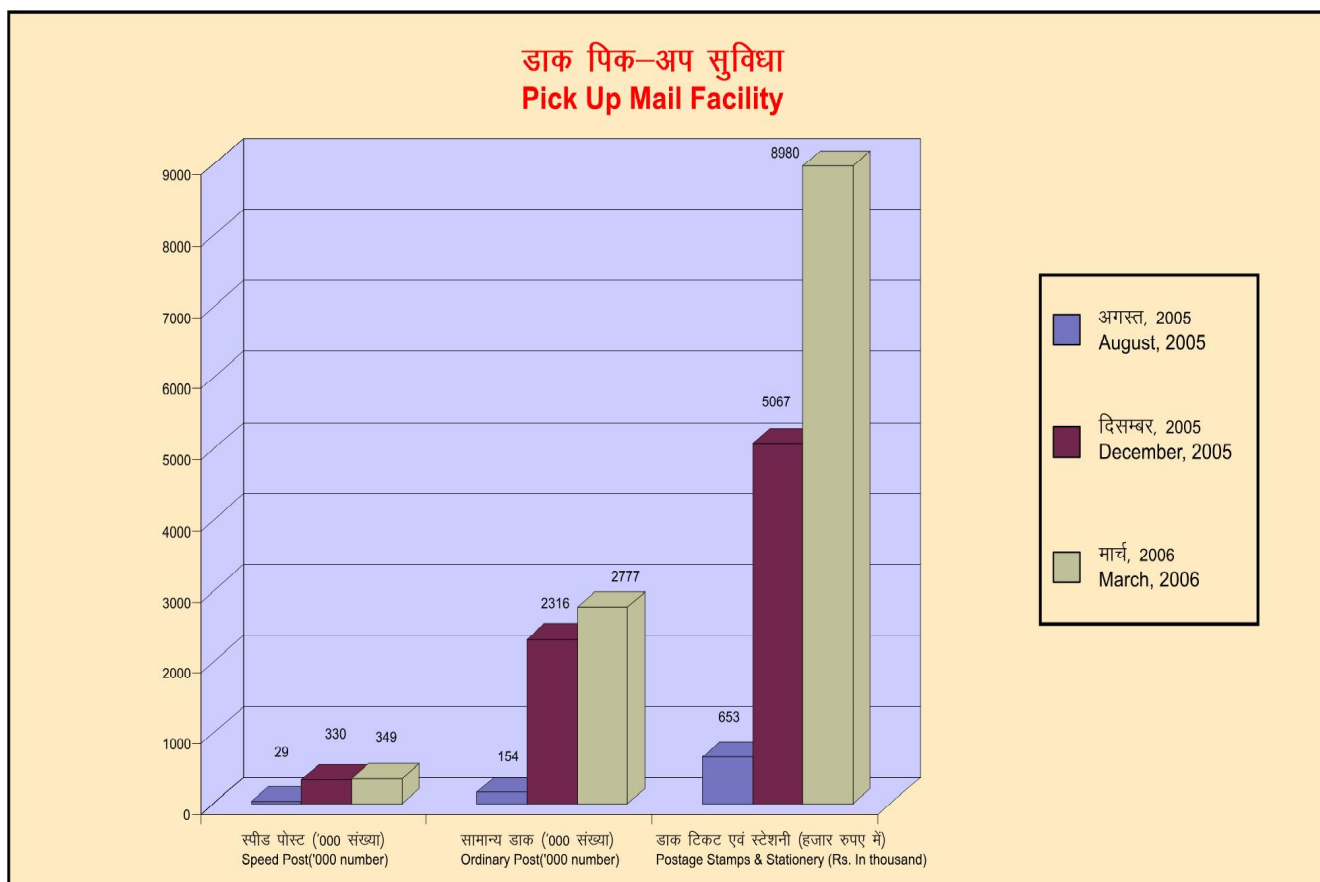
3.13 Plans for achieving an efficient mail transmission network throughout the country have been put into effect. With this objective the Department has identified different segments of mail traffic and devised exclusive handling for each segment. Thus, there are specialised channels like Metro Channel for mail between metro cities, Rajdhani Channel for mail between the national capital and the state capitals and vice-versa, Green Channel for

local mail, Business Channel for bulk mail and Patrika Channel for newspapers and periodicals.

3.14 Special arrangements to meet the sudden spurt in traffic during festival season like Diwali, Christmas, Raksha Bandhan and New Year were made. In major towns, appropriate guidance was provided to the members of the public to post their letters directly into the destination mailbags to speed up transmission and delivery to the addressees.

Pick up Mail Facility

3.15 In order to provide quality service and to increase revenue, the Department of Posts launched pick up of mail facility by postmen w.e.f. 18th July, 2005. There was a steady increase in the Speed Post 'Pick Up



अगस्त, 2005 में 1,53,666 वस्तुओं से बढ़कर मार्च, 2006 में 27,77,395 वस्तुएं तक हो गई और डाक टिकट और डाक स्टेशनरी की बिक्री अगस्त, 2005 में 0.65 मिलियन रु. से बढ़कर मार्च, 2006 में 8.98 मिलियन रु. हो गई।

डाक प्रचालनों का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण

3.16 विभाग ने डाक के पारेषण, प्रोसेसिंग तथा वितरण के कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से डाक के पारेषण, प्रोसेसिंग तथा वितरण के कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण की एक नीति प्रारंभ की है। डाक कार्यालयों के आधुनिकीकरण का उद्देश्य डाक कार्यालयों में बेहतर उपकरण उपलब्ध कराना और बेहतर कार्य के वातावरण का निर्माण करना है जिससे संपूर्ण कार्यकुशलता प्राप्त हो सके।

3.17 लेखादेय मदों जैसे पंजीकृत पत्रों, बीमाकृत मदों आदि की छंटाई को इन मदों के त्वरित निपटान एवं सुरक्षा के उद्देश्य से और शिकायतों /पूछताछ के मामले में अधिक शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

3.18 वर्ष 2005-06 के दौरान 4 मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया है जबकि 18 प्रधान रिपोर्ट कार्यालयों तथा 34 पंजीकरण केन्द्रों का भी कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

मेल मोटर सेवा (एम एम एस)

3.19 विभाग के 1207 मेल मोटर वाहनों और 486 स्टाफ कारों/निरीक्षण वाहनों के रखरखाव, प्रचालन और प्रशासन के लिए रेल मोटर सेवा उत्तरदायी है। विभाग के अपने मेल मोटर वाहन 98 स्टेशनों में चलते हैं। इनमें से 17 स्टेशनों पर बड़े मरम्मत कार्य और रखरखाव कार्य करने के लिए पूर्ण विकसित वर्कशाप सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्ष 2005-2006 के दौरान, विभागीय डाक वाहनों ने डाक प्रेषित करने के लिए 26.90 मिलियन कि.मी. की दूरी तय की। इस अवधि के दौरान एम.एम.एस. पर 550.92 मिलियन रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 2004-05 के दौरान औसत लागत प्रति कि.मी. 20.48 रु. थी। मुम्बई और दिल्ली में शहर के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए इसने वहां 135 सीएनजी प्रोपेल्लड मेल वैन खरीदी हैं और बेड़े में भारत स्टेज-III वाहन शामिल किए हैं।

3.20 वर्ष 2005-06 के दौरान, डाक विभाग ने वित्त मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करके प्रतिबंध से राहत पाते हुए योजना और गैर-योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वाहनों की अधिप्राप्ति की।

योजना

वाहन	26[टाटा टुरिन (16) टाटा सूमो (1) टाटा 407(6) टाटा 709 (3)]
तिपहिया	32[सीएनजी (9) डीजल (23)]
दुपहिया	18 टीवीएस 100 सीसी 4 स्ट्रोक

गैर-योजना

वाहन	51[आरटीवी सीएनजी (6) टाटा 407 (7), टाटा 410(6) टाटा 709(1) टाटा सूमो (16) टाटा टुरिन (6), मारुति ओमनी (5) मारुति जिप्सी (4)]
------	--

3.21 मेल मोटर सेवा के स्टोर इवेंटरी सिस्टम को डाक विभाग, हैदराबाद के साफ्टवेयर विकास केन्द्र द्वारा डिजाइन किए गए स्टोर माड्यूल साफ्टवेयर को शामिल करके कम्प्यूटरीकृत किया गया। वर्ष 2005-06 के दौरान, निम्नलिखित मेल मोटर सेवा प्रारंभ की गई:

स्टेशन का नाम	बेड़े की स्थिति
धनबाद (झारखण्ड)	3
बोकारो स्टील सिटी (झारखण्ड)	2
बेहरामपुर (उड़ीसा)	2
लक्षद्वीप	1

सामग्री प्रबंधन (एमएम)

3.22 विभागीय परिषद (जेसीएम) के स्टाफ पक्ष की मांग कि मैदानी क्षेत्र के स्टेशनों जहां गर्म वर्दी की आपूर्ति की जाती है, में तैनात फील्ड इकाइयों के पात्र समूह 'ग' और समूह 'घ' कर्मचारियों का चार वर्षों के एक ब्लॉक में आपूर्ति की जा रही पॉलियस्टर सूती वर्दी के तीन सेटों के स्थान पर उनके चार सेटों की व्यवस्था की जाए, को स्वीकार करके लागू कर दिया गया है।

3.23 दिनांक 19.9.2003 को आयोजित डाक सेवा बोर्ड की 13वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में ऊनी जर्सी, ऊनी बड़े कोट का कपड़ा, पत्र पेटियों एवं फार्मों के मुद्रण हेतु कागज, वूलेन सर्ज कपड़ा (किस्म IV) आदि वर्दी की अधिप्राप्ति के लिए स्टोरों के विकेन्द्रीकरण के आदेश डाक सर्किलों को जारी कर दिए गए।

Volume'. The quantity of speed post articles has increased from 28,820 in August, 2005 to 3,48,625 in March, 2006 i.e. more than twelve times. The Pick Up of ordinary mail increased from 1,53,666 articles in August, 2005 to 27,77,395 articles in March, 2006 and sale of postage stamps & stationery has increased from Rs.0.65 Million in August, 2005 to Rs.8.98 Million in March, 2006.

Modernisation and Computerisation of Mail Operations

3.16 In order to expedite transmission, processing and delivery of mail, the Department has embarked on a policy of computerisation and modernisation of the mail processing, transmission and delivery in post offices. The modernisation of mail offices aims at providing better equipment and improved work environment in the Mail Offices.

3.17 Processing of accountable articles like Registered Letters, Insured Articles etc., has been computerised for speedy and safe handling of articles and for more expeditious response in case of enquiries.

3.18 During the year 2005-2006, 4 Mail Offices were modernised, while 18 Head Record Offices were computerized and 34 Registration Centres were also computerized.

Mail Motor Service (MMS)

3.19 The Mail Motor Service is responsible for maintenance, operations and administration of 1207 Mail Motor Vehicles and 486 staff cars/inspection vehicles of the Department. The Department operates its own fleet of mail motor vehicles at 98 stations. Full-fledged workshop facilities for major repairs and maintenance are available at 17 of these stations. During 2005-2006, the MMS Vehicles covered 26.90 Million Kms. for conveyance of mails. An expenditure of Rs. 550.92 Million was incurred on MMS at an average cost of Rs. 20.48 per Km. The Mail Motor Service has 135 CNG propelled Mail Vans in Mumbai & Delhi and has introduced Bharat Stage III vehicles in the fleet to reduce pollution level.

3.20 During the year 2005-06, the Department of Posts procured following vehicles under Plan and Non-

Plan after obtaining permission from Ministry of Finance on relaxation of ban.

Plan

Vehicles: 26 {Tata Tourin (16), Tata Sumo (1), Tata 407 (6), Tata 709 (3)}

Three-wheelers: 32 {CNG (9), Diesel (23)}

Two-wheelers: 18 TVS 100 CC 4 Stroke

Non-Plan

Vehicles: 51 {(RTV CNG (6), Tata 407 (7), Tata 410 (6), Tata 709 (1), Tata Sumo (16), Tata Tourin (6), Maruti Omni (5), Maruti Gypsy (4)}

3.21 Store inventory system of Mail Motor Service has been computerized with the induction of store module software designed by Software Development Center of Department of Posts, Hyderabad. During 2005-2006, the following Mail Motor Service has been introduced:

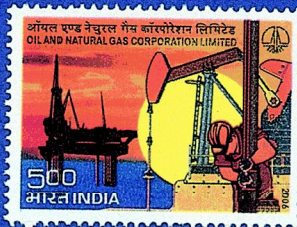
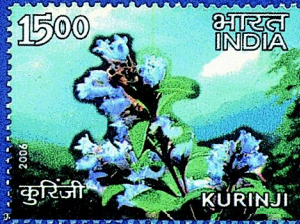
Name of the Station	Fleet Position
Dhanbad (Jharkhand)	3
Bokaro Sterel City (Jharkhand)	2
Berhampur (Orissa)	2
Lakshdweep	1

Material Management (MM)

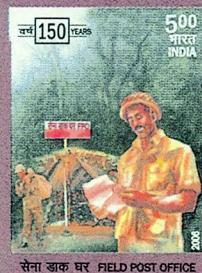
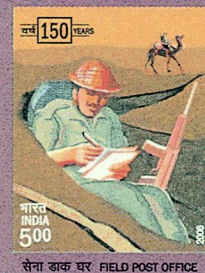
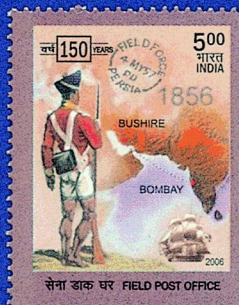
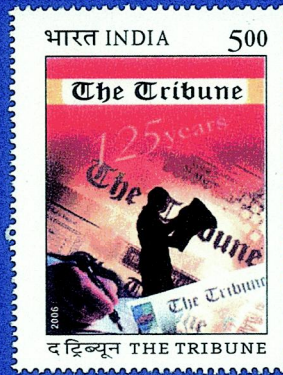
3.22 The demand of the staff side of the Department Council (JCM) that eligible Group 'C' and Group 'D' employees of the field units of the Department of Posts posted in plain stations where warm uniform is supplied, may be provided with four sets of Polyester Cotton uniform in place of three sets of Polyester Cotton uniform being supplied in a block of four years has been accepted and implemented.

3.23 In pursuance of the decision taken by the Postal Service Board in its 13th meeting held on 19.09.2003, orders for decentralization of procurement of stores and uniform e.g. Woolen Jerseys, Woolen Great Coat cloth, Letter Boxes, Paper for printing of Forms, Woolen Serge Cloth (Variety IV) were issued to the Postal Circles.

कुछ विशेष डाक टिकट



SOME THEMATIC STAMPS



अध्याय 4

फिलैटली

परिचय

4.1 भारत की फिलैटलिक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- विशेष/स्मारक डाक टिकटों की डिजाइनिंग, मुद्रण एवं वितरण।
- नियत डाक टिकटों और डाक लेखन सामग्री जैसे लिफाफे, अंतर्देशीय पत्रकार्ड, पोस्टकार्ड, हवाई पत्र एवं रजिस्टर्ड आवरण आदि मर्दों की डिजाइनिंग, मुद्रण एवं वितरण।
- फिलैटली का उन्नयन। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर फिलैटलिक प्रदर्शनियों का आयोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा राज्य/क्षेत्रीय और जिला स्तर पर प्रदर्शनियों की मानिट्रिंग करना शामिल है।
- राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय, डाक भवन की देखरेख करना।

राष्ट्र की छवि निर्माण के लिए डाक टिकटों का उपयोग

4.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारम्भ में डाक टिकटों के माध्यम को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को उजागर करने में प्रयुक्त किया गया एवं इनमें पंचवर्षीय योजनाओं, इस्पात संयंत्रों, बांधों आदि जैसे विषयों को दर्शाया गया। इसके बाद, देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर को दर्शाया जाने लगा तथा कला, स्थापत्य, समुद्री विरासत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं सिनेमा पर विषयपरक सेटों में अनेक सुन्दर डाक टिकट जारी किये गए। स्मारक डाक टिकटों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले महान नेताओं को भी सम्मानित किया गया है इनमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। चित्रकारी, साहित्य, संगीत, सामाजिक उत्थान आदि क्षेत्रों में अत्यधिक योगदान करने वाले महापुरुषों को भी स्मारक डाक टिकटों द्वारा सम्मानित किया गया है। एक प्रकार से, डाक टिकटें डाक शुल्क भुगतान के अपने मूल उद्देश्य के अलावा देश के लिए सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका भी निभा रही हैं। डाक टिकटों की 'डाक शुल्क का

भुगतान' एवं 'सांस्कृतिक राजदूत' की दोहरी भूमिका को देखते हुए दो श्रेणी की डाक टिकटें अस्तित्व में आई हैं अर्थात् 'नियत डाक टिकटें' एवं 'स्मारक डाक टिकटें'। प्रथम डाक टिकटें डाक मर्दों पर डाक शुल्क के भुगतान के रूप में दैनन्दिन प्रयोग के लिए हैं। इनमें कम डिजाइन आगत निहित हैं जिससे उनके निर्माण पर कम व्यय आता है और उन्हें बड़ी मात्रा में मुद्रित करवाया जाता है। दूसरी श्रेणी की डाक टिकटों को सौन्दर्यपरक दृष्टिकोण से डिजाइन एवं मुद्रित किया जाता है। इन्हें कम मात्रा में मुद्रित करवाया जाता है और यह डाक टिकट संग्रहकर्ताओं में अधिक रुचि जागृत करती हैं।

फिलैटली पर नीति

4.3 स्मारक डाक टिकट जारी करने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम पर सरकार को सलाह देने के लिए एक फिलैटली सलाहकार समिति (पीएसी) का गठन किया गया है। विभाग संसद एवं राज्य विधान सभा के सदस्यों, राज्य सरकारों एवं अन्य संगठनों/संस्थानों और व्यक्तियों से डाक टिकट जारी करने के संबंध में प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में प्रस्ताव प्राप्त करता है। डाक टिकटों के जारी किये जाने के समय उनका फिलैटलिक मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समिति कुछ दिशा-निर्देशों के आधार पर इन प्रस्तावों की जांच करती है तथा प्रतिभूति मुद्रणालयों की एवं विक्रय क्षमता के दृष्टिगत वार्षिक डाक टिकट जारी किये जाने संबंधी कार्यक्रम की अनुशंसा करती है। फिलैटली सलाहकार समिति फिलैटली एवं इसके उन्नयन संबंधी नीतिगत मुद्दों की भी जांच करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। समिति में डाक विभाग एवं आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से सरकारी सदस्य एवं नामांकन द्वारा गैर सरकारी सदस्य शामिल किये जाते हैं। गैर सरकारी सदस्यों को संसद सदस्यों एवं प्रसिद्ध फिलैटलीविदों एवं जीवन के विविध क्षेत्रों जैसे कला, संग्रहालय विद्या, पुरातत्व विज्ञान, डिजाइन, फोटोग्राफी एवं शिक्षा के क्षेत्र से प्रख्यात लोगों में से चुना जाता है। वर्ष 2006 के लिए जारी होने वाले डाक टिकटों की सिफारिश हेतु फिलैटली सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में 17.05.2005 को आयोजित की गई।

Chapter 4

PHILATELY

Introduction

4.1 The philatelic activities of the Department include:-

- Designing, printing and distribution of special/commemorative postage stamps.
- Designing, printing and distribution of definitive postage stamps and items of postal stationery like Envelope, Inland Letter Card, Postcard, Aerogram and Registered Cover etc.
- Promotion of Philately and conduct of Philatelic Exhibitions at the national level and participation in international and world exhibitions, as well as monitoring of exhibitions at State/Regional and District levels.
- Maintenance of the National Philatelic Museum, Dak Bhavan.

The Postage Stamp as image products of the country

4.2 After independence, the medium of postage stamps was initially used to highlight the country's achievements in science and technology as well as its socio-economic development by depicting themes like the Five-Year Plans, Steel Plants, Dams, etc. Subsequently, the focus shifted to the country's rich cultural and natural heritage. Many beautiful stamps were issued in thematic sets on art, architecture, maritime heritage, science, technology, defence and cinema. Great leaders of national and international standing were honoured with commemorative stamps, the most prominent being Mahatma Gandhi, the Father of the Nation. Personalities, who have made immense contributions in areas like painting, literature, music, social upliftment etc., were also honoured with commemorative stamps. The role of "cultural ambassadors" was thus assigned to postage stamps, apart from their original

purpose of being receipts of postage. In keeping with the dual character of "receipts of postage" and "cultural ambassadors", two categories of stamps have emerged, viz. the "Definitive Postage Stamps" and the "Commemorative Postage Stamps". The former is meant for day-to-day use at post offices and on mail articles. The Definitive Postage Stamps are having less design inputs, entail minimum expenditure in their manufacturing and are printed in large quantities. The latter, on the other hand, are designed and printed with greater aesthetic inputs. These are manufactured in smaller limited quantities and generate more interest among stamp collectors.

Policy on Philately

4.3 A Philatelic Advisory Committee (PAC) has been constituted to advise the Government on the annual programme for issue of Commemorative Stamps. Every year, the Department receives a large number of proposals for issue of stamps from Members of Parliament and State Legislative Assemblies, State Governments and other Govt. organizations, private organizations/institutions and individuals. The Committee examines these proposals on the basis of certain guidelines meant to ensure the philatelic value of the stamps when issued and recommends the annual stamp issue programme taking into account also the capacity of the security printing presses. The PAC also examines policy issues related to philately and its promotion and submits its recommendations. The Committee comprises official members from the Departments of Posts and Economic Affairs as well as non-official members by nomination. The non-official members are drawn from among the Members of Parliament, noted philatelists, and eminent personalities from various walks of life like art, museology, archaeology, design, photography and academics. The meeting of the Philatelic Advisory Committee (PAC) to recommend on the stamps issues for 2006 was held on 17.05.2005 at New Delhi.

फिलैटली का उन्नयन

4.4 राजस्व अर्जित करने हेतु फिलैटली की बहुत संभावनाएँ हैं तथा फिलैटली के उन्नयन एवं विकास हेतु निम्नलिखित विभिन्न उपाय किए गए हैं।

- समूचे देश में जिला स्तर तक की डाक-टिकट प्रदर्शनियों का आयोजन।
- देशभर में फिलैटली संगोष्ठियां, फिलैटली उत्सव और फिलैटली कार्यशालाएं आयोजित करना।
- फिलैटलिक ब्यूरो, जो ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने के स्थान है, का प्रौद्योगिकीय एवं सौन्दर्यपरक उन्नयन।
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फिलैटली के प्रचार-प्रसार के लिए प्रशिक्षण देना।
- फिलैटली के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार।
- बाल दिवस यानी 14 नवम्बर को विद्यालय के छात्रों के मध्य वार्षिक डाक टिकट डिजाइन प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। श्रेष्ठतम प्रविष्टि को पुरस्कार दिया जाता है और अगले वर्ष जारी की जाने वाली बाल दिवस डाक टिकट के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

फिलैटली विक्रय एवं सेवाएं

4.5 पूरे देश में फिलैटलिक मर्चों का विक्रय 69 फिलैटलिक ब्यूरो तथा करीब 1,103 फिलैटलिक काउन्टरों के माध्यम से किया जाता है जिसमें देश के प्रधान डाकघर और मुख्य डाकघर सम्मिलित हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान अर्जित फिलैटलिक राजस्व 230 मिलियन रुपये था। फिलैटली के उन्नयन के लिए सम्मिलित प्रयत्नों के फलस्वरूप इस रुचि को देश के विभिन्न भागों में लोकप्रिय बनाने में सहायता मिली है तथा विभाग में पंजीकृत ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। अतः फिलैटलिक जमा खाता धारकों की संख्या जो वर्ष 1999-2000 में 23905

थी, वर्ष 2005-06 तक बढ़कर 1,37,857 हो गई थी जबकि देश में डाक टिकट संग्रहण करने वालों की कुल संख्या विभाग द्वारा हाल में कमीशन किए गए एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार करीब 40 लाख अनुमानित की गई है।

फिलैटलिक गतिविधियां

4.6 वर्ष 2005-06 के दौरान 46 स्मारक डाक टिकट/विशेष डाक टिकट जारी किए गए हैं। कुछ जारी किए गए विशेष तथा लोकप्रिय डाक टिकटों में दांडी मार्च पर जारी 4 डाक टिकटों का सेट (लघु शीट के साथ), बांडुंग सम्मेलन, विश्व पर्यावरण दिवस (हरित नगर), भारतीय स्टेट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, पत्र पेटियों (लघु शीट के साथ चार डाक टिकटों का एक सेट), सूचना समाज पर विश्व सम्मेलन, कोलकाता पुलिस कमिश्नरी, भारत में नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य, एम. एस. सुबुलक्ष्मी, राष्ट्रपति द्वारा बेड़ा पुनरीक्षण (चार डाक टिकटों का सेट), विश्व उपभोक्ता अधिकार, दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान हैं।

नए उत्पाद

4.7 एक 220 x 110 उभरा हुआ लिफाफा (ए -4 माप के पेपर के लिए) 18.7.2005 को शुरु किया गया तथा 18.10.2005 को इसका रंग/डिजाइन वाला एक प्रकार शुरु किया गया। एक डाक टिकट थैली जिसमें पोस्टमैन द्वारा बेचे जाने वाले 100/200 रु. तक के डाक टिकट हों, 18.7.2005 को शुरु की गई।

फिलैटलिक प्रदर्शनियाँ

4.8 अप्रैल 2005 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न स्थानों में 17 डाक टिकट प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। राष्ट्रीय फिलैटलिक संग्रहालय के प्रदर्श इन सभी प्रदर्शनियों में आमंत्रण वर्ग में प्रदर्शित किए गए थे। भारतीय डाक ने ताइपेई में 19-24 अगस्त, 2005 तक आयोजित 'ताइपेई 2005' में भाग लिया।

Philately Promotion

4.4 Philately has potential for revenue generation and the following various measures have been taken up to promote and develop philately.

- Holding of Stamp Exhibitions across the country right down to the district level.
- Holding of Philatelic Seminars, Philatelic Festivals, Philatelic Workshops throughout the country.
- Technological and aesthetic up-gradation of the Philatelic Bureaux, which are the points of customer interface.
- Training of officers and personnel in philately promotion.
- Publicity to generate awareness.
- An Annual Stamp Design Competition is held among school children on 14th November i.e. on Children's Day every year. The best entries are awarded prizes and their designs feature in the Children's Day stamp and ancillaries brought out next year on the same day.

Philatelic sales and services

4.5 Sale of philatelic items is carried out all over the country through 69 Philatelic Bureaux and around 1,103 Philatelic Counters including all the Head Post Offices and Mukhya Dak Ghars of the country. Philatelic revenue earned during the year 2005-06 was Rs. 230 Million. Concerted efforts for promotion of Philately have helped popularize the hobby in different parts of the country, and there has been a tremendous growth in the number of customers registered with the Department. Thus, the number of Philatelic Deposit Account Holders

which stood at 23,905 in 1999-2000 has increased to 1,37,857 by 2005-06, while the total number of stamp collectors in the country is estimated to be four million as per an independent study commissioned by the Department recently.

Philatelic Activities

4.6 During the year 2005-06, forty six (46) commemorative /special postage stamps have been released. Among the more significant and popular stamps issued were the set of four stamps on Dandi March (with miniature sheet), Bandung Conference, World Environment Day (Green Cities), State Bank of India, International Day of Peace, Letter boxes (a set of four stamps with miniature sheet), World Summit on the Information Society, Kolkata Police Commissionerate, Newborn Health in India, M.S. Subbulakshmi, President's Fleet Review (a set of four stamps), World Consumer Rights Day and Indian Agricultural Research Institute.

New products

4.7 A new 220x110 embossed envelope (for A-4 size paper) was launched on 18.7.2005 and with a colour/design variant on 18.10.2005. A Stamp Pouch containing stamps amounting to Rs. 100/200 to be sold through Postmen, was launched on 18.7.2005.

Philatelic Exhibitions

4.8 17 stamp exhibitions were held in various places around the country during the period April 2005 to March 2006. Exhibits from the National Philatelic Museum were displayed in the invitee class in all these exhibitions. India Post participated in the 'Taipei 2005' International Philatelic Exhibition held at Taipei from 19-24 August 2005.

अध्याय 5

व्यवसाय विकास कार्यकलाप

5.1 विभाग के मूल्यवर्धित प्रीमियम उत्पादों के डिज़ाइन, निगरानी, विकास एवं विपणन के लिए 1996 में व्यवसाय विकास निदेशालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 2004-05 में व्यवसाय विकास निदेशालय को व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय में पुनर्गठित किया गया। निदेशालय में अब एक पार्सल एवं लॉजिस्टिक डिवीजन, एक विपणन डिवीजन और एक प्रचालन डिवीजन है। सभी सर्किलों में विपणन एवं पार्सल डिवीजन भी सृजित किये गए हैं। मेट्रो सर्किलों में विपणन का दायित्व एसएजी स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय का मुख्य दायित्व मूल्यवर्धित सेवाओं में कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- वर्तमान मूल्यवर्धित एवं परंपरागत डाक एवं पार्सल उत्पादों और सेवाओं का प्रशासन, विस्तार एवं उन्नयन;
- वित्तीय एवं बीमा उत्पादों एवं सेवाओं को छोड़कर नवीन मूल्यवर्धित उत्पादों एवं सेवाओं की नियोजना एवं प्रस्तावना;
- उनकी रिटेलिंग एवं नेटवर्किंग के लिए प्रक्रिया, विनियमन एवं दिशा-निर्देश;

- बाजार अध्ययन, बाजार परीक्षण एवं उत्पाद सुधार;
- बाजार नीतियाँ, गठजोड़ एवं सहयोग;
- मूल्य वर्धित उत्पादों एवं सेवाओं की वृद्धि की समीक्षा एवं निगरानी;
- विभाग के निष्क्रिय संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की संभावना की खोज।

उत्पाद

5.2 व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, व्यवसाय डाक-कुल डाक समाधान, सीधी डाक, एक्सप्रेस पार्सल डाक, मीडिया डाक, लॉजिस्टिक पोस्ट, ई-बिल पोस्ट, ई-पोस्ट, रिटेल पोस्ट एवं बिल मेल सेवा के प्रबंधन एवं विपणन के लिए जिम्मेदार है।

व्यवसाय वृद्धि

5.3 वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान प्रीमियम उत्पादों से अर्जित राजस्व 12021.04 मिलियन रुपये था। उत्पाद-वार राजस्व सारणी-3 में परिलक्षित किया गया है:-

तालिका-3 व्यवसाय विकास गतिविधियों की उत्पादवार राजस्व वृद्धि (मिलियन रुपये में)			
उत्पाद	वर्ष 2004-05 में राजस्व	वर्ष 2005-06 में राजस्व	प्रतिशत वृद्धि
स्पीड पोस्ट	3,541.60	4,084.20	15.32
व्यवसाय पोस्ट	4,730.60	6,100.50	28.96
मीडिया पोस्ट	63.60	280.68	341.32
एक्सप्रेस पोस्ट	377.00	457.63	21.39
रिटेल पोस्ट	505.00	651.07	28.92
बधाई डाक	4.20	2.19	(-) 47.86
*अन्य व्यवसाय सेवाएँ	311.40	444.77	42.83
कुल	9,533.40	12,021.04	26.09

* अन्य में शामिल हैं: ई-पोस्ट, ई-बिल पोस्ट, बिल मेल सेवा, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा आदि।

Chapter 5

BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES

5.1 Business Development Directorate was set up in 1996 to design, monitor, develop and market value-added premium products of the Department. The Business Development Directorate was reorganized into Business Development and Marketing Directorate in the year 2004-05. The Directorate now has a Parcel and Logistics Division, a Marketing Division and Operations Division. Marketing and Parcel Divisions have also been created in all the Circles. In the Metro Circles, the work of marketing is being handled by SAG level officers. The main responsibility of the Business Development and Marketing Directorate is to ensure focused management of value added services and it includes the following: -

- Administration, expansion and promotion of the existing value-added and traditional mail and parcel products and services;
- Planning and introduction of new value-added products and services, except financial and insurance products and services;
- Procedures, regulations and guidelines for their retailing and networking;

- Market study, market testing and product improvement;
- Market strategies, alliances and cooperation;
- Monitoring and review of growth of value-added products and services;
- Exploring the scope of commercial utilization of idle resources of the Department.

Products

5.2 The Business Development and Marketing Directorate manages and markets Speed Post, Speed Post Passport Service, Business Post – Total Mailing Solutions, Direct Post, Express Parcel Post, Media Post, Logistics Post, e-Bill Post, e-Post, Retail Post and Bill Mail Service.

Business Growth

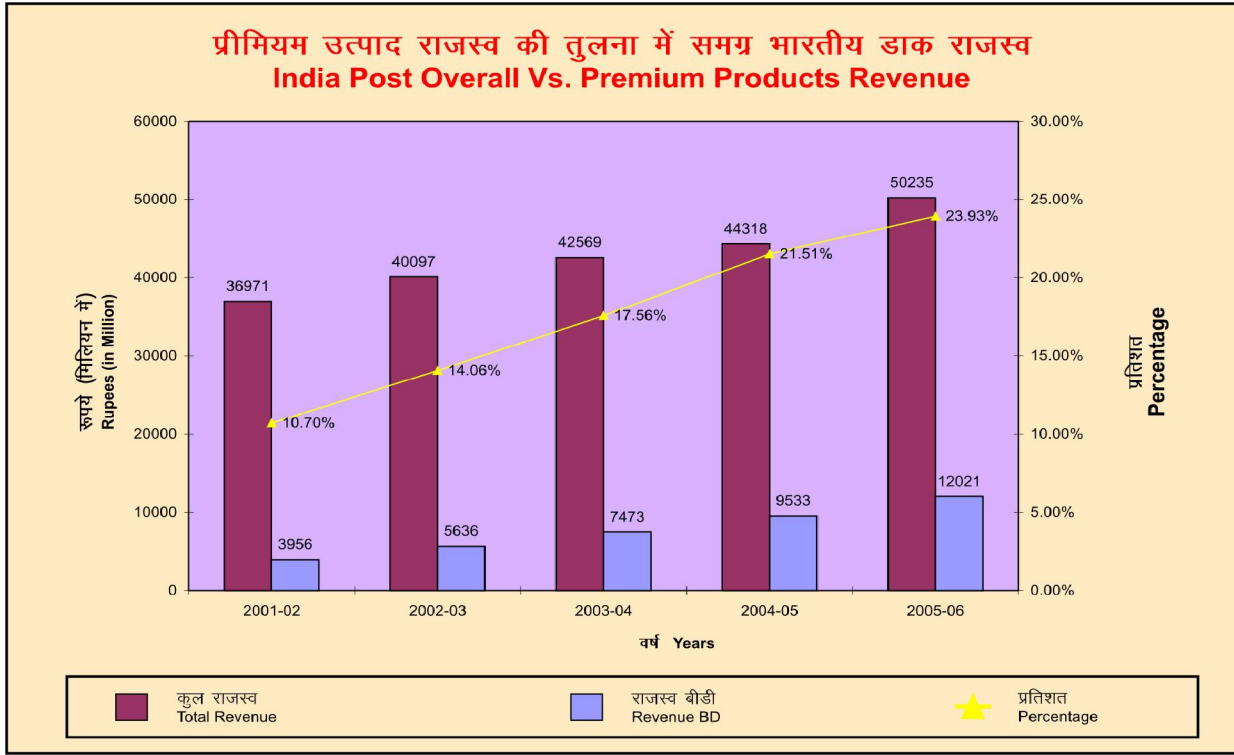
5.3 During the financial year 2005-06, the revenue realized from premium products was Rs. 12021.04 Million. The Product-wise revenue is reflected in Table-3.

Product	Revenue in 2004-05	Revenue in 2005-06	% age increase
Speed Post	3,541.60	4,084.20	15.32
Business Post	4,730.60	6,100.50	28.96
Media Post	63.60	280.68	341.32
Express Post	377.00	457.63	21.39
Retail Post	505.00	651.07	28.92
Greeting Post	4.20	2.19	(-47.86
*Other Business Services	311.40	444.77	42.83
Total	9,533.40	12,021.04	26.09

*Others include: e-Post, e-Bill Post, Bill Mail Service, Speed Post Passport Service, etc.

विभाग के समग्र राजस्व में प्रीमियम उत्पादों से राजस्व का अंश वर्ष 2005-06 में 23.93% से अधिक था। पिछले कुछ वर्षों में

यह निरंतर बढ़ रहा है जैसा कि नीचे चित्र से स्पष्ट है:-



स्पीड पोस्ट

5.4 तीव्र एवं समयबद्ध वितरण सेवाएँ प्रदान करने के दृष्टिगत, सात मेट्रो शहरों को जोड़ते हुए वर्ष 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरु की गई। आज स्पीड पोस्ट के राष्ट्रीय नेटवर्क में, भारत के 168 बड़े शहरों/कस्बों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में 97 देशों को जोड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, 951 कस्बे और जिला मुख्यालय राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों के नेटवर्क की मार्फत जुड़े हैं जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों हेतु स्पीड पोस्ट मर्दे भी बुक की जा सकती हैं।

5.5 स्पीड पोस्ट देश एवं विश्व भर में ग्राहकों को पत्रों, कागजात एवं पार्सल के रूप में, प्रत्येक 35 किग्रा. तक, समयबद्ध एवं आश्वस्त वितरण सेवा प्रदान करती है। स्टेशनों को जोड़ने के लिए उपलब्ध तीव्रतर परिवहन वाहन के दृष्टिगत वितरण मानक निर्धारित किये जाते हैं। इसके प्रचालन एवं प्रबंध में, वाणिज्यिक रवैये के तौर पर, व्यवसाय सेवा के रूप में इसकी व्यवस्था की जाती है।

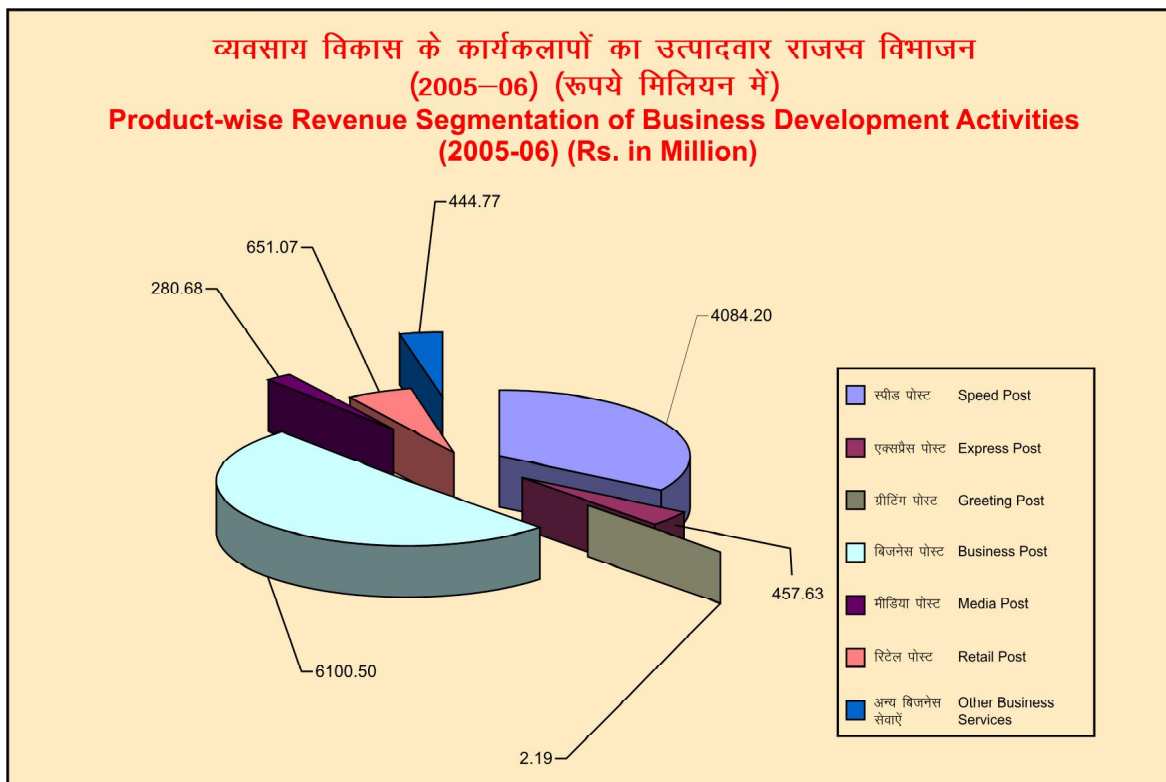
5.6 स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत स्पीड पोस्ट घरेलू सेवा, स्पीड पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय सेवा, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, स्पीड पोस्ट धनादेश एवं स्पीड पोस्ट उपहार सेवा दी जाती हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान, स्पीड पोस्ट से राजस्व अर्जन 4084.20 मिलियन रुपये रहा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्शाता है। स्पीड पोस्ट में ग्राहक सेवा एवं वितरण दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्पीड पोस्ट में सर्वाधिक राजस्व दिल्ली सर्किल द्वारा अर्जित किया गया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, वर्ष 2005-06 तक 855 स्पीड पोस्ट केन्द्रों में कम्प्यूटर लगाये गए हैं।

ऑनलाइन ट्रैक एवं ट्रेस का क्रियान्वयन

5.7 स्पीड पोस्ट एवं एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट हेतु इंटरनेट आधारित ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया है जिसमें ग्राहक विभाग की वेबसाइट www.indiapost.gov.in को खोलकर अपने सामान की स्थिति का ऑनलाइन पता कर

The share of revenue from Premium Products in the overall revenue of the Department was over 23.93 % in

2005-06. It has been growing over the years, as shown in the graphic.



Speed Post

5.4 Speed Post Services were introduced in 1986, linking 7 Metro Cities, with a view to provide fast and time-bound delivery services. As on date, Speed Post has a network linking 168 major cities/towns in India in the national network and 97 countries in the international network. In addition, 951 town and district headquarters are linked on the State Speed Post network, from where Speed Post articles can be booked for national and international destinations.

5.5 Speed Post offers the customer, time-specific and assured delivery service of letters, documents and parcels up to 35 Kgs. each across the country and around the world. Delivery norms are fixed taking into account the fastest transport available to link the stations. It is managed as a business service with commercial approach in its operations and management.

5.6 Under the brand Speed Post, Speed Post Domestic Services, Speed Post International Services, Speed Post Passport Service, Speed Post Money Order and Speed Post Gift Service are offered. During 2005-06, revenue generation from Speed Post has been Rs. 4084.20 Million, representing a growth rate of about 15.32% over the previous year. Customer service and delivery efficiency is the main focus in Speed Post. The highest revenue in Speed Post was generated by Delhi Circle. Under the Tenth Plan, 855 Speed Post Offices have been provided with computers till 2005-06.

Implementation of Online Track & Trace

5.7 Internet based Track and Trace System has been implemented for Speed Post and Express Parcel Post wherein a customer can find out the status of his consignment online through the Internet by logging on to the Department's website www.indiapost.gov.in. It has

सकता है। यह सुविधा राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों एवं चुनिंदा राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों में प्रारंभ की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सभी स्पीड पोस्ट मदों के लिए ट्रेक एवं ट्रेस सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सभी राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों को वैब सर्वर से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2005-06 तक ट्रेक एवं ट्रेस सुविधा हेतु 415 स्पीड पोस्ट केन्द्रों को कम्प्यूटर प्रदान किये गए हैं।

स्पीड पोस्ट के अंतर्गत मूल्यवर्धन

5.8 विभाग ने कारपोरेट ग्राहकों से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए नियमित आधार पर स्पीड पोस्ट के उपयोग के माध्यम से ग्राहकों के लिए निशुल्क पिक-अप सेवा, मात्रा आधारित छूट और क्रेडिट सुविधा प्रदान की है। उद्योग में वृद्धि के साथ कदम-ताल मिलाने के लिए, मूल्यवर्धन एवं सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने संबंधी अनेक कदम उठाए हैं। कारपोरेट ग्राहकों के लिए प्रदान की गई कुछ मूल्यवर्धित सेवाएँ निम्नवत हैं :-

- बुक अभी करें भुगतान बाद में (बीएनपीएल) सेवा;
- निःशुल्क पिक-अप;
- नोडल वितरण केन्द्र;
- स्पीड पोस्ट एकत्रीकरण केन्द्रों (एसपीपीसी) से बड़ी मात्रा में प्राप्त मदों का सीधे वितरण;
- मात्रा आधारित छूट दरें;
- देश में कहीं भी वितरण हेतु संविदात्मक सेवा।

स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा

5.9 डाक विभाग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से 5 मार्च, 2001 को स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा प्रारम्भ की है। स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में स्थित स्पीड पोस्ट केन्द्रों में पासपोर्ट आवेदन प्रपत्रों की प्राप्ति का विकेन्द्रीकरण करना है। स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा के अंतर्गत, विदेश मंत्रालय की तरफ से, चुनिंदा स्पीड पोस्ट केन्द्रों पर पासपोर्ट आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं। इस सेवा के दो मूल अंग हैं यानी

- (क) चुनिंदा स्पीड पोस्ट केन्द्रों पर लिफाफों के साथ-साथ पासपोर्ट आवेदन पत्रों की बिक्री;

- (ख) भरे हुए पासपोर्ट आवेदन पत्रों को स्वीकार करना एवं आगे कार्रवाई हेतु उन्हें पासपोर्ट कार्यालयों को प्रेषित करना।

इस सेवा के अंतर्गत, स्पीड पोस्ट केन्द्र पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा करने वाले कार्यालयों के रूप में कार्य करते हैं अर्थात् ग्राहकों को सुविधा प्रदान करते हैं। कुल 213 डाकघरों/स्पीड पोस्ट केन्द्रों के साथ यह सेवा अब देश भर में उपलब्ध है और सेना डाक सेवा के अंतर्गत इसका डाकघरों तक भी विस्तार किया गया है।

व्यवसाय डाक

5.10 व्यवसाय डाक बड़ी मात्रा में ग्राहकों के लिए ग्राहकोनुकूल सेवाएँ प्रदान करके कुल व्यवसाय समाधान प्रदान करती है। बड़ी मात्रा में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख शहरों में व्यवसाय डाक केन्द्र या वृहद मेलिंग केन्द्र स्थापित किये गए। इस सेवा के अंतर्गत, डाक द्वारा प्रस्तावित सभी प्रकार की पारंपरिक सेवाओं के साथ एकत्रण, इनसर्शन, पता लेखन, सीलिंग, फ्रैंकिंग इत्यादि के रूप में मूल्यवर्धन प्रदान किया जाता है। इस वर्ष मूल्यवर्धन एवं पूर्व मेलिंग गतिविधि के रूप में मुद्रण डाक सेवा को भी सूची में शामिल कर लिया गया। अधिकाधिक कारपोरेट ग्राहक व्यवसाय पोस्ट सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और मैट्रो शहरों एवं कस्बों में व्यवसाय मेल का बढ़ना निरंतर जारी है। वर्ष 2005-06 में व्यवसाय डाक द्वारा अर्जित राजस्व 6,100.50 मिलियन रुपये है जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.96 प्रतिशत से भी अधिक है। व्यवसाय डाक से अर्जित राजस्व स्पीड पोस्ट से अर्जित राजस्व से भी अधिक हो गया है।

सीधी डाक

5.11 अनेक देशों ने सीधे डाक विपणन की अत्यधिक वृद्धि की संभावना वाले व्यवसाय मेल के एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में पहचान की है। उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ सीधी डाक के भारत में भी तीव्रता से बढ़ने की आशा है। बिना पता लिखी डाक के लक्षित जनता के दरवाजे पर वितरण के प्रयोजन से जून, 2005 में सीधी डाक नामक सेवा प्रारम्भ की गई। जुलाई, 2005 से मार्च, 2006 तक का राजस्व अर्जन 8.53 मिलियन रु. था।

been operationalized in the National Speed Post Centres and in selected State Speed Post Centres. In the Tenth Five Year Plan, it is proposed to link all the State Speed Post Centres with the web-server for providing on-line track and trace service for all speed post articles. 415 Speed Post Centres have been provided computers for track and trace till 2005-06.

Value Additions under Speed Post

5.8 In order to increase revenue from corporate customers, free pick up service, volume based discount and credit facility is provided to Corporate Customers using Speed Post on a regular basis. In order to keep pace with growth in the industry, the Department has taken a number of steps to provide better quality of services to the customers. Some of the value added services provided to Corporate Customers are as follows :-

- Book Now Pay Later (BNPL) facility;
- Free pick-up;
- Nodal Delivery Centres;
- Direct delivery of articles received in bulk from Speed Post Concentration Centre (SPCC);
- Volume based discounted rates;
- Contractual Service for delivery anywhere in the country.

Speed Post Passport Service

5.9 The Department of Posts, in partnership with Ministry of External Affairs, launched Speed Post Passport Service on 5th March 2001. The primary objective of Speed Post Passport Service is to decentralize the acceptance of passport application forms to Speed Post Centres across the country. Under the Speed Post Passport Service, Passport Application Forms are accepted at selected Speed Post Centres, on behalf of the Ministry of External Affairs. This service has two basic components:

- (a) Sale of Passport Application Forms along with envelopes at selected Speed Post Centres; and
- (b) Acceptance of filled-up Passport Application Forms and dispatch to Passport Offices, for further processing.

Under this service, Speed Post Centres function as Passport Application Acceptance Offices thus providing convenience to the customers. The Service is available now across the country with total outlets of 213 Post Offices/Speed Post Centres. The service has further been extended to the Post Offices under the Army Postal Services.

Business Post

5.10 The Business Post offers total business solutions for the bulk users by providing customised services. Business Post Centres or Mass Mailing Centres were established in major cities to cater to the needs of Bulk Mailers. The service provides value addition to all traditional services offered by the Post in the form of collection, insertion, addressing, sealing, franking, etc. This year, Print Mail Service as a value addition and a pre-mailing activity, was also added to the list. More and more corporate customers have been using Business Post Services and Business Mail continues to grow in the Metro Cities and Towns. In the year 2005-06, the revenue generated through Business Post is Rs. 6,100.50 Million, which is about 28.96% more than the previous year. The revenue from Business Post has surpassed the revenue generated from Speed Post also.

Direct Post

5.11 Many countries have identified Direct Marketing Mail as an important component of business mail with high potential for growth. With high economic growth, Direct Mail volumes are expected to grow significantly in India also. A service called 'Direct Post' was introduced in June, 2005 to deal with the delivery of unaddressed mail to the door-steps of the target population. The revenue generation from July, 2005 to March, 2006 was Rs. 8.53 Million.

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट

5.12 एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट के माध्यम से भूतल परिवहन द्वारा पार्सलों का एक्सप्रेस वितरण किया जाता है। वाणिज्यिक हित को देखते हुए उत्पाद को मार्च, 1999 में पुनः प्रारम्भ किया गया। इसमें 35 किग्रा. तक वजन वाले पार्सलों की बुकिंग एवं प्रेषण किया जा सकता है। इस सेवा को कारपोरेट ग्राहकों को संविदात्मक आधार पर उपलब्ध करवाया गया है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की दरें अक्टूबर, 2004 में संशोधित की गई थीं। वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व बढ़कर 457.63 मिलियन रुपये हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 21.39 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि परिलक्षित करता है। सर्वाधिक राजस्व महाराष्ट्र सर्किल द्वारा अर्जित किया गया।

मीडिया पोस्ट

5.13 मीडिया पोस्ट के द्वारा कारपोरेट ग्राहकों/सरकारी संगठनों एवं अन्य बड़े निजी संस्थानों को अपने उत्पाद/सेवाओं को डाक स्टेशनरी, पत्र पेटिकाओं आदि पर विज्ञापित करवाने का अवसर दिया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान मीडिया पोस्ट से अर्जित राजस्व 280.68 मिलियन रुपये रहा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 341.32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

लॉजिस्टिक पोस्ट

5.14 'लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा' नामक एक नई सेवा वर्ष 2004-05 में प्रारम्भ की गई। डाक विभाग के लिए इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक सेवा एवं व्यावसायिक अवसरों के बाजार अंश के मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन किये जाने के बाद इस सेवा को प्रारम्भ किया गया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि लॉजिस्टिक सेवा का बाजार अंश 600,000 से 700,000 मिलियन रुपये प्रतिवर्ष के मध्य था और डाक विभाग भारत में बढ़ते वाणिज्य के लिए एक विश्वसनीय सेवा उपलब्ध करवा सकता है और साथ ही इससे अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त कर सकता है। निवल राजस्व 1.01 मिलियन रुपये था।

ई-बिल पोस्ट

5.15 यह एक नई सेवा है जिसे विभाग ने ग्राहकों के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता सेवाओं के एक अंश के रूप में प्रारम्भ किया है।

यह सेवा, फिलहाल, बंगलौर एवं कोलकाता में उपलब्ध है और अन्य शहरों में इसके शीघ्र प्रारम्भ हो जाने की संभावना है। ग्राहकों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत इसे डिजाइन किया गया है। यह सेवा प्रयोक्ताओं द्वारा डाकघर काउंटर पर बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, पानी एवं अन्य प्रकार के बिलों/देयताओं के भुगतान करने के लिए उपयोगी है। प्रयोक्ता समीपस्थ डाकघर में जा सकता है और अपने उपयोगिता बिलों का भुगतान कर सकता है। विभाग भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) एवं अन्य ऑन लाइन व्यापारिक संगठनों के साथ परामर्श करके देश में ई-कॉमर्स के विकास हेतु इस सॉफ्टवेयर को उपयोग में लाने का विचार रखता है।

ई-पोस्ट

5.16 डिजिटल अंतराल को भरने के लिए डाक विभाग द्वारा 30 जनवरी, 2004 को इस ई-क्षम सेवा को देश भर में प्रारम्भ किया गया। ई-पोस्ट में ई-मेल के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं जिन्हें प्रेषितियों के पत्तों के समीपस्थ डाकघरों में मुद्रित करके पत्रों के रूप में प्रेषितियों के पत्तों पर भेजा जाता है। इसी प्रकार से, लिखित में संदेश डाकघर में लाए जा सकते हैं जिनकी जांच की जाती है और उन्हें विश्व में किसी भी ई-मेल आईडी को या भारत में किसी भी पते पर ई-मेल के रूप में भेजा जा सकता है। डाकघर की पहुंच हर कहीं करने के दृष्टिगत इस सेवा को प्रारम्भ किया गया था। विभाग ने इसे सेवा का ऑन लाइन उपयोग करने के लिए पूर्व प्रदत्त (प्रीपेड) कार्ड जारी किये हैं। ई-पोस्ट सेवा के अंतर्गत प्रति प्रेषिति ए-4 आकार के संदेश के लिए 10 रुपये प्रति संदेश वसूल किये जाते हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान इस सेवा से राजस्व के रूप में 6.26 मिलियन रुपये अर्जित किये गए। कारपोरेट जगत ने बिल, स्टेटमेंट, नोटिस आदि जारी करने के लिए ई-पोस्ट को एक तीव्र एवं मितव्ययी सेवा के रूप में पाया है। कार्पोरेट ई-पोस्ट सेवा को 18 अक्टूबर, 2005 को प्रारम्भ किया गया।

रिटेल पोस्ट

5.17 भारतीय डाक, सरकारी एवं निजी संगठनों के लिए, रिटेल पोस्ट की मार्फत, देशभर में फैले अपने 1,50,000 से अधिक डाकघरों के व्यापक नेटवर्क के द्वारा, टेलीफोन/बिजली/मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं आदि जैसे सेवा उद्योगों के लिए ग्राहक बिल

Express Parcel Post

5.12 Express Parcel Post provides express delivery of parcels through surface transportation. The product was re-launched in March 1999 with a commercial focus. It provides booking and dispatch of parcels weighing up to 35 Kgs. The service is provided to Corporate Customers on contractual basis. The rates of Express Parcel Post were revised in October 2004. During 2005-06, the revenue touched the figure of Rs. 457.63 Million, showing an increase of 21.39% over the previous year. The maximum revenue was generated by Maharashtra Circle.

Media Post

5.13 Media Post provides opportunities to corporate customers/government organizations and other large private institutions to have their products/services advertised on the postal stationery, postal vans, letter boxes, etc. During 2005-06, revenue from Media Post has been Rs. 280.68 Million, showing an increase of 341.32% over the previous year.

Logistics Post

5.14 A new service called “**Logistics Post Service**” was introduced in 2004-05. This service was introduced after a study was commissioned by Department of Posts to evaluate the market size of Logistics Service and business possibilities for the Department of Posts in this area. The study concluded that the market size of Logistics Service was between Rs. 600,000 to 700,000 Million per annum; and the Department of Posts could get into the Logistic Business which would not only provide a reliable service to growing commerce in India, but would also have the potential to earn additional revenue for the Department. The net revenue was Rs. 1.01 Million.

e-Bill Post

5.15 This is a new service, which has been launched by the Department as one of the technology-enabled services for customers. Presently, this service is available

at Bangalore and Kolkata and is likely to start in other cities very soon. This has been designed keeping in view the requirement of the clients. The service is useful for payment of electricity, telephone, mobile, water and other kinds of bills/dues at the Post Office Counter by the users. The user can go to a nearby Post Office and pay their utility bills. After interaction with the Confederation of Indian Industries (CII) and various online trading associations, the Department plans to utilize this software for the development of e-Commerce in the country.

e-Post

5.16 This is another e-enabled service launched by Department of Posts on 30th January, 2004 nation wide. The e-Post allows sending of messages through e-mail to be printed in Post Offices nearest to the addressees and to be delivered to them at their postal addresses as letters. Similarly, written messages can be brought to a Post Office, which after scanning can be sent as an e-mail to any e-mail ID in the world or to a postal address in India. This service has been introduced keeping in view the last mile advantage of the Post Office. The Department has issued pre-paid cards to use this Service online. This service would be very advantageous for those in the cities or even NRIs who have their kith and kin in some of the remote parts of India. The charges for e-post services are Rs. 10/- per e-mail message of A-4 size per addressee. Rs. 6.26 Million were generated as revenue during the year 2005-06. The Corporate world has increasingly been attracted to e-post as a quick and inexpensive means of issuing bills, statements, notices, etc. Corporate e-Post was launched on 18th October, 2005.

Retail Post

5.17 Through its vast network of more than 1,50,000 Post Offices across the country, India Post offers the facility to collect consumers' bills for service industries like telephone/electricity/mobile phone users, etc. for Govt. and private organizations through Retail Post. Post Offices also sell forms for public bodies over the counter of Post Offices. Besides this, Cellular companies also

वसूलने की सुविधा प्रदान करता है। डाकघर अपने काउंटरों पर सार्वजनिक निकायों के प्रपत्र भी बेचते हैं। इसके अलावा, सैलुलर कंपनियाँ भी कैश कार्ड एवं रिचार्ज कूपन आदि बेचने के लिए डाकघर केन्द्रों का उपयोग करती हैं। इस उत्पाद में वर्ष 2005-06 के दौरान 28.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सर्वाधिक राजस्व महाराष्ट्र सर्किल द्वारा अर्जित किया गया।

बिल मेल सेवा

5.18 इस सेवा को वित्तीय विवरण, बिल, मासिक खाता बिल या इसी प्रकार की अन्य मदों, जिन्हें सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों को प्रेषित किया जाना है, के रूप में संचार की बुकिंग के लिए, 15 सितंबर, 2003 को, देश भर में प्रारम्भ किया गया। यह सेवा मदों के स्थानीय या जिले के भीतर, नियमित आधार पर, वितरण के लिए है। इस सेवा के लिए निर्धारित अवधि 90 दिन है। बिल मेल सेवा हेतु प्रथम 20 ग्राम के लिए प्रभार 3 रुपये और अतिरिक्त 20 ग्राम या उसके अंश के लिए प्रभार 1.60 रुपये होगा। इस सेवा से वर्ष 2005-06 के दौरान 330.95 मिलियन रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इस वर्ष मौजूदा बिल मेल सेवा का मूल्यवर्धन करते हुए कारपोरेट ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बिल मेल सेवा

प्रारम्भ की गई थी जिसमें इस सेवा को, समूचे भारत वर्ष में बिल वितरण हेतु स्पीड पोस्ट, ईपीएफ आदि जैसी अन्य सेवाओं के साथ पैकेज रूप में प्रस्तुत किया गया है।

व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय की नवीन पहल

5.19 व्यापार विकास एवं विपणन निदेशालय ने निम्नलिखित नए कदम उठाए :

- 2 जून, 2005 को सीधी डाक (डायरेक्ट पोस्ट) सेवा प्रारम्भ की गई।
- 14, नवम्बर, 2005 को 'मेरा दोस्त इंडिया पोस्ट प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। इसके प्रति काफी लोगों ने भरपूर उत्साह दिखाया।
- फरवरी, 2006 के पहले सप्ताह में यूपीयू के तत्वाधान में दिल्ली में डायरेक्ट मेल वर्कशाप आयोजित की गई।
- सर्किल अध्यक्षों को विभागीय तथा किराए पर लिए गए डाक परिसरों में तथा आस पास विज्ञापन हासिल करने और उनकी दरें नियत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं।

use Post Office outlets to sell cash cards and recharge coupons. The product has shown good potential, registering a growth rate of 28.92% during 2005-06 over the revenue earned during the previous year. The maximum revenue was earned by Maharashtra Circle.

Bill Mail Service

5.18 This service was launched nationwide on 15th September, 2003 for booking of communications in the nature of a financial statement, bill, monthly account bills or other such items of similar nature, which may be posted by service providers to their customers. The service is meant for the articles to be delivered locally or within a district on regular basis. The periodicity prescribed for the service is 90 days. The charges for Bill Mail Service are Rs. 3/- for first 20 gms. and Rs. 1.60 for additional 20 gms. or part thereof. This Service generated revenue of Rs. 330.95 Million in 2005-06. National Bill Mail Service as value addition to existing Bill Mail Service has stabilized, meeting the requirements of the corporate

customers, the service was packaged with other services like Speed Post, Express Parcel Post (EPP) etc. to deliver bills all over the country.

New Initiatives of Business Development and Marketing Directorate

5.19 The Business Development and Marketing Directorate have taken the following new initiatives:

- Direct Post launched on 2nd June, 2005.
- The 'Mera Dost India Post' contest was organized on 14th November, 2005. It generated huge public response.
- Direct Mail workshop organized in Delhi under the aegis of UPU in the first week of February, 2006.
- Powers have been delegated to Heads of Circles to fix rates and obtain advertisements in and around Departmental and rental postal premises.

अध्याय 6

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सेवा गुणवत्ता निधि (क्यूएसएफ)

6.1 विकासशील और कम विकसित देशों में डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 22वीं कांग्रेस द्वारा 1999 में सेवा गुणवत्ता निधि (क्यूएसएफ) स्थापित की गई। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है। भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के नौ निर्वाचित सदस्यों से बना न्यासी-बोर्ड क्यूएसएफ के कार्य की देखरेख करता है। भारत न्यासी-बोर्ड का निर्वाचित सदस्य है। सचिव (डाक) और उप महानिदेशक (आई आर) ने सेवा गुणवत्ता निधि के न्यासी बोर्ड की टोक्यो, जापान में 05 से 08 अप्रैल, 2005 तक आयोजित हुई बैठक में भाग लिया। भारतीय डाक ने न्यासी बोर्ड की नई दिल्ली में 20.7.2005 से 22.7.2005 तक आयोजित हुई अगली बैठक की मेजबानी की।

6.2 क्षेत्र के अग्रणी डाक प्रशासन और सेवा गुणवत्ता निधि के न्यासी बोर्ड के सदस्य के रूप में भारतीय डाक ने यूपीयू की सेवा गुणवत्ता निधि और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए टर्मिनल शुल्क की नई प्रणाली पर नई दिल्ली में 18.7.2005 से 20.7.2005 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया। सेवा गुणवत्ता निधि की कार्यविधियों में हुए परिवर्तनों तथा 1 जनवरी, 2006 से अनुप्रयोज्य टर्मिनल शुल्क की नई लेखाकरण प्रक्रियाओं से एशिया-प्रशांत देशों के प्रतिभागियों को अवगत कराना इस कार्यशाला का उद्देश्य था। कार्यशाला में 20 देशों के 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भारतीय डाक और जापान पोस्ट ने कम विकसित देशों के सभी प्रतिभागियों को संयुक्त रूप से अध्येतावृत्तियां प्रदान कीं।

एशिया प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू)

6.3 एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सचिव (डाक), उप महानिदेशक (आईआर) और सहायक महानिदेशक (आईआर) शामिल थे, ने एशिया प्रशांत डाक संघ की 9वीं कांग्रेस की 30 मई से 4 जून, 2005 तक सियोल, कोरिया में

आयोजित बैठक में भाग लिया। एपीपीयू एक सीमित संघ है। इसका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) से संबंध है। यूपीयू संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है। भारत समेत 29 देश एपीपीयू के सदस्य हैं। सदस्य देशों की डाक सेवाओं में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। भारत एपीपीयू के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाता है। एशिया प्रशांत डाक प्रशिक्षण केन्द्र के शासी बोर्ड और एशिया प्रशांत डाक सहयोग प्रबंधन बोर्ड (एपीपीसीएमबी) का सदस्य होने के अलावा भारत तकनीकी सहायता एवं सेवा की गुणवत्ता पर एपीपीयू की स्थायी समिति का अध्यक्ष है। एपीपीयू कांग्रेस, जिसे प्रत्येक चार वर्षों पर आयोजित किया जाता है, के दौरान भारत को एपीपीयू कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। यह एक ऐसा निकाय है जो दो कांग्रेसों के बीच काम करता है और एपीपीयू के कामकाज की देखरेख करने के लिए उत्तरदायी है।

बहुवर्षीय एकीकृत परियोजनाएं

6.4 विभाग ने ढाका, काठमांडू और यांगून में जेनरल पोस्ट आफिसों के पोस्ट आफिस काउंटर्स को कम्प्यूटरीकृत करने का काम हाथ में लिया है। ये परियोजनाएं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बहुवर्षीय एकीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई हैं। इनके लिए यूनिवर्सल यूनियन द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कम्प्यूटरीकरण और साफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को मान्यता देते हुए यूपीयू भारतीय डाक के माध्यम से इन कार्यकलापों को पूरा करवा रहा है। परियोजनाएं जनवरी, 2004 में शुरू की गई थीं। परियोजनाएं इन सभी देशों में सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। भारतीय डाक ने अगस्त, 2005 में मालदीव में चार डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना भी पूरी की है। यह परियोजना डाक विभाग और टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इण्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) द्वारा 2003 में संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। यह परियोजना मुख्यतया भारतीय डाक द्वारा विकसित मेघदूत साफ्टवेयर के ग्राहकोनुकूलन और संस्थापन से संबंधित थी।

Chapter 6

INTERNATIONAL RELATIONS

Quality of Service Fund (QSF)

6.1 With the aim of improving the quality of postal services in developing and least developed countries, Quality of Service Fund (QSF) was set up in 1999 by 22nd Congress of Universal Postal Union, a specialized agency of the United Nations. The Board of Trustees comprising nine elected members from different geographical regions manages the work of QSF. India is an elected member of the Board of Trustees. Secretary (Posts) and Deputy Director General (IR) attended the meeting of the Board of Trustees (BoT) of Quality of Service Fund (QSF) held in Tokyo, Japan from 05th to 08th April, 2005. India Post hosted the next meeting of the BoT in New Delhi from 20.07.2005 to 22.07.2005.

6.2 As a leading postal administration in the region and as a member of the Board of Trustees of the Quality of Service Fund, India Post organized a workshop on Quality of Service Fund of the UPU and new system of Terminal Dues for the Asia Pacific region from 18.07.2005 to 20.07.2005 in New Delhi. The aim of the workshop was to familiarize participants from the Asia Pacific countries with the changes in the Quality of Service Fund procedures and with the new accounting procedures for Terminal Dues that became applicable from 1st January 2006. As many as 28 participants from 20 countries participated in the workshop. India Post and Japan Post jointly granted fellowships to all participants from Least Developed Countries.

Asia Pacific Postal Union (APPU)

6.3 A three-member delegation comprising Secretary (Posts), DDG (IR) and ADG (IR) participated in the 9th Congress of Asian-Pacific Postal Union (APPU) held

in Seoul, Korea from 30th May to 4th June, 2005. The APPU is a restricted Union, which is affiliated to the Universal Postal Union, a specialized agency of the United Nations. The APPU, having a membership of 29 countries, including India, has been formed with the objective of promoting cooperation in postal services among member countries. India plays an active role in the affairs of APPU. Besides being a member of the Governing Board of the Asia Pacific Postal Training Centre and of the Asia Pacific Post Cooperative Management Board (APP CMB), India is Chairman of the APPU Standing Committee on Technical Assistance and Quality of Service. During the APPU Congress which is held every four years, India was elected the Vice Chair of the APPU Executive Council, a body which functions between two Congresses and is responsible for managing the affairs of the APPU.

Multi Year Integrated Projects

6.4 The Department undertook projects for computerizing post office counters at General Post Offices in Dhaka, Kathmandu and Yangon. The projects were taken under the Multi Year Integrated Projects of the Universal Postal Union with funds provided by the Union. These activities were taken up by the UPU through India Post in recognition of its capabilities in the area of computerization and software development. The projects were started in January, 2004. The projects have successfully been completed in all these countries. India Post also completed the project of computerization of four post offices in Maldives in August, 2005. The project was started in 2003 jointly by Department of Posts and Telecommunications Consultants India Ltd. (TCIL). The project mainly involved customization and installation of the Meghdoot software developed by India Post.

प्रतिनिधिमंडल

6.5 एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सचिव (डाक), उप महानिदेशक (आईआर) और निदेशक (प्रौद्योगिकी) शामिल थे, ने पेरिस में 03.10.2005 से 05.10.2005 तक आयोजित वर्ल्ड पोस्टल बिजनेस फोरम और पोस्ट एक्सपो 2005 में भाग लिया। सचिव (डाक) अध्यक्ष, ला पोस्टे, फ्रांस से भी मिले और परस्पर सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की।

6.6 सचिव (डाक) की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बर्न, स्विटजरलैंड में 27 मार्च से 6 अप्रैल, 2006 तक आयोजित डाक प्रचालन परिषद के वार्षिक सत्र में भाग लिया। सचिव (डाक) ने समिति 3 की बैठकों की अध्यक्षता भी की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने डाक प्रचालन परिषद के अन्य महत्वपूर्ण निकायों जैसे टेलीमेटिक्स कोआपरेटिव, ईएमएस कोआपरेटिव, सेवा गुणवत्ता निधि के न्यासीमंडल, टर्मिनल शुल्क परियोजना ग्रुप के कार्यदल 13 आदि की बैठकों में भाग लिया।

6.7 इस अवधि के दौरान रॉयल मेल के चेयरमैन सहित मंगोलिया एवं स्विस् पोस्ट के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों ने आपसी रुचि और सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु भारत का दौरा किया। क्यूबा के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व सुश्री सिव्लिया मुनारिज मॉन, उप मंत्री, सूचना एवं संचार क्यूबा कर रही थीं, ने 28.2.2006 को डाक विभाग का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल को ई-पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर (आईएमओ) प्रणाली और मेघदूत साफ्टवेयर का प्रदर्शन दिखाया गया। प्रतिनिधियों ने सभी तीनों प्रणालियों में गहरी रुचि दिखाई।

6.8 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के महानिदेशक मि. एडुआर्ड दयान ने 07.03.2006 से 10.03.2006 तक भारत का दौरा किया। उनके साथ यूपीयू के एशिया एवं प्रशांत रीजनल विशेषज्ञ, मि. ओसामू गोदो भी आए थे। यह दौरा इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था कि यह 11 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था। मि. दयान को भारत सरकार के अतिथि का दर्जा दिया गया था। वे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठकों के दौरान यूपीयू एवं भारतीय डाक से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई और भारतीय

डाक को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर किया गया। मि. दयान ने ई-पोस्ट, तत्काल मनीआर्डर, पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत, गाजियाबाद में अत्याधुनिक कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण सुविधाओं, पर्यावरण एवं टिकाऊ विकास आदि के क्षेत्रों में भारतीय डाक द्वारा की गई पहलों में गहरी रुचि दिखाई। यूपीयू ने अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरणों, सेवा की गुणवत्ता का परीक्षण, गुणवत्ता बनाए रखने, तकनीकी मानक, ईएमएस आदि जैसे क्षेत्रों में भारतीय डाक की मदद करने के प्रति अपनी इच्छा भी व्यक्त की।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेना

6.9 एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड, उप महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) तथा सहायक महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय मेल) शामिल थे, ने बर्न, स्विटजरलैंड में 5 से 21 अक्टूबर, 2005 तक आयोजित प्रशासन परिषद के सत्र के दौरान यूपीयू के डाक प्रचालन परिषद की बैठक में भाग लिया। भारत 40 सदस्यीय डाक प्रचालन परिषद का एक सदस्य है तथा प्रचालनात्मक मुद्दों पर समिति 3 की अध्यक्षता करता है। परिषद सदस्य डाक प्रशासनों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालनों के महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक, वाणिज्यिक, आर्थिक और तकनीकी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। भारतीय डाक उन दो डाक प्रशासनों (दूसरा देश चीन था) में से एक था जिसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा भारत में डाक सेवाओं के विकास पर प्रस्तुतीकरण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस पर सदस्य (प्रचालन) द्वारा प्रस्तुतीकरण पेश किया गया जिसे बहुत अधिक सराहा गया।

6.10 सचिव (डाक) ने इन्फॉर्मेशन सोसायटी (डब्ल्यूएसआईएस) के विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 से 18 नवम्बर, 2005 तक ट्यूनिंस, ट्यूनीशिया का दौरा किया। शिखर सम्मेलन में सबके लिए सुलभ सूचनापरक समाज का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारों, बिजनेसों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों को इकट्ठा बुलाया गया था। सचिव (डाक) ने 'भारतीय डाक और आईसीटी : डिजिटल दूरी पाटने का एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण पेश किया।

टर्मिनल शुल्क परियोजना दल (टीडीपीजी)

6.11 भारतीय डाक ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के डाक प्रचालन परिषद के टर्मिनल शुल्क परियोजना दल (टीडीपीजी)

Delegations

6.5 A three-member delegation comprising Secretary (Posts), Deputy Director General (IR) and Director (Technology) attended the World Postal Business Forum and Post Expo 2005 held in Paris from 03.10.2005 to 05.10.2005. Secretary (Posts) also met the Chairman, La Poste, France and discussed the various areas of mutual cooperation.

6.6 A three-member delegation headed by Secretary (Posts) attended the annual session of POC held from 27th March to 6th April, 2006 at Berne, Switzerland. Secretary (Posts) chaired the Meetings of Committee 3. The Indian delegation attended meetings of the other important bodies of POC such as Telematics Cooperative, EMS Cooperative, Board of Trustees of Quality of Service Fund, Working Group 13 of the Terminal Dues Project Group etc.

6.7 During this period several international delegations from Royal Mail including their Chairman, Mongolia and Swiss Post visited India to discuss issues of mutual interest and cooperation. A Cuban delegation led by Ms. Silvia Munarriz Mon, Vice Minister, Information and Communications, Cuba visited Department of Posts on 28.02.2006. A demonstration of the ePost, International Money Order (IMO) systems and Meghdoot software was given to the delegation. The delegates displayed keen interest in all three systems.

6.8 Mr. Edouard Dayan, Director General of Universal Postal Union visited New Delhi from 07.03.2006 to 10.03.2006. He was accompanied by Mr. Osamu Goto, the Asian and Pacific Regional Expert in the UPU. The visit was extremely significant being undertaken after a gap of 11 years. Mr. Dayan was accorded the status of a guest of the Government of India. He met the Hon'ble Minister of State for Communications & IT and senior officers of the department. During the meetings with the delegation, important matters involving UPU and India Post were discussed and issues affecting India Post were

highlighted. Mr Dayan expressed keen interest in the initiatives being taken by India Post in the areas of ePost, Instant Money Order, state of the art computer labs and training facilities at Postal Staff College India, Ghaziabad, Environment and Sustainable Development etc. UPU has also expressed its willingness to help India Post in areas such as international money transfers, quality of service testing, addressing quality, technical standards, EMS etc

Participation in International Meetings

6.9 A three-member delegation comprising Member (Operations), Postal Services Board, Deputy Director General (International Relations) and Assistant Director General (International Mails) attended the meeting of Postal Operations Council (POC) of UPU held during the session of Council of Administration from 5th to 21st October, 2005 in Berne, Switzerland. India is a member of the 40-member Postal Operations Council (POC) and chairs Committee 3 on Operational Issues. The Council is responsible for important operational, commercial, economic and technical aspects of international postal operations among member postal administrations. India Post was one of the two postal administrations (the other being China) invited by the Universal Postal Union to make a presentation on the development of postal services in India. As such Member (Operations) made a presentation that was received very well.

6.10 Secretary (Posts) visited Tunis, Tunisia to attend the World Summit on the Information Society (WSIS) held from 14 to 18 November, 2005. The Summit brought together international organizations, governments, businesses and civil society representatives involved in building an information society accessible to all. Secretary (Posts) made a presentation on the topic "India Post and ICTs: A regional approach to bridging the digital divide".

Terminal Dues Project Group (TDPG)

6.11 India Post hosted the meeting of the Steering Committee of the Terminal Dues Project Group (TDPG)

की संचालन समिति की बैठक की 12-13 जनवरी, 2006 तक जयपुर में मेजबानी की। टर्मिनल शुल्क परियोजना दल यूपीयू की डाक प्रचालन परिषद द्वारा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कार्यकलापों में से एक है और टर्मिनल शुल्क की एक नई प्रणाली को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय डाक ग्रेट ब्रिटेन के साथ टीडीपीजी के भीतर नीतिगत प्रश्नों के कार्य दल की सह अध्यक्षता कर रहा है। बैठक में 12 देशों एवं यूपीयू के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पार्सलों का ट्रैक एवं ट्रेस

6.12 जनवरी, 2006 से एक नई पार्सल डाक डिलीवरी भुगतान प्रणाली प्रचलन में लाई गई है। इस नई प्रणाली में एक प्रशासन भागीदार प्रशासन के साथ मिलकर पार्सलों के बारे में ट्रैक एवं ट्रेस सूचना प्रदान करता है तथा ट्रैकिंग घटनाक्रमों पर आंकड़ों का आदान प्रदान करता है। भागीदार प्रशासन को वर्ष 2006 के लिए नियत बेस आवक लैण्ड रेट का 15% बोनस के रूप में मिलेगा।

6.13 भारतीय डाक ने नए विश्वव्यापी पार्सल नेटवर्क की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं तथा पार्सलों के ट्रैक एवं ट्रेस के लिए भागीदार प्रशासनों के साथ

इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस संदेशों का आदान-प्रदान करने के लिए बुनियादी सूचना तंत्र स्थापित किया है।

विदेश डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

6.14 विदेश डाकघरों और उप विदेश डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने की परियोजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूरी कर ली गई है। विभाग ने मुंबई एवं दिल्ली विदेश डाकघरों और कोची, उप विदेश डाकघर में अंतर्राष्ट्रीय पार्सल डाक हबों को विकसित करने की परियोजना भी शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय पार्सल डाक हब परियोजना का उद्देश्य पार्सलों की विशेषीकृत हैंडलिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप पार्सलों की हैंडलिंग में लगने वाले समय के काफी सीमा तक कम हो जाने की सम्भावना है। यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जा रही पार्सल सेवा की बेहतर क्वालिटी से अंतर्राष्ट्रीय मानकों से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी और इस तरह इससे बिजनेस के साथ अंतर्राष्ट्रीय पार्सलों में विभाग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी इससे हमारी बाजार स्थिति आगे और सुदृढ़ होगी तथा विभाग के लिए और अधिक राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी।

of the Postal Operations Council of the Universal Postal Union in Jaipur on 12-13 January, 2006. The Terminal Dues Project Group is one of the most important activities taken up by the Postal Operations Council of UPU and a new system of Terminal Dues is in the process of being evolved. India Post co-chairs the Working Group on Policy Questions within the TDPG along with Great Britain. 16 participants from 12 countries and UPU participated in the meeting.

Track and Trace of Parcels

6.12 A new parcel post delivery payment system has been introduced from January 2006 onwards. According to the new system an Administration provides track & trace information about parcels and exchanges data on the tracking events with partner administration, it will receive 15% of the base Inward Land Rate set for the year 2006 as bonus.

6.13 India Post has taken necessary steps to meet the requirements of the new worldwide parcel network and has set up basic information for exchange of

Electronic Data Interface messages with partner Administrations for track & trace of parcels.

Computerization of Foreign Post Offices

6.14 The project for computerization of Foreign Post Offices and Sub Foreign Post Offices has been completed under the 10th Five Year Plan. The Department has also undertaken the project to develop International Parcel Post Hubs at Mumbai and Delhi Foreign Post Offices and Kochi Sub Foreign Post Office. The International Parcel Post Hub project is aimed to provide specialized handling of parcels. As a result of implementation of this project, the time taken in handling of parcels is expected to reduce considerably. It is expected that the improved quality of parcel service offered by India Post will help in competing with international standards and thereby increase the business and market share of the Department in International Parcels. This would further strengthen our market position and help in generating more revenue for the Department.

अध्याय 7

प्रौद्योगिकी

परिचय

7.1 योजना आयोग द्वारा गठित च्कार्य दलछ की सिफारिशों के आधार पर भारतीय डाक ने प्रौद्योगिकी के प्रवेश के माध्यम से और सभी बड़े डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण द्वारा अपने प्रचालन/ कार्य प्रणाली का उन्नयन करने के लिए तथा प्रभावपूर्ण मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु प्रचालक फील्ड यूनिटों का नेटवर्क प्रदान करने के संबंध में अपनी वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रयास जारी रखे हैं। भारतीय डाक ने ग्राहकों की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नए उत्पाद एवं सेवाएं भी प्रारंभ किए हैं।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग

7.2 प्रभावपूर्ण और समयबद्ध तरीके से गुणात्मक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय डाक ने 8362.7 मिलियन रुपये की बजटीय सहायता से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी प्रधान डाकघरों तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसंख्य डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने तथा नेटवर्क के माध्यम से सभी डाकघरों को आपस में जोड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि के चौथे वर्ष (2005-06) की समाप्ति तक भारतीय डाक ने देशभर में सभी 839 प्रधान डाकघर और 6184 उप डाकघर कम्प्यूटरीकृत कर दिए हैं। इसके अलावा 19 डाक लेखा कार्यालय और 139 प्रशासनिक कार्यालय भी कम्प्यूटरीकृत कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र

7.3 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के समन्वय से भारतीय डाक स्वयं द्वारा अथवा किसी भी अन्य बाहरी साफ्टवेयर विकास एजेंसियों द्वारा विकसित सभी मौजूदा साफ्टवेयरों को केन्द्रीय सर्वर आधारित प्रौद्योगिकी पर चलाने के लिए सभी प्रधान डाकघरों, प्रशासनिक कार्यालयों, लेखा

कार्यालयों, स्पीड पोस्ट केन्द्रों आदि की नेटवर्किंग करने के लिए 'राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र' की स्थापना कर रहा है। प्रारंभ में, लगभग 1300 डाकघरों को नेटवर्क किया जाएगा और अगले वर्षों में यह नेटवर्किंग सभी कम्प्यूटरीकृत डाकघरों में विस्तारित की जाएगी।

साफ्टवेयर विकास केन्द्र

7.4 मैसूर, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में चार विभागीय साफ्टवेयर विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। तीन केन्द्र इस दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। इन केन्द्रों द्वारा विकसित विभागीय साफ्टवेयर देशभर के कम्प्यूटरीकृत डाकघरों तथा अन्य प्रशासनिक/प्रचालन कार्यालयों में सभी फ्रन्ट आफिस तथा बैक आफिस प्रचालनों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।

स्वचालित मेल प्रोसेसिंग केन्द्र (एएमपीसी)

7.5 वर्ष 1993 और 1996 में क्रमशः मुम्बई तथा चेन्नई में दो एएमपीसी स्थापित किए गए थे। चार मेट्रो शहरों में डाक छंटाई प्रक्रिया को मशीनीकृत करने तथा डाक के पारेषण के प्रयोजन से चार मेट्रो शहरों को एकीकृत कर राष्ट्रीय मेल ग्रिड बनाने के प्रयास में भारतीय डाक ने दिल्ली और कोलकाता में एडवांस आप्टिकल कैरेक्टर रिकॉगनिशन (ओसीआर) प्रौद्योगिकी के साथ दो और एएमपीसी की स्थापना के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। परियोजना के वर्ष 2007 में प्रारंभ होने की संभावना है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से 4 मेट्रो शहरों यथा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में उत्पन्न डाक को तीव्र प्रोसेसिंग तथा वितरण सुनिश्चित करने वाले नेटवर्क में कवर किया जा सकेगा। इस परियोजना के निष्पादनार्थ सरकार द्वारा 710.5 मिलियन रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

Chapter 7

TECHNOLOGY

Introduction

7.1 Based on the recommendations of the “Working Group” constituted by the Planning Commission, India Post has been continuing its efforts during the current five year plan to upgrade its operative/working systems by induction of technology and computerization of all large Post Offices and provide a network of operative field units to ensure effective monitoring. India Post has also launched technology based new products and services to meet the present and future needs of the customers.

Computerization & Networking of Post Offices

7.2 With an objective to render quality service in an effective and time bound manner, India Post has laid a target to computerize all Head Post Offices and a large number of Sub Post Offices in urban as well as rural areas and to link all these Post Offices through a network during the 10th Five Year Plan with a budgetary support of Rs. 8362.7 Million. Upto the end of 4th year (2005-06) of the current five year plan period, India Post has computerized all the 839 Head Post Offices and 6184 Sub Post Offices across the country. Further, 19 Postal Accounts Offices and 139 Administrative Offices have also been computerized.

National Data Centre

7.3 India Post in coordination with National Informatics Centre (NIC) is establishing a “National Data Centre” to facilitate networking of all HPOs, Administrative Offices, Accounts Offices, Speed

Post Centres, etc. by running all the existing software developed either by India Post or by other outside software development agencies on a Central Server Based Technology. Initially, about 1300 offices are to be networked and this networking will be extended to all computerised offices in the following years.

Software Development Centres

7.4 India Post has set up four Departmental Software Development Centres at Mysore, Kolkata, Hyderabad and Chennai. The last three Centres were set up during this 10th Five Year Plan. The departmental software developed by these Centres are used in Computerised Post Offices and other Administrative/Operative Offices for all front office and back office operations across the country.

Automated Mail Processing Centres (AMPC)

7.5 Two AMPCs were set up at Mumbai and Chennai during the year 1993 and 1996 respectively. In its efforts to mechanise the mail sorting process at all the four metro cities and to form a National Mail Grid by integrating the four metro cities for the purpose of transmission of mails. India Post has initiated action for setting up of two more AMPCs with advanced Optical Character Recognition (OCR) technology at Delhi and Kolkata. The project is likely to be commissioned during the year 2007. By implementing this project, the mails generated in the 4 metro cities i.e. Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata will be covered by a network ensuring faster processing & delivery. To execute this project, an outlay of Rs. 710.5 Million has been approved by the Government.

डाकघरों में कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण

7.6 कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने और उनकी कार्य-दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय डाक ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 157.2 मिलियन रुपये के परिव्यय से 811 डाकघरों के कार्य-वातावरण में सुधार लाने तथा 40 मिलियन रुपये के परिव्यय से नई

इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रचालनात्मक डिवाइस द्वारा 1600 डाकघरों को उपस्करबद्ध करने की योजना बनाई है। वर्ष 2005-06 तक 552 डाकघरों को कार्य-वातावरण को सुधारने के कार्यकलाप के अंतर्गत कवर किया गया तथा 1936 डाकघरों को नई इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रचालनात्मक डिवाइस की आपूर्ति के कार्यकलाप के अंतर्गत कवर किया गया।

Modernisation of Working System in Post Offices

7.6 To provide better working environment for the staff and to accelerate their functional efficiency, so as to render greater satisfaction to the customers, India Post has planned to improve ergonomics in 811 Post Offices with an outlay of Rs. 157.2 Million and also to

equip 1600 Post Offices with new electro-mechanical operational devices with an outlay of Rs. 40 Million during the 10th Five Year Plan. Upto the year 2005-06, 552 Post Offices have been covered under the activity of improving ergonomics and 1936 Post Offices have been covered under the activity of supply of new electro-mechanical operational devices.

अध्याय 8

वित्तीय सेवाएं

8.1 डाकघर बचत बैंक देश के सबसे पुराने एवं सबसे बड़े बैंकिंग संस्थानों में से है। डाकघर बचत बैंक योजना एक एजेंसी कार्य है जो डाक विभाग द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से निष्पादित किया जाता है। डाकघर बचत बैंक डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से समूचे देश के लोगों को विभिन्न स्कीमों में अपनी बचत-राशि जमा करने का अवसर प्रदान करता है। इसकी पहुंच और सेवा की देश की किसी भी अन्य बैंकिंग एजेंसी से तुलना नहीं की जा सकती। वित्त मंत्रालय इस एजेंसी कार्य के लिए डाक विभाग को समय-समय पर नियत दर से पारिश्रमिक देता है।

8.2 डाकघर बचत बैंक की ग्राहक संख्या 162 मिलियन खाताधारक है तथा वार्षिक जमा राशि 1,600,000 मिलियन रु. से अधिक है। बचत बैंक सुविधा 1,54,000 डाकघरों के नेटवर्क

की मार्फत उपलब्ध करवाई जाती है जो देश में सभी बैंकिंग इकाइयों को मिलाने के बाद प्राप्त होने वाली संख्या से भी दुगुनी है। इन सेवाओं को देशभर में डाकघरों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। ये बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय स्कीम, लोक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक स्कीम, किसान विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बचत पत्र हैं। डाकघरों की पहुंच एवं नेटवर्क का अधिकतम उपयोग करने के लिए भारतीय डाक विभिन्न निजी-सार्वजनिक भागीदारियों के माध्यम से नई वित्तीय सेवाओं की शुरुआत करने का प्रयास कर रही है।

8.3 सभी राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत डाकघरों का बकाया शेष 4,590,000 मिलियन रुपये है। बचत योजनाओं के विवरण नीचे तालिका 4 में दिए गए हैं:

तालिका 4 बचत योजना: विवरण (31.3.2006 को)		
स्कीम का नाम	खातों की संख्या	जमा की गई कुल राशि (मिलियन रु. में)
बचत खाते (बचत बैंक)	60,911,773	167,899.6
आवर्ती जमा खाते	64,723,609	501,897.6
सावधि जमा खाते	8,576,579	368,781.7
मासिक आय योजना खाते	24,625,490	1,830,760.5
राष्ट्रीय बचत पत्र खाते (87 एवं 92)	857,816	40,592.6
लोक भविष्य निधि खाते	1,981,703	168,712.9
वरिष्ठ नागरिक	489,931	159,160.8
योग	162,166,901	3,237,805.7

डाक वित्त मार्ट

8.4 भारतीय डाक को एक मित्रवत "एकल स्थल वित्तीय सेवा प्रदाता" के रूप में स्थापित करने हेतु कुछ डाकघरों की वित्तीय मार्ट के रूप में डाकघर बचत बैंक सेवाएं तथा नई

वित्तीय सेवाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण, घरेलू धन अंतरण, म्युचुअल फंड पेंशन फंड, इलेक्ट्रॉनिक फंड अंतरण, डाक जीवन बीमा, ओरियन्टल जीवन बीमा इत्यादि के गैर जीवन बीमा उत्पाद सेवाएं देने के लिए पुनः संरचना की जा रही है। डाक

Chapter 8

FINANCIAL SERVICES

8.1 The Post Office Savings Bank (POSB) is the oldest and largest banking institution in the country. The Post Office Savings Bank Scheme is an agency function performed by the Department of Posts on behalf of the Ministry of Finance, Government of India. Through its network the Post Office Savings Bank provides an avenue to people all over the country to deposit their savings in various schemes. Its reach and service is unparalleled by any other banking agency in the country. The Ministry of Finance remunerates the Department of Posts for the Savings Bank work at a rate fixed from time-to-time.

8.2 Post Office Savings Bank has a customer base of 162 Million account holders with annual deposits

exceeding Rs. 1,600,000 Million and a branch network of 1,54,000 branches, which is double the size of all banks in the country put together. Products that are retailed from the post offices across the country include Savings Account, Recurring Deposit, Time Deposit, Monthly Income Scheme, Public Provident Fund, Senior Citizens Savings Scheme, Kisan Vikas Patras and National Savings Certificates. In order to utilize the network and reach of the Post Offices optimally, India Post is attempting to introduce new financial services through various public-private partnerships.

8.3 The outstanding balance under all national savings schemes in post offices is over Rs. 4,590,000 Million. Profile of the Savings Schemes is given in Table 4: -

TABLE 4
SAVINGS SCHEME: PROFILE (AS ON 31.03.2006)

Name of Scheme	Number of Accounts	Total Amount Deposited (Rs. in Million)
Saving Accounts (SB)	60,911,773	167,899.6
RD Accounts	64,723,609	501,897.6
TD Accounts	8,576,579	368,781.7
MIS Accounts	24,625,490	1,830,760.5
NSS Accounts (87 & 92)	857,816	40,592.6
PPF Accounts	1,981,703	168,712.9
Sr. Citizen	489, 931	159,160.8
Total	162,166,901	3,237,805.7

Postal Finance Mart

8.4 To establish India Post as a friendly neighbourhood 'One-Stop Financial Service Provider', some post offices are being re-modeled into Finance

Marts for providing POSB (Post Office Savings Bank) services and new Financial Services, such as, International Money Transfer, Domestic Money Transfer, Mutual Funds, Pension Funds, Electronic Fund Transfer, Postal Life Insurance, non-life insurance products of

वित्तीय मार्ट को भारतीय म्युचुअल फंड तथा बीमा से अर्हता प्राप्त स्टॉफ द्वारा संचालित किया जाता है जिससे वे जमाकर्ताओं को वित्तीय सलाह उपलब्ध करा सकें। 2005-06 में 142 डाक वित्तीय मार्टों का संचालन शुरू हो गया। इस योजना को अधिक स्थानों में संचालित करने का प्रस्ताव है।

तत्काल मनीआर्डर (आईएमओ)

8.5 तत्काल मनीआर्डर (आईएमओ) एक आन-लाइन घरेलू धन पारेषण सेवा है जो तत्काल धन प्रेषण की अपेक्षा वाले ग्राहकों के लिए लक्षित है। इस सेवा को जनवरी 2006 में शुरू किया गया। यह सेवा ग्राहक को तत्काल मनीआर्डर सेवा उपलब्ध कराने वाले किसी डाकघर से मिनटों में सेवा प्रदान करती है। वर्तमान में यह योजना 58 डाकघरों में है तथा इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है।

म्युचुअल फंड एवं बांड्स

8.6 म्युचुअल फंड उद्योग खूब प्रगति कर रहा है तथा देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें लगभग 2,318,620 मिलियन रु. की संपत्ति है। यह उद्योग एसेट मैनेजमेंट कम्पनियों के प्रबंधन के तहत है। भारतीय डाक ने म्युचुअल फंडों की खुदरा-बिक्री करने के बिजनेस में प्रवेश किया है ताकि म्युचुअल फंड को चुने हुए डाकघरों के ऐसे ग्राहकों तक पहुंचाया जाए जो अपने निवेश के लिए तीव्रतर विकास (बढ़ोतरी) के अवसरों की तलाश में रहते हैं।

8.7 पहले से ही 250 से अधिक डाकघरों का बढ़ता हुआ नेटवर्क है जिनमें प्रिंसिपल- प्रूडेंशियलआईसीआईसीआई/एसबीआई/आईसीआईसीआईकैपिटल/आईडीबीआई बांडों के चुने हुए म्युचुअल फंडों और बांडों का वितरण किया जा रहा है। इस सेवा से न केवल देश के पूंजी बाजार की पहुंच का विस्तार हुआ है वरन इसने आम आदमी के लिए बाजार आधारित निवेश विकल्प भी सुलभ कराया है। यूटीआई और एसबीआई के विभिन्न नए फंड ऑफर (एनएफओ) भी डाकघरों में रिटेल किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा

8.8 भारतीय डाक-वेस्टर्न यूनियन गठजोड़ ग्राहकों को वास्तविक समय आधार पर 205 से अधिक देशों एवं क्षेत्रों से धन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। फिलहाल यह सेवा

8,500 से अधिक डाकघरों में उपलब्ध है। इस सेवा से वर्ष 2005-06 में 17035.6 मिलियन रुपए का धन प्रेषण प्राप्त हुआ है तथा इसने भारतीय डाक के लिए 215.9 मिलियन रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

गैर जीवन बीमा उत्पादों की खुदरा बिक्री

8.9 डाक विभाग ने आरियन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड के साथ देश के मुख्य डाकघरों के माध्यम से कॉरपोरेट एजेंट के बतौर कम्पनी के गैर जीवन बीमा उत्पादों की खुदरा बिक्री के लिए एक गठबन्धन किया है।

डाकघर बचत बैंक खाताधारकों को दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर

8.10 डाक विभाग ने आरियन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड के अनुरोध पर बचत बैंक/मासिक आय योजना/वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के खाता धारकों को दुर्घटना मृत्यु बीमा उपलब्ध कराने के लिए गठबन्धन किया है। इस सेवा को आरियन्टल बीमा कम्पनी द्वारा पहले से उपलब्ध कराए जा रहे उत्पादों के साथ एक अन्य उत्पाद के बतौर डाकघरों से बिक्री हेतु 20 जनवरी, 2006 को शुरू किया गया। यह डाकघर बचत बैंक ग्राहकों को मूल्य संवर्धन उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम है। यह नई योजना 15 रु. के निम्न वार्षिक प्रीमियम पर एक वर्ष के लिए एक लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर उपलब्ध कराती है। यह डाकघर बचत बैंक ग्राहकों के लिए विशेषतः ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के डाकघर बचत बैंक ग्राहकों के लिए बहुत आकर्षक है क्योंकि सामान्यतः उनके पास कोई जोखिम कवर नहीं होता।

नई पहल

8.11 वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विभाग की नई पहल का केन्द्र बिन्दु सेवाओं को एक साथ उपलब्ध कराना है जो कि नेटवर्क की खुदरा बिक्री की पहुंच का लाभ उठाकर ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करेगा। अतः डाकघर न केवल बचत बैंक योजनाओं के लिए धीरे-धीरे एकल स्थल दुकान (वन स्टॉप शॉप) बन सकते हैं बल्कि निजी-सार्वजनिक इकाइयों के लिए लाभप्रद भी होंगे जो इसके माध्यम से उन क्षेत्रों तक पहुंचना चाहते हैं जो अन्यथा उनकी पहुंच के बाहर होंगे। नई की गई पहल निम्नलिखित हैं:

Oriental Life Insurance etc. Postal Finance Marts are manned by staff having Association of Mutual Funds of India (AMFI) and Insurance qualifications to enable them to provide investment advice to depositors. In 2005-06, 142 Postal Finance Marts started operating. The scheme is proposed to be extended to more locations.

Instant Money Order (iMO)

8.5 Instant Money Order (iMO), an on-line domestic money transmission service intended for a market clientele requiring instant money remittance. The service was launched in January, 2006. This service enables the customers to receive money in minutes from any of the post office providing iMO service. The scheme is presently available in 58 post offices and is proposed to be expanded.

Mutual Funds & Bonds

8.6 The Mutual Funds industry is making rapid strides and growing at a fast pace in the country, with nearly Rs. 2,318,620 Million of assets under the management of Asset Management Companies. India Post has entered into the business of retailing of Mutual Funds so as to bring mutual fund within the reach of a select post office clientele who are looking for a faster growth avenue for their investment.

8.7 There is already a growing network of over 250 post offices distributing select Mutual Funds and Bonds of Principal/Prudential-ICICI/SBI/ICICI Capital/IDBI Bonds. This service while extending the reach of the capital market of the country, also provides the common man easy access to market based investment options. Various New Fund Offers (NFOs) of UTI and SBI have been retailed in the post offices.

International Money Transfer Service

8.8 The India Post – Western Union tie-up provides the customer the facility of receiving remittances from more than 205 countries and territories on a real time

basis. The service is currently available from more than 8,500 post offices. The service has brought in remittances worth Rs. 17035.6 Million in the year 2005-06 and has generated revenue of Rs. 215.9 Million for India Post.

Retailing of Non-Life Insurance products

8.9 The Department of Posts in a tie up with Oriental Insurance Co. Ltd. (OIC) is retailing the company's non-life insurance products as Corporate Agents through major post offices in the country.

Accidental Death Insurance Cover to POSB Account Holders

8.10 The Department of Posts has tied up with Oriental Insurance Company Limited (OIC) to provide Accidental Death Insurance for account holders of Savings Bank/Monthly Income Scheme/Senior Citizen Savings Scheme on request basis. This service was launched on 20th January, 2006 as an add on product to the products already provided by OIC for sale from Post Offices. It is a step in the direction of providing value addition to Post Office Savings Bank customers. This new scheme provides Accidental Death Insurance cover for one year of Rs. one lakh at a low annual premium of Rs.15/-. It is very attractive to Post Office Savings Bank customers especially in rural and remote areas, as generally they do not have any risk cover whatsoever.

New Initiatives

8.11 The focus of the Department's initiatives in the area of financial services is to provide a bouquet of services that will cater to the needs of the customer by leveraging the retailing outreach of the network. Thus, post offices can gradually become a one-stop shop not only for Saving Bank schemes but also for public private entities who wants to ride the outreach to reach areas which are otherwise inaccessible to them. The new initiatives taken are as follows: -

- (i) ग्राहकों द्वारा ग्राहक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत त्रैवार्षिक ब्याज अपने घर में विभाग की मनीआर्डर सेवा के माध्यम से मनीआर्डर कमीशन अदा करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है।
- (ii) मासिक आय योजना/वरिष्ठ नागरिक बचत योजना ब्याज की राशि को खाताधारक के अनुरोध पर उत्तर दिनांकित चेक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

सामाजिक लाभ योजना

8.12 2 फरवरी, 2006 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों को पारिश्रमिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए 27 राज्यों में 200 जिलों की पहचान की है। डाक विभाग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में बचत बैंक खातों के माध्यम से पारिश्रमिक भुगतान कर इस योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की है।

डाक जीवन बीमा

8.13 सन् 1884 में प्रारंभ की गई डाक जीवन बीमा योजना (पीएलआई) सरकारी कर्मचारियों के हितलाभ के लिए शुरू की गई सबसे पुरानी डाक जीवन बीमा योजना है। प्रारंभ में यह केवल डाक कर्मचारियों के लिए ही शुरू की गई थी। आज यह स्कीम केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मियों, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनेकों स्वायत्त तथा वित्तीय संस्थानों और केन्द्र व राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा रक्षा संस्थापनाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा प्रदान कर रही है। एक अभिनव परिवर्तन के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के हितलाभ के लिए वर्ष 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना (आरपीएलआई) शुरू की गई है।

8.14 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि की स्थिति और वर्ष 2005-2006 के दौरान अधिप्राप्त कारोबार की स्थिति नीचे तालिका 5 में दी गई है:-

तालिका 5				
डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा द्वारा किया गया कार्य-निष्पादन				
योजना का नाम	अधिप्राप्त पालिसियों की संख्या	बीमित राशि (मिलियन रु. में)	क्रियाशील (सक्रिय) पालिसियों की कुल संख्या	31.03.2006 तक बीमित सकल राशि (मिलियन रु. में)
डाक जीवन बीमा	364,564	45,332.0	3,098,248	229,516.0
ग्रामीण डाक जीवन बीमा	1,443,818	88,228.6	4,702,776	252,296.0

8.15 डाक जीवन बीमा निम्नलिखित प्रकार की पालिसियों की सुविधा प्रदान करती है:-

- (i) आजीवन बीमा (सुरक्षा)
- (ii) परिवर्तनीय आजीवन बीमा (सुविधा)
- (iii) बंदोबस्ती बीमा (संतोष)
- (iv) 15 एवं 20 वर्षों के लिए प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (सुमंगल)
- (v) संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा (युगल सुरक्षा)

(vi) चिल्ड्रन पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

8.16 ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की पॉलिसियाँ प्रदान की जाती हैं।

- (i) आजीवन बीमा (ग्राम सुरक्षा)
- (ii) परिवर्तनीय आजीवन बीमा (ग्राम सुविधा)
- (iii) बंदोबस्ती बीमा (ग्राम संतोष)
- (iv) 15 एवं 20 वर्षों के लिए प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (ग्राम सुमंगल)

- (i) The customers can receive the quarterly interest under Senior Citizen Savings Scheme at their doorstep through the Money Order service of the Department after paying the money order commission.
- (ii) The Monthly Income Scheme/Senior Citizen Savings Scheme interest amount can be received through Post Dated Cheques on the request of the account holder.

Social Benefit Scheme

8.12 On 2nd February, 2006 Government of India introduced National Rural Employment Guarantee Scheme to provide wage employment to skilled/semiskilled/unskilled labourers across the country. The Government has identified 200 Districts in 27 States for implementation of National Rural Employment Guarantee Scheme. The Department of Posts has taken an initiative to facilitate implementation of this Scheme by way of

payment of wages through Savings Bank account in the states of Andhra Pradesh, Karnataka and West Bengal.

Postal Life Insurance

8.13 Postal Life Insurance (PLI), introduced in 1884, is the oldest life insurance scheme for the benefit of Government employees. Initially meant only for the Postal employees, today it caters to employees of the Central and State governments, Local bodies, Government aided Educational Institutions, Universities, Nationalized Banks, Autonomous and Financial institutions, Public Sector Undertakings of the Central and State Governments and Officers and Staff of Defence Establishments. In a major innovation, Rural Postal Life Insurance (RPLI) scheme was introduced in 1995 for the benefit of the rural populace.

8.14 The status of PLI/RPLI funds as on 31.03.2006, and the business procured during the year 2005-2006 is given in Table 5.

TABLE 5 PERFORMANCE OF PLI/RPLI				
Name of Plan	No of Policies Procured	Sum Assured (Rs. in Million)	Aggregate No. of Active Policies	Aggregate Sum Assured up to 31.03.2006 (Rs. in Million)
PLI	364,564	45,332.0	3,098,248	229,516.0
RPLI	1,443,818	88,228.6	4,702,776	252,296.0

8.15 PLI offers the following types of policies: -

- (i) Whole Life Assurance (Suraksha)
- (ii) Convertible Whole Life Assurance (Suidha)
- (iii) Endowment Assurance (Santosh)
- (iv) Anticipated Endowment Assurance for 15 & 20 years (Sumangal)
- (v) Joint Life Endowment Assurance (Yugal Suraksha)

(vi) Children Policy (Bal Jivan Bima)

8.16 The following types of Policies are offered in RPLI

- (i) Whole Life Assurance (Gram Suraksha)
- (ii) Convertible Whole Life Assurance (Gram Suidha)
- (iii) Endowment Assurance (Gram Santosh)
- (iv) Anticipated Endowment Assurance for 15 & 20 years (Gram Sumangal)

(v) 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिय)

बीमा की अधिकतम सीमा क्रमशः 1 लाख रुपये और 20,000 रुपये है।

(vi) चिल्ड्रन पॉलिसी (बाल जीवन बीमा)

8.17 डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी बीमा कवर प्रदान करते हैं। डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में

8.18 डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा पालिसियों को चालू रखने के लिए पिछली बार बोनस निम्न दरों पर घोषित किया गया था :-

तालिका 6 बोनस की दर			
प्रकार	प्रति 1000/-रुपये की बीमित राशि पर बोनस की दर (रुपये में)		
	आजीवन बीमा	बंदोबस्ती बीमा	प्रत्याशित बीमा
31.3.2004 की स्थिति के अनुसार डाक जीवन बीमा	90	70	65
31.3.2002 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण डाक जीवन बीमा	60	50	50

8.19 वर्ष 2005-2006 के दौरान डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के संबंध में निपटाए गए दावे इस प्रकार हैं:

तालिका 7 निपटाए गए दावे		
विवरण	डाक जीवन बीमा	ग्रामीण डाक जीवन बीमा
दावों की संख्या	110,532	14,608
भुगतान की गई राशि (मिलियन रु. में)	3,815.60	315.77

(v) 10 year RPLI (Gram Priya)

in PLI & RPLI is Rs. One Lakh and Rs.20,000/- respectively.

(vi) Children Policy (Bal Jivan Bima)

8.18 The bonus for continuing PLI and RPLI policies have been declared last at the following rates:

8.17 The PLI and RPLI also cover physically handicapped persons. The maximum limit of insurance

TABLE 6 RATE OF BONUS			
Plan	Rates of bonus per Rupees 1000/- sum assured		
	Whole Life Assurance	Endowment Assurance	Anticipated Assurance
PLI as on 31.03.2004	90	70	65
RPLI as on 31.03.2002	60	50	50

8.19 Details of claim under PLI and RPLI policies, settled during the year 2005-2006, are as given below: -

TABLE 7 CLAIMS SETTLED		
Details	PLI	RPLI
No. of Claims	110,532	14,608
Amount Paid (Rs. in Million)	3815.60	315.77

अध्याय 9

वित्तीय प्रबंधन

परिचय

9.1 डाक विभाग डाकघरों के एक बड़े राष्ट्रव्यापी नेटवर्क द्वारा जनता को डाक सेवाएं उपलब्ध कराता है। सम्पूर्ण डाक सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त डाकघर भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संगठनों की ओर से बचत बैंक, पेंशन का भुगतान, नकद पत्रों की बिक्री आदि जैसी एजेन्सी कार्य भी करते हैं।

9.2 वर्ष 2005-06 के दौरान बचत बैंक और बचत पत्र कार्य के पारिश्रमिक सहित कुल अर्जित राजस्व 50,234.88 मिलियन रुपए था और अन्य मंत्रालयों/विभागों से एजेन्सी प्रभार के रूप

में प्राप्त हुई राशि 1,957.80 मिलियन रु. थी। पिछले वर्ष में 59,645.37 मिलियन रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 2005-06 में कुल कार्यकारी-व्यय 64,291.52 मिलियन रुपये है (यानि लगभग 7.79% की वृद्धि)। व्यय में बढ़ोतरी मुख्य रूप से बढ़े हुए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत तथा पेंशनरी प्रभार आदि के भुगतान के कारण हुई है। वेतन और पेंशनरी प्रभार में हुई वृद्धि के बावजूद विभाग का घाटा 12098.84 मिलियन रुपये पर स्थिर बना रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.44% कम है।

Chapter 9

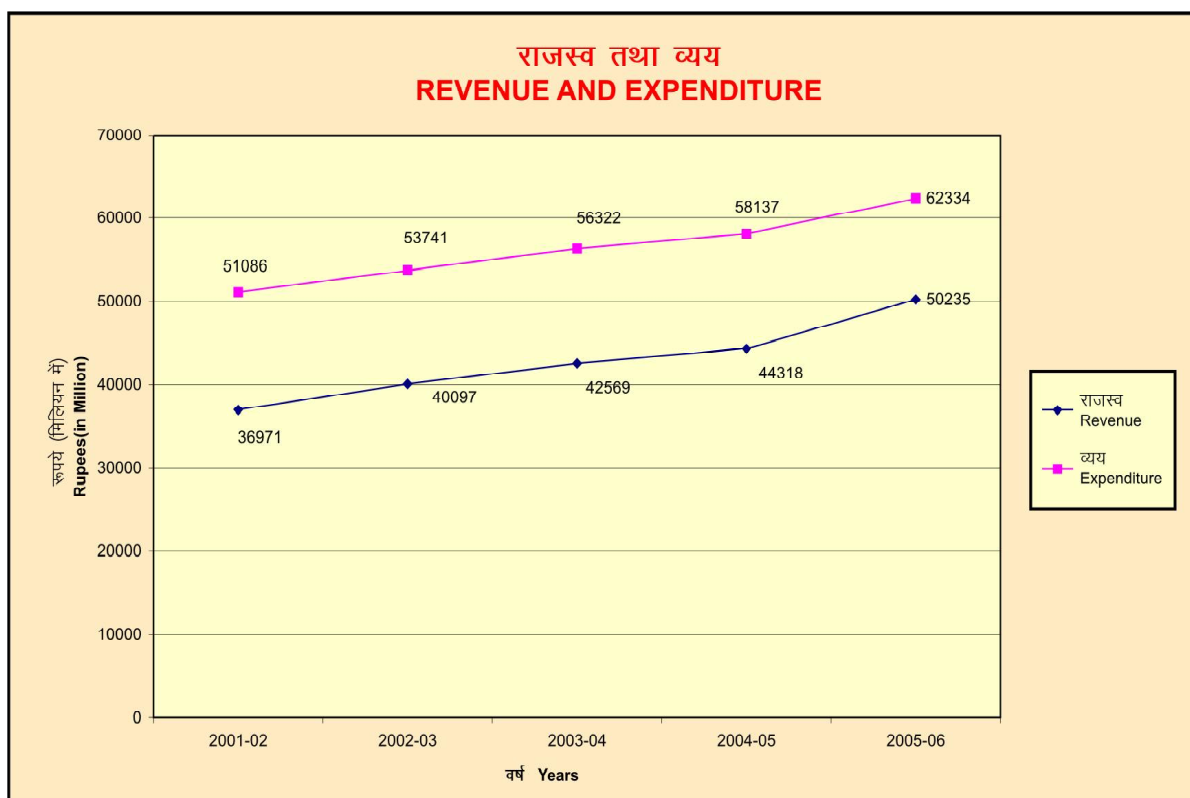
FINANCIAL MANAGEMENT

Introduction

9.1 The Department of Post provides postal services to the public through a large nation-wide network of Post Offices. Besides providing purely postal services, Post Offices perform agency functions like Savings Bank, Payment of Pension, Sale of Cash Certificates, etc., on behalf of other Ministries/ Departments of the Government of India/other organisations.

9.2 The total revenue earned including remuneration for SB and SC work during the year 2005-06 was Rs. 50,234.88 Million and the amount received from other

Ministries/Departments as Agency charges was Rs. 1,957.80 Million. Gross working expenditure for the year 2005-06 was Rs. 64,291.52 Million against the previous year's expenditure of Rs. 59,645.37 Million (i.e. an increase of about 7.79%). The increase was mainly due to payment of Dearness Allowance/Dearness Relief and payment of Pensionary charges etc. Despite the increase in salaries and Pensionary charges, the deficit of the Department was pegged at Rs. 12098.84 Million, which was lower than the previous year by 12.44%.



तालिका-8
राजस्व और व्यय
(वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए)

(रुपये मिलियन में)

ब्यौरा	वास्तविक आंकड़े 2004-05	वास्तविक आंकड़े 2005-06	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ प्रतिशत कमी (-)
राजस्व			
डाक टिकटों की बिक्री	7,986.58	7,585.60	(-) 5.02
नकदी के रूप में प्राप्त डाक शुल्क	12,971.13	14,699.92	13.33
मनीआर्डर और भारतीय पोस्टल आर्डर आदि पर कमीशन	3,268.94	3,341.01	2.20
बचत बैंक/बचत पत्र कार्य के लिए पारिश्रमिक	18,610.00	23,224.10	24.79
* अन्य प्राप्तियां	1,481.82	1,384.25	(-) 6.58
योग	44,318.47	50,234.88	13.35
व्यय			
सामान्य प्रशासन	3,448.69	3,690.91	7.02
प्रचालन	38,833.25	41,616.13	7.17
एजेंसी सेवाएं	2,042.15	2,187.94	7.14
**अन्य	15,321.28	16,796.54	9.63
कुल सकल व्यय	59,645.37	64,291.52	7.79
घटाएं वसूलियां	1,508.45	1,957.80	29.79
निवल व्यय	58,136.92	62,333.72	7.22
घाटा (निवल व्यय-राजस्व)	13,818.45	12,098.84	(-) 12.44

* इसमें डाक विभाग द्वारा बिक्री किए गए पासपोर्ट आवेदन फार्म, पासपोर्ट शुल्क टिकट एवं केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के सेवा प्रभार तथा अन्य डाक प्रशासनों आदि से हुई आय शामिल है।

** इसमें मजदूरी, कार्यालय व्यय, समयोपरि भत्ता, किराया एवं कर, व्यावसायिक सेवाएं, अनुरक्षण, स्टाफ को सुविधाएं, पेंशन प्रभार, आपूर्ति और सामग्री, मशीनरी एवं उपस्कर तथा अन्य प्रशासनिक व्यय आदि शामिल हैं।

TABLE 8
REVENUE AND EXPENDITURE
(FOR THE YEAR 2004-2005 & 2005-2006)

(Rs. in Million)

Particulars	Actuals 2004-05	Actuals 2005-06	% age Inc(+)/ Dec(-)over previous year
Revenue			
Sale of Stamps	7,986.58	7,585.60	(-) 5.02
Postage Realised in Cash	12,971.13	14,699.92	13.33
Commission on Money Orders and Indian Postal Orders etc.	3,268.94	3,341.01	2.20
Remuneration for Saving Bank/Saving Certificates Work	18,610.00	23,224.10	24.79
*Other Receipts	1,481.82	1,384.25	(-)6.58
Total	44,318.47	50,234.88	13.35
Expenditure			
General Administration	3,448.69	3,690.91	7.02
Operation	38,833.25	41,616.13	7.17
Agency Services	2,042.15	2,187.94	7.14
**Others	15,321.28	16,796.54	9.63
Total Gross Expenditure	59,645.37	64,291.52	7.79
Less Recoveries	1,508.45	1,957.80	29.79
Net Expenditure	58,136.92	62,333.72	7.22
Deficit (Net Expenditure-Revenue)	13,818.45	12,098.84	(-) 12.44

* This includes service charges retained by the Department of Posts from sale of Passport Application Form, Passport Fee Stamps, Central Recruitment Fee Stamps, receipts from other Postal Administrations etc.

** This includes Wages, Office Expenses, Overtime Allowance, Rent and Taxes, Professional Services, Maintenance, Amenities to Staff, Pension charges, Supplies and Material, Machinery and Equipment and Other Administrative Expenses, etc.

तालिका - 9

वर्ष 2004-05 और 2005-06 में एजेंसी सेवाओं पर कार्यकारी व्यय की वसूली

(मिलियन रुपये में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	2004-05 वास्तविक आंकड़े	2005-06 वास्तविक आंकड़े
1.	सैनिक पेंशन	10.74	0.00
2.	कोयला खनिकों तथा ईपीएफ/परिवार पेंशन तथा विविध सेवाओं का भुगतान	40.84	41.80
3.	रेलवे पेंशन का भुगतान	85.52	89.50
4.	डाक जीवन बीमा	1243.75	1432.00
5.	सीमा शुल्क वसूली	15.87	15.40
6.	महिला समृद्धि योजना	0.00	0.00
7.	अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण खातों पर कमीशन-वेस्टर्न यूनियन स्कीम	69.55	125.40
8.	संयुक्त डाक-तारघरों का टेलीग्राफ हिस्सा	10.39	3.40
9.	*अन्य	31.79	250.30
योग		1,508.45	1,957.80

* इसमें दिल्ली प्रशासन के गैर -डाक टिकटों की बिक्री पर कमीशन, सेना डाक सेवा लेखा और अन्य सरकारी विभागों से वसूलियां आदि शामिल हैं।

9.3 विभाग की आय 'वसूलियां' और 'राजस्व' के रूप में होती हैं। तालिका 9 में उल्लिखित 'वसूलियां' मद अन्य विभागों एवं संगठनों की ओर से किए गए एजेंसी कार्यों के लिए विभाग द्वारा अर्जित कमीशन की राशि का और 'राजस्व' डाक वस्तुओं की बिक्री, मनीआर्डर तथा भारतीय पोस्टल आर्डर पर कमीशन, अन्य प्रीमियम सेवाओं से प्राप्तियां, बचत बैंक तथा बचत पत्रों से प्राप्त पारिश्रमिक आदि का द्योतक है। कार्यकारी व्यय की तुलना में विभाग की आय कम है। अतः वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग का घाटा 12,098.84 मिलियन रु. था जो पिछले वर्ष के 13,818.45 मिलियन रु. के घाटे से कम है। इस प्रकार राजस्व प्राप्ति में हुई 13.35% की सराहनीय वृद्धि के कारण कार्यकारी व्यय में 7.22% की वृद्धि के बावजूद घाटे में

12.44% की कमी हुई। विभाग को जो घाटा हुआ है उसका मुख्य कारण सबसिडी का उच्च स्तर है जो विभाग विश्व सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए डाक नेटवर्क, विशेषकर ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में, पर वहन करता है।

9.4 वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान 'कार्यकारी व्यय' और 'पूंजीगत परिव्यय' के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का वर्ष के दौरान समुचित रूप से उपयोग कर लिया गया था। अधिशेष निधि को समय पर वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित कर दिया गया था। यह सराहनीय उपलब्धि प्रभावपूर्ण बजटीय नियंत्रण और व्यय की माहवार प्रगति की मानीटरिंग के कारण हासिल हो सकी।

TABLE-9
RECOVERY OF WORKING EXPENSES ON ACCOUNT OF AGENCY
SERVICES IN 2004-05 & 2005-06

(Rs. in Million)

Sl. No	Head of Account	2004-05 Actuals	2005-06 Actuals
1.	Military Pension	10.74	0.00
2.	Payment of Coal Miners and EPF/Family Pension & other Misc. Services	40.84	41.80
3.	Payment of Railway Pension	85.52	89.50
4.	Postal Life Insurance	1243.75	1432.00
5.	Custom Duty Realisation	15.87	15.40
6.	Mahila Samridhi Yojna	0.00	0.00
7.	Commission on A/c. of International Money Transfer – Western Union Scheme	69.55	125.40
8.	Telegraph share of Combined Offices	10.39	3.40
9.	*Others	31.79	250.30
	Total	1,508.45	1,957.80

* This includes Commission on sale of Non-Postal stamps of Delhi Administration, Recoveries from Army Postal Service Accounts and other Government Departments etc.

9.3 The earnings of the Department are in the form of 'Recoveries' and 'Revenue'. The item 'Recoveries' mentioned in Table 9 represents the amount of commission earned by the Department for Agency Functions done on behalf of other Departments and organisations and 'Revenue' is on account of sale of Postal Articles, commission on money orders and Indian Postal Orders, receipts from other premium services, remuneration for Savings Bank and Savings Certificates work etc. The earnings of the Department are on the lower side in comparison to the working expenses incurred. During the financial year 2005-06, the deficit of the Department was Rs. 12,098.84 Million, which is less than previous year's deficit of Rs. 13,818.45 Million.

Thus despite increase in Working Expenses of 7.22%, the deficit has been decreased by 12.44% due to appreciable increase in Revenue Receipts of 13.35%. Most of the deficit arises due to the high level of subsidy that is borne by the Department on the Postal network, particularly in rural and tribal areas, in order to fulfill the Universal Service Obligation.

9.4 The fund made available by the Ministry of Finance for 'Working Expenses' and 'Capital Outlay' during the year, was appropriately utilized. Surplus funds were surrendered in time to the Ministry of Finance. This appreciable achievement was made possible by effective budgetary control and monitoring the progress of expenditure on monthly basis.

तालिका -10
2005-2006 के दौरान अभ्यर्पित निधियां तथा बचत

(मिलियन रूपए में)

व्यय का स्वरूप	बजट प्राक्कलन	अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोजन	कुल वास्तविक व्यय	अधिक (+)/बचत (-)	अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित राशि	बचत	
3201 कार्यकारी-व्यय	62745.90	517.00	63262.90	64291.52	1028.62	0.00	1028.62
2552 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान	52.70	0.00	52.70	0.00	(-) 52.70	20.00	(-) 32.70
कुल कार्यकारी व्यय	62798.60	517.00	63315.60	64291.52	975.92	20.00	995.92
5201 पूंजीगत परिव्यय	3082.30	492.60	3574.90	2691.94	(-) 882.96	44.00	(-) 838.96
4552 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान	99.60	0.00	99.60	0.00	(-) 99.60	0.00	(-) 99.60
कुल पूंजीगत व्यय	3181.90	492.60	3674.50	2691.94	(-) 982.56	44.00	(-) 938.56
कुल कार्यकारी व्यय+ पूंजीगत व्यय	65980.50	1009.60	66990.10	66983.46	(-) 6.64	64.00	57.36

पूंजीगत परिव्यय

9.5 वर्ष 2005-2006 में नियत परिसम्पत्तियों पर 2,691.94 मिलियन रूपए का व्यय हुआ जिसमें से 7.04% भूमि और भवनों पर और 92.13% डाक सेवाओं के यांत्रिकीकरण और आधुनिकीकरण पर और 0.83% मेल मोटर वाहनों और अन्य पर हुआ। वर्ष के अंत में नियत परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत मूल्य बढ़कर 15,339.86 मिलियन रूपए हो गया। वर्ष के अंत

तक निवल प्रगामी नियत परिसम्पत्ति मूल्य 13,595.60 मिलियन रूपए हो गया।

सेवाओं की लागत

9.6 वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न डाक सेवाओं की औसत लागत एवं राजस्व निम्नलिखित तालिका-11 में दिए गए हैं :

TABLE 10
FUNDS SURRENDERED AND SAVINGS DURING 2005-06

(Rs. in Million)

Nature of Expenditure	Budget Estimate	Suppl. Grant/ Re-app.	Total	Actual Expd.	Excess(+)/ Saving(-)	Amount Surrendered/ Re-app.	Savings
3201 Working Exp	62745.90	517.00	63262.90	64291.52	1028.62	0.00	1028.62
2552 Prov. For the Development of North East Region	52.70	0.00	52.70	0.00	(-)52.70	20.00	(-)32.70
Total working Exp.	62798.60	517.00	63315.60	64291.52	975.92	20.00	995.92
5201 Capital Exp.	3082.30	492.60	3574.90	2691.94	(-)882.96	44.00	(-)838.96
4552 Prov. for the Development of North East Region	99.60	0.00	99.60	0.00	(-)99.60	0.00	(-)99.60
Total Capital Exp.	3181.90	492.60	3674.50	2691.94	(-)982.56	44.00	(-)938.56
Total Working Exp. + Capital Exp.	65980.50	1009.60	66990.10	66983.46	(-)6.64	64.00	57.36

Capital Outlay

9.5 The expenditure on fixed assets in the year 2005-06 was Rs. 2,691.94 Million, of which 7.04% was on Land and Buildings, 92.13% on Mechanization and Modernisation of Postal Services and 0.83% on Mail Motor Vehicles and others. The value of Gross Capital

on fixed assets rose to Rs.15,339.86 Million at the end of the year. The net progressive fixed asset value upto the end of the year was Rs. 13,595.60 Million.

Cost of Services

9.6 The average cost and revenue of various postal services during 2003-04 is given in Table-11 below:

तालिका 11
सेवाओं की लागत

(रूपयों में)

क्र.सं.	सेवा का नाम	2003-2004 (वास्तविक)	
		औसत लागत	औसत राजस्व
1.	पोस्टकार्ड	6.89	0.50
2.	मुद्रित पोस्टकार्ड	6.92	6.00
3.	प्रतियोगिता पोस्टकार्ड	4.80	10.00
4.	पत्र कार्ड (अंतर्देशीय पत्र)	7.02	2.50
5.	पत्र	7.96	10.04
6.	पंजीकृत समाचार पत्र -एकल	9.34	0.39
7.	पंजीकृत समाचार पत्र - बंडल	15.89	0.79
8.	बुक पोस्ट -बुक पैटर्न एवं सैम्पल पैकेट	11.35	7.27
9.	बुक पोस्ट - मुद्रित पुस्तकें	19.06	4.37
10.	बुक पोस्ट - अन्य पत्रिकाएं	18.07	9.44
11.	पावती	6.18	3.00
12.	पार्सल	80.94	57.17
13.	पंजीकरण	32.90	17.00
14.	स्पीड पोस्ट	44.54	36.08
15.	मूल्यदेय डाक	21.09	4.07
16.	बीमा	42.78	53.21
17.	मनीआर्डर	53.20	27.39
18.	तार मनीआर्डर	68.55	29.39
19.	भारतीय पोस्टल आर्डर	21.42	2.18
20.	विदेश डाक	23.71	35.56

Table 11
COST OF SERVICES

(in Rs.)

Sl. No.	Name of Service	2003-04 (Actual)	
		Average Cost	Average Revenue
1	Postcard	6.89	0.50
2	Printed Postcard	6.92	6.00
3	Competition Postcard	4.80	10.00
4	Letter Card (Inland)	7.02	2.50
5	Letter	7.96	10.04
6	Regd. Newspaper-Single	9.34	0.39
7	Regd. Newspaper-Bundle	15.89	0.79
8	Book Post - Book Pattern & S. Pkts.	11.35	7.27
9	Book Post-Printed Books	19.06	4.37
10	Book Post-Other Periodicals	18.07	9.44
11	Acknowledgement	6.18	3.00
12	Parcel	80.94	57.17
13	Registration	32.90	17.00
14	Speed Post	44.54	36.08
15	Value Payable Post	21.09	4.07
16	Insurance	42.78	53.21
17	Money Order	53.20	27.39
18	Telegraphic Money Order	68.55	29.39
19	Indian Postal Order	21.42	2.18
20	Foreign Mail	23.71	35.56

अध्याय 10

मानव संसाधन विकास

10.1 डाक विभाग एक अत्यन्त मानव संसाधन उन्मुख संगठन है। इसके 2,34,187 नियमित कर्मचारी और इसके अतिरिक्त 2,86,004 ग्रामीण डाक सेवक हैं जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। इतने विशाल मानव संसाधन को लगातार प्रशिक्षण देना जारी रखने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और जानकारी को अद्यतन करने के लिए विभाग के पास प्रशिक्षण का सुविकसित आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। डाक प्रचालनों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के प्रवेश, नए उत्पादों के विपणन के महत्व, नई वित्तीय सेवाएं शुरू करने एवं व्यवसाय विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसने प्रबंधक एवं प्रचालक तथा अन्य कर्मचारियों की दक्षता के निरंतर उन्नयन और उनका व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने के प्रयोजन से ऑन द जॉब और संस्थागत प्रशिक्षण, दोनों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है।

प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचा

10.2 निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान विभाग की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं

- गाजियाबाद पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत- समूह क और ख डाक सेवा अधिकारियों तथा लेखा सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए
- सहारनपुर, मैसूर, वडोदरा, दरभंगा, मदुरै और गुवाहाटी स्थित डाक प्रशिक्षण केन्द्र
- सर्किल/क्षेत्रीय मुख्यालय में 60 कार्य-स्थल कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (डब्ल्यूसीटीसी)
- स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत डाकियों, ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर्स और डाक वितरकों को कुछ विशेष डाक प्रचालनों पर डिवीजनल/सब डिवीजनल स्तर जैसे नोडल बिन्दुओं में एक सप्ताह से कम की लघु अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

- अधिकारियों को संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए नियमित रूप से विदेशों में भी भेजा जाता है जिनमें थाइलैण्ड में एशिया-प्रशांत पोस्टल कालेज, बैंकाक और भारत के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान जैसे प्रशासनिक स्टाफ कालेज भारत, हैदराबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय, बंगलौर, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे आदि शामिल हैं।

पोस्टल स्टाफ कालेज भारत

10.3 पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत, गाजियाबाद विभाग के प्रबंधकीय संवर्गों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शीर्ष प्रशिक्षण संस्था है। इस कालेज का मुख्य उद्देश्य प्रवेश तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण द्वारा भारतीय डाक सेवा और डाक सेवा समूह 'ख' के अधिकारियों में अपेक्षित ज्ञान, दक्षता और आचार-व्यवहार का विकास करना है ताकि वे डाक प्रणाली को अधिक कार्यकुशल और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बना सकें।

डाक प्रशिक्षण केन्द्र

10.4 कुल छह डाक प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनकी स्थापना डाक सर्किलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई।

10.5 क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य हैं:

- डाक निरीक्षकों और डाक सहायकों एवं छंटाई सहायकों को प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करना;
- डाक एवं छंटाई सहायकों, पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों, सहायक अधीक्षक डाकघर, पोस्टमास्टर्स आदि को सेवाकालीन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना; तथा
- विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर प्रणालियों को समझने, उनका प्रचालन करने के लिए अपेक्षित दक्षता और जानकारी प्रदान करना।

Chapter 10

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

10.1 The Department of Posts is a highly Human Resource intensive organization. It has 2,34,187 regular employees and in addition 2,86,004 Gramin Dak Sewaks who operate mostly in rural areas. To cater to the continued training of this vast human resource pool and to regularly update the skills, knowledge and awareness of the officers and staff, the Department has a well-developed training infrastructure. Priority is also being accorded to human resource development keeping in view the large scale induction of technology in postal operations, the thrust on marketing of new products, introduction of new financial services and business development activities. Extensive training programmes have been prepared for both on the job as well as institutional training, for the managers, operative and other functionaries for continually upgrading their skills and professional competence.

Training Infrastructure

10.2 The following training institutes take care of the training needs of the Department:-

- Postal Staff College India at Ghaziabad (PSCI) for training Group 'A' and 'B' Postal Service officers and officers from the Accounts Service.
- Postal Training Centres (PTCs) at Saharanpur, Mysore, Vadodara, Darbhanga, Madurai and Guwahati.
- 60 Workplace Computer Training Centres (WCTCs) at the Headquarter of Circles/Regions.
- Local training programmes, whereby short duration training of less than one week on selected Postal Operations is organized at nodal points like Divisional/Sub-divisional level to Postmen, Gramin Dak Sewak Branch Postmasters and Mail Deliverers.

- Officers are also regularly sent to relevant training courses abroad including Asian-Pacific Postal College, Bangkok in Thailand and Training Institutes of repute in India like Administrative Staff College India, Hyderabad, Indian Institutes of Management, National Law School University Bangalore, National Institute of Bank Management, Pune, etc.

Postal Staff College India

10.3 The Postal Staff College India, Ghaziabad, is the apex training institution catering to the training needs of the managerial cadres of the Department. The primary objective of the College is to impart induction as well as in-service training to the officers of the Indian Postal Service and Postal Service Group "B", with a view to inculcate requisite knowledge, soft skills and attitude to enable them to manage the postal system effectively and be responsive to customers' needs.

Postal Training Centres

10.4 The six Postal Training Centres have been established taking into account the requirement of the Postal Circles.

10.5 The main objectives of the Regional Postal Training Centres are: -

- To impart induction training to Inspectors of Posts and Postal & Sorting Assistants;
- To impart in-service and refresher training to Postal and Sorting Assistants, Supervisors, Inspector of Posts, Assistant Superintendent of Posts, Postmasters, etc; and
- To impart the skills and knowledge required for understanding and operating computer hardware and software systems relevant to the needs of the Department.

10.6 वर्ष 2005-2006 के दौरान पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत, छह डाक प्रशिक्षण केन्द्रों और कार्यस्थल कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया :-

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	डाक प्रशिक्षण संस्थाएँ			
		पोस्टल स्टाफ कालेज	डाक प्रशिक्षण केन्द्र	कार्यस्थल प्रशिक्षण केन्द्र/ नोडल बिन्दु	कुल
1.	प्रवेश प्रशिक्षण	157	2,188	-	2,345
2.	सेवाकालीन प्रशिक्षण	307	7,316	-	7,632
3.	जीडीएसबीपीएम वितरण स्टाफ आदि को सेवाकालीन प्रशिक्षण	-	-	55,010	55,010
4.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	426	13,079	25,415	38,920
5.	विदेशों के अधिकारियों / स्टाफ को प्रशिक्षण	-	15	-	15
6.	विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए अधिकारी	14	-	-	14
योग		904	22,598	80,425	1,03,927
प्रशिक्षित महिला अधिकारियों/ स्टाफ की कुल संख्या		51	2,480	-	2,531

10.6 During the year 2005-06, the Postal Staff College India, six Postal Training Centres and the Workplace Computer Training Centres have trained the following number of officers/staff: -

S. No.	Training Activity	Postal Training Institutions			
		Postal Staff College	Postal Training Centres	Workplace Training Centres/ Nodal points	Total
1	Induction Training	157	2,188	-	2,345
2	In-service Training	307	7,316	-	7,623
3	In-service Training to GDSBPMs, Delivery Staff, etc.	-	-	55,010	55,010
4	Computer Training	426	13,079	25,415	38,920
5	Training of officers/staff of foreign countries	-	15	-	15
6	Officers sent for training abroad	14	-	-	14
Total		904	22,598	80,425	1,03,927
Total Number of women officers/staff trained		51	2,480	-	2,531

अध्याय 11

सतर्कता कार्यकलाप

11.1 डाक विभाग में कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा और सेवाओं में कार्यकुशलता बनाए रखने के उद्देश्य से सचिव, डाक विभाग की अध्यक्षता में नई दिल्ली मुख्यालय में एक पूर्ण विकसित सतर्कता स्थापना है। सचिव, डाक विभाग की सहायता के लिए उप महानिदेशक (सतर्कता) है जो कि विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता संबंधी सभी मामलों में सचिव के विशेष सहायक के रूप में कार्य करते हैं और डाक विभाग तथा मुख्य सतर्कता आयोग के बीच कड़ी का काम करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता के लिए मुख्यालय में निदेशक (सतर्कता), तीन सहायक महानिदेशक और एक डेस्क अधिकारी हैं। इसके अलावा हानि और धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने, राजस्व की चोरी का पता लगाने तथा अन्य प्रकार के अनाचारों की जांच के लिए मुख्यालय में एक जांच प्रभाग और केन्द्रीय जांच दल है।

11.2 सर्किल, क्षेत्रीय और डिविजनल स्तर पर सतर्कता संबंधी कार्य इनके प्रमुख यानि प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल और डिविजनल अध्यक्ष द्वारा अपने समग्र कार्यों और उत्तरदायित्वों के ही एक भाग के रूप में किए जाते हैं।

11.3 मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता मामलों को देखने के अलावा निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में संवेदनशील स्थानों का नियमित और अचानक निरीक्षण करने, ऐसी कार्यविधियों

की समीक्षा करने और उन्हें दोषरहित बनाने के लिए भी जिम्मेदार है जिनमें भ्रष्टाचार या कदाचार की आशंका हो। वे विभाग और इसके फील्ड कार्यालयों में भ्रष्टाचार और दूसरे प्रकार के अनाचारों की रोकथाम और इनका पता लगाने के लिए भी उत्तरदायी है।

11.4 विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ समय-समय पर बैठकें होती हैं और सी बी आई के साथ परामर्श करके संदेहास्पद अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है। इन संदेहास्पद अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। फील्ड यूनिटों के साथ परामर्श करके संदेहास्पद निष्ठा वाले अधिकारियों की एक सूची भी तैयार की गई है।

11.5 राजस्व की चोरी का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता दल द्वारा कार्यालय में अचानक निरीक्षण किया जाता है। कदाचार और राजस्व की चोरी रोकने के लिए आवश्यक उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। वर्ष के दौरान सतर्कता कार्यकलाप (सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय सहित) इस प्रकार रहे:-

- (i) ग्यारह अधिकारियों और 1023 अन्य कर्मचारियों को भारी दण्ड और 67 अधिकारियों और 6283 अन्य कर्मचारियों को साधारण दण्ड दिया गया।
- (ii) अट्टाइस (28) मामलों की जांच हुई और उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया।

Chapter 11

VIGILANCE ACTIVITIES

11.1 In order to maintain integrity of the officials and efficiency in services, the Department of Posts has in place a full-fledged vigilance set up at its headquarters at New Delhi headed by the Secretary (Post) who is assisted by the Deputy Director General (Vigilance), who is the Chief Vigilance Officer (CVO) of the Department. The CVO acts as the Special Assistant to the Secretary in all matters pertaining to vigilance and provides a link between the Department of Posts and the Central Vigilance Commission (CVC). The CVO is assisted by a Director (Vigilance), three Assistant Directors General and one Desk Officer at the Headquarter. Besides, there is also an Investigation Wing and a Central Checking Squad for investigation into loss and fraud cases, checking of leakage of revenue and other malpractices.

11.2 At the Circle, Regional and Divisional levels, vigilance related functions are discharged by heads of these formations, viz. Principal Chief Postmaster General/Chief Postmaster General, Regional Postmaster General and Divisional Heads, as part of their overall duties and responsibilities.

11.3 Besides, dealing with vigilance cases, as a part of preventive vigilance the CVO arranges regular and

surprise inspections of sensitive spots, review and streamlining of procedures, which appear to afford scope for corruption or misconduct, initiate measures for prevention, detection of corruption and other malpractices in the Department and its field offices.

11.4 Periodical meetings with CBI at various levels are held and Agreed Lists of suspected officers drawn up in consultation with CBI. Close watch is kept on the listed officers. List of Officers of doubtful integrity has also been prepared in consultation with the field units.

11.5 Surprise visits are carried out in offices through the Central Checking Squad to detect leakage of revenue. Appropriate action is taken to prevent malpractices and leakage of revenue. Vigilance activities during the year (including attached and subordinate office) were as follows: -

- (i). Eleven Officers and 1023 other staff were awarded major penalty while 67 Officers and 6283 other staff were awarded minor penalty.
- (ii). Twenty-eight cases were examined and referred to CVC.

अध्याय 12

महिलाओं से संबंधित मुद्दे

12.1 31.3.2006 को विभाग में कुल 2,34,187 विभागीय कर्मचारी थे जिसमें विभिन्न ग्रेडों में 31,493 महिला कर्मचारी शामिल हैं (देखें तालिका 17)। डाक विभाग के सभी प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं को पूरा महत्व दिया जाता है। विभाग में महिलाएं प्रचालक से लेकर नीति और निर्णय लेने के स्तरों पर कार्यरत हैं। वे सभी दायित्वों का समान रूप से निर्वहन करती हैं, चाहे यह कार्यालय में बैठकर हो या इसके बाहर काम कर।

12.2 लैंगिक समानता, समता और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का सिद्धांत डाक विभाग के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनने और उन्नतिशील एवं सहयोगपूर्ण परिवेश सुनिश्चित करने के

लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे वे अपने घर और कार्य की जिम्मेदारियों में संतुलन रखने में सक्षम हो पाएंगी। इसमें महिला कर्मचारियों के लिए अलग से आराम कक्षों और मनोविनोद कक्षों की व्यवस्था करना और जहां संभव हो, शिशुसदनों की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

12.3 महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निदेशालय में एक समिति स्थापित की गई है। समिति की अध्यक्ष निदेशक रैंक की एक महिला अधिकारी हैं। इसमें चार सदस्य हैं। फील्ड में भी डिवीजन स्तर पर समान प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई है। वर्ष के दौरान समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

Chapter 12

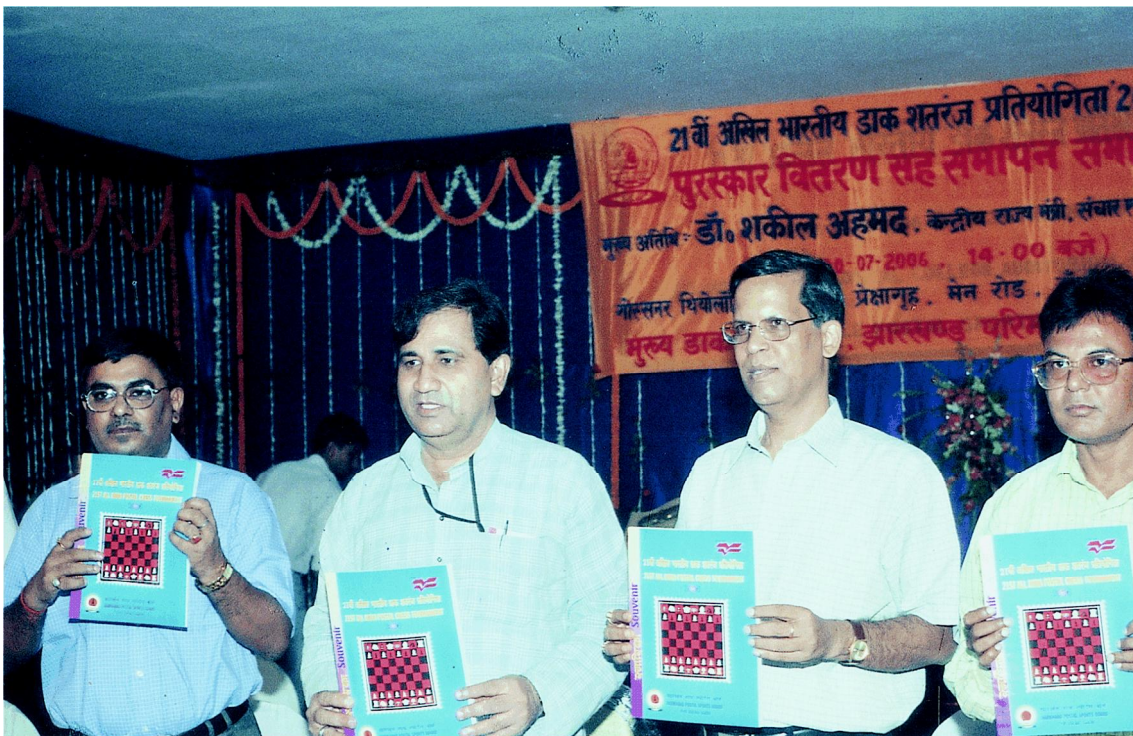
GENDER ISSUES

12.1 On 31.03.2006 there were 2,34,187 departmental employees, which includes 31,493 women employees in various grades in the Department (see Table 17). Gender sensitization modules have been included in all Induction and In-service Training programmes of the Department of Posts. Women hold positions at all levels in the Department ranging from operative to policy and decision-making levels. They partake equally in all responsibilities, be it office based or outdoor.

12.2 The principles of gender equality, equity and protection of the rights of women are a matter of prime concern of the Department of Posts. Every effort is being made to be sensitive to their needs and ensure a

thriving and supportive environment, which will enable them to balance their responsibilities at work with those at home. This includes providing separate rest rooms and recreation rooms for women employees and providing crèche facilities, where possible.

12.3 To look into the matter of prevention of sexual harassment of women a committee chaired by a lady officer of the rank of Director has been set up in the Directorate with four other members. Similar bodies have been set up at every level up to the Division level in the field. The Committee has not received any complaint during the year.



डा. शकील अहमद, माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री रांची, झारखण्ड में 21वीं अखिल भारतीय डाक शतरंज प्रतियोगिता 2006 के समापन समारोह के अवसर पर स्मारिका जारी करते हुए।

Release of Souvenir by Dr. Shakeel Ahmad, Hon'ble Minister of State for Communications & IT at Ranchi, Jharkhand on the closing ceremony of 21st All India Postal Chess Championship 2006.

अध्याय 13 निशक्तता क्षेत्र

13.1 डाक विभाग द्वारा निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित स्कीमों/नीतियां प्रारंभ की गई हैं।

- (i) जो डाक कर्मचारी 13, 100 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन ले रहे हैं, उनके शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से विक्षिप्त/नेत्रहीन/ मूक एवं बधिर बच्चे 'डाक कल्याण निधि से डाक कर्मचारियों के बच्चों के सहायतार्थ शैक्षिक सहायता का अनुदान' स्कीम के अंतर्गत 45/-रुपये प्रतिमाह की वार्षिक छात्रवृत्ति पाने के हकदार हैं। छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षिक स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की 3% निधि विकलांग बच्चों के लिए निर्दिष्ट है। अब तक निशक्तता से ग्रस्त 59 व्यक्तियों को छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ दिया गया है।
- (ii) अस्थिजन्य रोगों से ग्रस्त विकलांग कर्मचारी कल्याण निधि से निम्नलिखित सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
 - (क) विकलांग कर्मचारी द्वारा मशीनचालित तिपहिया साइकिल के क्रय पर किए व्यय की प्रतिपूर्ति बशर्ते कि वह अधिकतम 2000/- रुपये हो।
 - (ख) मोटरचालित तिपहिया साइकिल के क्रय पर सर्किल कल्याण निधि से 15000/-रुपये की राशि अथवा

मोटरचालित तिपहिया साइकिल की लागत का 50% जो भी कम हो। यदि संबंधित कर्मचारी स्कूटर अग्रिम के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे मामले में सहानुभूतिपूर्वक प्राथमिकता देकर उस पर विचार किया जाता है।

- (ग) अस्थिजन्य रोग से ग्रस्त विकलांग कर्मचारी केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर) नियमावली के अंतर्गत व्हील चेयर की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
- (iii) प्रथम से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले शारीरिक विकलांग/ मानसिक रूप से विक्षिप्त/नेत्रहीन मूल-बधिर बच्चों को परिवहन प्रभार तथा छात्रावास/ मेस सबसिडी (परिवहन प्रभार के स्थान पर) दी जाएगी। श्रेणी 'क' शहरों में यह दर इस समय 50 रु. प्रति माह और श्रेणी 'ख' शहरों में 40 रुपये प्रति माह है।
- (iv) 5 कि.ग्रा. तक के भार वाले अन्ध साहित्य पैकेट डाक विभाग द्वारा निःशुल्क भेजे जाते हैं।

13.2 1996 से डाक निदेशालय में ग्रेड 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में 540 रिक्त पद भरे गए जिसमें से 17 रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरी गईं।

Chapter 13

DISABILITY SECTOR

13.1 The following Schemes/Policies have been taken up by the Department of Posts for the benefit of Persons with disabilities as a follow-up action for implementation of the Persons with Disability Act, 1995 (PWD Act).

- (i) Physically handicapped/mentally retarded/blind/deaf and dumb children of Postal employees drawing pay up to Rs. 13,100 p.m. are eligible to get annual Scholarship of Rs. 45 p.m. under the scheme of 'Grant of Educational Assistance to the children of Postal Employees from the Postal Welfare Fund'. 3% funds are earmarked for scholarship of handicapped children out of the available funds under scholarships and other educational schemes. So far fifty-nine persons with disability have been benefited under the scholarship scheme.
- (ii) Orthopaedically handicapped employees are eligible to get following financial assistance from the Welfare Fund.
 - (a) Full reimbursement of expenditure incurred by a handicapped employee for purchase of mechanized tri-cycle subject to a maximum of Rs. 2,000.
 - (b) For Purchase of motorized tri-cycle an amount of Rs. 15,000 from the Circle Welfare Fund or 50% of the cost of the motorized tri-cycle, whichever is less. Grant of scooter advance in such cases is considered sympathetically on priority basis in case the concerned employee applies for the same.
 - (c) Orthopaedically handicapped employees are entitled to get reimbursement of the cost of Wheel Chair under the Central Services (Medical Attendance) Rules.
- (iii) Grant of Transport Charges and Hostel/Mess Subsidy (in lieu of Transport Charges) to handicapped/mentally retarded/blind/deaf and dumb children studying in 1st to 12th standard. The existing rates for this are Rs. 50 p.m. in class 'A' cities and Rs. 40 p.m. in class 'B' cities.
- (iv) Blind Literature Packets weighing up to 5 Kg is transmitted by post free of cost by the Department of Posts.

13.2 Since 1996, out of 540 vacancies filled in the Postal Department in various posts in Grade A, B, C and D, 17 vacancies were filled by persons with disability as per the instructions of Department of Personnel and Training.

अध्याय 14

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलाप

14.1 भारतीय डाक ने, सरकार के नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों के लिए विशेष पहल की है।

14.2 पहले पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल एक डाक सर्किल द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाती थी। तथापि, इस क्षेत्र के सामरिक महत्व पर विचार करते हुए एवं विकासात्मक कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से तत्कालीन सर्किल को दो स्वतंत्र डाक सर्किलों में विभाजित कर दिया गया। इसमें एक असम सर्किल है जो असम राज्य के साथ कोटर्मिनस है तथा दूसरा पूर्वोत्तर डाक सर्किल है, जिसमें छः राज्य-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम का कुछ भाग आते हैं। हर सर्किल मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

14.3 असम डाक सर्किल में 4,006 डाकघर हैं, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। प्रत्येक डाकघर औसतन 6654 की जनसंख्या को तथा 19.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है। पूर्वोत्तर डाक सर्किल का मुख्यालय शिलांग में है और इसके अधिकार क्षेत्र में कुल 2,933 डाकघर हैं। प्रत्येक डाकघर औसतन क्रमशः 60.33 वर्ग किलोमीटर और 4,051 की जनसंख्या को सेवा उपलब्ध कराता है।

योजना कार्यकलाप

14.4 पिछले वर्षों में शुरु किए गए विकासात्मक कार्यक्रमों को दसवीं योजना के दौरान जारी रखा गया। पिछले चार वर्षों के दौरान समूचे देश भर में योजना कार्यकलापों पर किए गए कुल व्यय के दृष्टिगत पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया व्यय निम्नवत है:

तालिका 12 पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजनागत व्यय (मिलियन रु. में)			
वार्षिक योजना	अखिल भारतीय*	पूर्वोत्तर में व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2002-03	459.10	25.30	5.51%
2003-04	633.04	39.13	6.18%
2004-05	1421.60	42.40	2.98%
2005-06	3011.11	48.20	1.60%

*इसमें उन कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय शामिल है जिसका प्रभाव पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश में एक समान पड़ेगा।

14.5 मानव संसाधन विकास हेतु प्रौद्योगिकी के समावेश से उत्पन्न आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राहकोनुकूल सेवाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विवरण नीचे दिया गया है:-

Chapter 14

DEVELOPMENT ACTIVITIES IN NORTH-EASTERN REGION

14.1 India Post has taken up special initiatives for developmental activities in the North-Eastern Region, in accordance with the policy guidelines of the Government.

14.2 The North Eastern Region was previously served only by one Postal Circle. However, considering the strategic importance of the region, and to ensure focussed attention on developmental activities, the erstwhile Circle was bifurcated into two independent Postal Circles namely – Assam Circle, co-terminus with the State of Assam, and the North-Eastern Postal Circle, covering the six states namely Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and some part of Sikkim. Each Circle is under the administrative control of a Chief Postmaster General.

14.3 Assam Postal Circle, with its headquarters at Guwahati, has a network of 4,006 Post Offices. On an average, each Post Office serves a population of 6,654 persons and an area of 19.58 Sq. Kms. North Eastern Postal Circle has its headquarters at Shillong. It has within its jurisdiction a total of 2,933 Post Offices. On an average, each Post Office serves an area and population of 60.33 Sq. Kms. and 4051 persons respectively.

Plan Activities

14.4 The developmental programmes initiated in previous years were continued in the Tenth Plan. The expenditure in the North-Eastern region for specifically identified schemes vis-a-vis the total expenditure on plan activities throughout the country during the last four years is given below: -

Table 12			
PLAN EXPENDITURE IN NORTH EASTERN REGION			
(Rs. in Million)			
Annual Plan	All India*	Expenditure in North-East	% age over total expenditure
2002-03	459.10	25.30	5.51%
2003-04	633.04	39.13	6.18%
2004-05	1421.60	42.40	2.98%
2005-06	3011.11	48.20	1.60%

* This includes expenditure on programmes that would impact uniformly across the country, including the North-Eastern Region.

14.5 In order to develop human resources, in line with emerging needs of technology induction and provision of customer centric services, officials in the North Eastern Region were imparted training in various fields. The details are as given below:

तालिका 13

क्र.सं.	राज्य	समूह 'क' और 'ख' कर्मचारियों को प्रशिक्षण	समूह 'ग' कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण	कंप्यूटर प्रशिक्षण	डाकिए के लिए प्रशिक्षण
1.	असम	9	233	168	399
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	24	25	153
3.	मणिपुर	-	27	66	152
4.	मेघालय	-	27	130	202
5.	मिजोरम	-	17	21	51
6.	नागालैंड	-	25	15	99
7.	त्रिपुरा	-	50	116	302

14.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में 2005-2006 के दौरान की गई अन्य मुख्य विकास गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

असम

14.7 वर्ष के दौरान 21 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालय, 152 डाकघर, 9 प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया और 4 डाकघर एवं 6 स्पीड पोस्ट केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया गया। 8 स्पीड पोस्ट एकत्रीकरण केन्द्रों का स्पीड नेट से उन्नयन किया गया, 100 ईडीबीओ को आधारभूत सुविधाओं संबंधी उपस्कर उपलब्ध कराए गए तथा 4 कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। डाक के पारेषण के लिए तिपहिया वाहन प्रदान किए गए। तीन फिलैटलिक प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं और 10 फिलैटलिक यूनिटों को उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराए गए।

अरुणाचल प्रदेश

14.8 वर्ष के दौरान, 4 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालय, 3 डाकघर, एक प्रशासनिक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया तथा एक डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया। एक स्पीड पोस्ट केन्द्र व्यवसाय विस्तार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। एक स्पीड पोस्ट केन्द्र का स्पीड पोस्ट सुविधाओं

के विकास के लिए स्पीड नेट पर 'ट्रैक एवं ट्रेस' से उन्नयन किया गया। एक फिलैटलिक यूनिट में उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध कराए गए तथा दो फिलैटलिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

मणिपुर

14.9 वर्ष के दौरान, 9 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालय, 7 डाकघर एवं एक प्रशासनिक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया। स्पीड पोस्ट सुविधाओं के विकास के लिए तीन स्पीड पोस्ट केन्द्रों का स्पीड नेट पर 'ट्रैक एवं ट्रेस' प्रणाली से उन्नयन किया गया। 52 ईडीबीओ को आधारभूत सुविधा संबंधी उपस्कर उपलब्ध कराए गए तथा एक डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त एक फिलैटलिक यूनिट को उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति की गई, दो फिलैटलिक कार्यशालाएं तथा एक फिलैटलिक प्रदर्शनी भी आयोजित की गईं। राज्य में एक डाक मार्ट स्थापित किया गया है। मेल वितरण के लिए एक मेल मोटर वाहन उपलब्ध कराया गया है तथा एक डाकघर भवन का निर्माण किया गया है।

मेघालय

14.10 वर्ष के दौरान, 1 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालय, 15 डाकघर, एक प्रशासनिक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया

Table 13

S. No.	State	Training to Group 'A' & 'B' officials	In-Service Training to Group 'C' Officials	Computer Training	Training For Postman
1.	Assam	9	233	168	399
2.	Arunchal Pradesh	-	24	25	153
3.	Manipur	-	27	66	152
4.	Meghalaya	-	27	130	202
5.	Mizoram	-	17	21	51
6.	Nagaland	-	25	15	99
7.	Tripura	-	50	116	302

14.6 The other major developmental activities undertaken during 2005-06 in the North Eastern States are given below:-

Assam

14.7 During the year 21 Speed Post booking/delivery offices, 152 Post Offices, 9 Administrative Offices were computerized and 4 Post Offices, 6 Speed Post Centres were modernised. 8 Speed Post Concentration Centres(SPCC) were upgraded with Speed Net, 10 EDBOs were provided with Infrastructural equipments and 4 Computerised Registration Centres have also been established. Three vehicles have been provided for transmission of mails. Three Philatelic Exhibitions were held and 10 Philatelic Units were provided with tools and equipments.

Arunachal Pradesh

14.8 During the year, 4 Speed Post booking/delivery offices, 3 Post Offices, One Administrative Office were computerized and one Post Office has been modernized. One Speed Post Centre has been provided under the Business Expansion Programme. One Speed Post Centre

was upgraded with Track and Trace on Speed Net to promote Speed Post facilities. One Philatelic Unit was provided with tools and equipments and two philatelic workshops were held.

Manipur

14.9 During the year, 9 Speed Post booking/delivery offices, 7 Post Offices and one Administrative Office were computerized. Three Speed Post Centres were upgraded with Track and Trace on Speed Net to promote Speed Post facilities. 52 EDBOs were provided with Infrastructural equipments. One post office was modernised. Further, one Philatelic Unit was supplied with tools and equipments, two philatelic workshops and one philatelic exhibition were held. One Postal Finance Mart has been set up in the State. One mail motor vehicle has been provided for delivery of mails and a post office building has been constructed.

Meghalaya

14.10 During the year, one Speed Post booking/delivery office, 15 Post Offices, One Administrative Office were computerized and 2 post offices were modernized.

गया। दो डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त 13 फिलैटलिक यूनिटों को उपकरण एवं उपस्करों की आपूर्ति की गई, 4 फिलैटलिक प्रदर्शनियां तथा 42 फिलैटलिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं। एक डाक वित्त मार्ट स्थापित किया गया। मेल वितरण के लिए राज्य में 3 दुपहिया और 2 तिपहिया वाहन उपलब्ध कराए गए।

मिजोरम

14.11 वर्ष के दौरान, 2 स्पीड पोस्ट केन्द्र, 4 डाकघर, एक प्रशासनिक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया तथा एक स्पीड पोस्ट केन्द्र का स्पीड नेट पर ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली से उन्नयन किया गया। 52 ईडीबीओ की उपकरण एवं उपस्कर से आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त एक फिलैटलिक प्रदर्शनी एवं तीन फिलैटलिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं। राज्य में एक डाक वित्त मार्ट स्थापित किया गया। डाक वितरण के लिए एक मेल मोटर वाहन उपलब्ध कराया गया है।

नागालैंड

14.12 वर्ष के दौरान, 5 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालय तथा एक प्रशासनिक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया जबकि एक डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त एक फिलैटलिक यूनिट को उपकरण एवं उपस्कर

उपलब्ध कराए गए तथा 4 फिलैटलिक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। राज्य में एक डाक वित्त मार्ट स्थापित किया गया। डाक वितरण के लिए एक मेल मोटर वाहन उपलब्ध कराया गया।

त्रिपुरा

14.13 वर्ष के दौरान 1 स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालय, 25 डाकघर तथा दो प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया जबकि दो डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया तथा 4 स्पीड पोस्ट केन्द्रों का स्पीड पोस्ट व्यवसाय के विकास के लिए ट्रेक और ट्रेस प्रणाली से उन्नयन किया गया। इसके अतिरिक्त दो फिलैटलिक यूनिटों को उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति की गई, 2 फिलैटलिक प्रदर्शनियां तथा 4 फिलैटलिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं। राज्य में दो डाक वित्तीय मार्ट स्थापित किए गए।

सिक्किम

14.14 वर्ष के दौरान 6 डाकघर तथा एक प्रशासनिक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया। एक डाकघर तथा तीन स्पीड पोस्ट केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया गया। स्पीड पोस्ट सुविधाओं के विकास के लिए 2 स्पीड पोस्ट केन्द्रों का स्पीड नेट से ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली द्वारा उन्नयन किया गया। 15 फिलैटलिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं। 5 ईडीबीओ को आधारभूत सुविधाओं वाले उपस्कर उपलब्ध कराए गए।

Further, 13 Philatelic units were supplied with tools and equipments, 4 philatelic exhibitions and 42 philatelic workshops were held. One Postal Finance Mart was set up in the State. 3 two wheelers and 2 three wheelers were provided during the year for delivery of mails.

Mizoram

14.11 During the year, 2 Speed post centers, 4 Post Offices, one Administrative Office were computerized and one Speed Post Centre was upgraded with Track and Trace on Speed Net to promote Speed Post business. 52 EDBOs were supplied with tools and equipments. Further, one philatelic exhibition and three philatelic workshops were held. One Postal Finance Mart was set up in the State. One mail motor vehicle has been provided for delivery of mails.

Nagaland

14.12 During the year, 5 Speed Post booking/delivery offices and one Administrative Offices were computerized, while one post office was modernised. Further, one Philatelic unit was supplied with tools &

equipments and 4 philatelic workshops were held. One Postal Finance Mart was set up in the State. One mail motor vehicle has been provided for delivery of mails.

Tripura

14.13 During the year, one Speed Post booking/delivery Office, 25 Post Offices and two Administrative Offices were computerized, while two post offices were modernized and 4 Speed Post Centres were upgraded with Track and Trace on Speed Net to promote Speed Post business. Further, 2 Philatelic units were supplied with tools & equipments, 2 philatelic exhibitions and 4 philatelic workshops were held. Two Postal Finance Marts were set up in the State.

Sikkim

14.14 During the year, 6 Post Offices and one Administrative office were computerized. One post office and 3 Speed Post Centres were modernized. 2 Speed Post Centres were upgraded with Track and Trace on Speed Net to promote Speed Post facilities. 15 philatelic workshops were held. 5 EDBOs were provided with Infrastructure Equipments.

अध्याय 15

अन्य कार्यकलाप

कर्मचारी संबंध

15.1 अवधि के दौरान विभाग ने अपने कर्मचारियों के परिसंघों और यूनियनों/संघों से आत्मीय और सार्थक संबंध बनाने का पूरा प्रयास किया। विभागीय परिषद (जेसीएम) की स्थायी समिति की बैठक 11 जुलाई, 2005 को सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें 18 नवम्बर, 2003 को आयोजित हुई विभागीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार किया गया। सचिव (डाक) ने 4 जनवरी, 2006 को, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी परिसंघ (एनएफपीई) तथा राष्ट्रीय डाक संगठन परिसंघ तथा उसकी सम्बद्ध यूनियनों के साथ आवधिक बैठक की। इसके अलावा सचिव (डाक) ने भारतीय डाक कर्मचारी परिसंघ तथा सम्बद्ध यूनियनों और गैर-परिसंघ यूनियनों के साथ एक अनौपचारिक बैठक 5 जनवरी, 2006 को आयोजित की। इन बैठकों का आयोजन कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए किया गया।

15.2 राष्ट्रीय डाक कर्मचारी परिसंघ (एनएफपीई), राष्ट्रीय डाक संगठन परिसंघ (एफएनपीओ) तथा भारतीय डाक कर्मचारी परिसंघ (बीपीईएफ) ने अपने मांग पत्र के साथ 15 मार्च, 2005 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए एक नोटिस दिया। 14.3.2005 को सदस्य (कार्मिक) डाक सेवा बोर्ड की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयी समिति का गठन किया गया जिसमें वित्त मंत्रालय (व्यय), कार्मिक विभाग, श्रम मंत्रालय तथा डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व किया तथा इसमें विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते का 50% विलय करने पर विचार किया गया। समिति ने 3 मई, 2005 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जिन्हें मंत्रिमंडल के अनुमोदन से पारित किया गया। अन्य सभी मुद्दों को भी सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सुलझाया गया, परिणामस्वरूप प्रस्तावित हड़ताल को रोका जा सका। महासचिव, भारतीय डाक कर्मचारी परिसंघ के अनुरोध पर मुख्य अभियंता (सिविल) ने 25 अगस्त, 2005 को बीपीईएफ के साथ एक बैठक की, जिसमें परिसंघ द्वारा बताए सभी लंबित

मुद्दों पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त उप महानिदेशक (पीएएफ) ने अखिल भारतीय डाक लेखा कर्मचारी एसोसिएशन के साथ 15 अप्रैल, 2005 को एक आवधिक बैठक का आयोजन किया जिसमें एसोसिएशन द्वारा उठाए मुद्दों पर विचार किया गया। सदस्य (प्रचालन तथा विपणन) की अध्यक्षता में, डाकियों तथा ग्रुप घड्ड कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले डाक परिसंघों तथा सेवा एसोसिएशनों के साथ एक बैठक का आयोजन 13 मई, 2005 को किया गया, जिसमें डाकियों द्वारा सामग्री एकत्रित करने के मुद्दे पर विचार किया गया।

15.3 जहां तक जन शिकायत निवारण कार्य का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि डाक विभाग में परिसंघों/यूनियनों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के रूप में पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। इसके अलावा, सरकारी कामकाज में अधिक खुलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग में हो रहे परिवर्तनों से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को विशेष बैठकों और मंत्रियों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों के दौरान अवगत कराया जाता है।

कर्मचारी कल्याण

15.4 डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड का उद्देश्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कल्याण, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलापों को आयोजित करना, बढ़ावा देना और विकसित करना है। बोर्ड को इसके लिए भारत की समेकित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान तथा खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों से धन एकत्र करने की व्यवस्था की जाती है।

15.5 कल्याण बोर्ड के कोषों का उपयोग खेलकूद, मनोरंजन क्लबों, बीमारी, मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करने, शैक्षणिक छात्रवृत्ति, पर्यटन यात्राओं के लिए सब्सिडी, विकलांग कर्मचारियों तथा उनके बच्चों की सहायता करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, क्रेशों (शिशुगृहों) आदि के

Chapter 15

OTHER ACTIVITIES

Staff Relation

15.1 During the period, the Department endeavored to maintain harmonious and meaningful relations with the Federations and Unions/Associations of its employees. A meeting of Standing Committee of Department Council (JCM) was held on 11th July, 2005. The meeting took place in a congenial atmosphere wherein the Action Taken Report on the decisions taken in the meeting of the Departmental Council held on 18th November, 2003 were discussed. Secretary (Posts) had a periodical meeting with the National Federation of Postal Employees and Federation of Postal Organisations along with their affiliated unions on 4th January, 2006. Further, an informal meeting of Secretary(P) with Bharatiya Postal Employees Federation and its affiliated unions and meetings with non-federated unions were held on 5th January, 2006. These meetings were granted to discuss various problems of staff.

15.2 A notice for indefinite strike w.e.f. 15th March, 2005 along with a Charter of Demands was served by National Federations of Postal Employees (NFPE), Federation of National Postal Organisations (FNPO) and Bharatiya Postal Employees Federations (BPEF). An inter-ministerial committee comprising of senior officers representing Ministry of Finance (Expenditure), Department of Personnel, Ministry of Labour and Department of Posts under the Chairmanship of the then Member (P), Postal Services Board was constituted on 14.3.2005 to consider grant of 50% merger of DA to Gramin Dak Sevaks of this Department. The Committee submitted its recommendations on 3rd May, 2005 which were given effect with the approval of the Cabinet. All other issues were also resolved amicably, as a result of which the threatened strike was averted. On the request of Secretary General, Bharatiya Postal Employees Federation (BPEF), Chief Engineer (Civil) held meeting

with the BPEF on 25th August, 2005 to discuss the pending issues reported by the Federation. Besides, Deputy Director General (PAF) had a periodical meeting with All India Postal Accounts Employees Association on 15th April, 2005 to discuss the issues raised by the Association. Under the Chairmanship of Member (Operations & Marketing) a meeting with Postal Federations and the Service Associations representing Postmen & Group 'D' was held on 13th May, 2005 in the context of collection of articles by Postmen.

15.3 In so far as Public Grievances Redressal work is concerned, it is to mention that in the Department of Posts, the Federations/Unions have been provided with enough opportunities in the form of formal as well as informal meetings to redress their grievances. Further, with a view to ensuring greater openness in the government functioning, the staff representatives are kept apprised about the new developments taking place in the Department by way of granting special meetings as well as during the periodical meetings with Minister/Senior Officers.

Staff Welfare

15.4 The objective of the Postal Services Staff Welfare Board is to promote, develop and organise welfare, sports and cultural activities for the employees of the Department. The Board receives grant-in-aid for these purposes from the Consolidated Fund of India. Voluntary contributions from the staff and collections through sports and cultural activities are also arranged.

15.5 The funds of the Welfare Board are utilised for activities like sports, recreation clubs, financial assistance in cases of illness, death, natural calamities, educational scholarships, subsidy for excursion trips, grant to help handicapped staff and their children, Vocational Training

लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश (कर्मचारियों के बच्चों को छात्र-वृत्ति प्रदान करने के लिए 1.8 मिलियन रु.), उड़ीसा (समिति की देयताओं पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए 1.25 मिलियन रु.), राजस्थान (लंबित दावों के समाधान के लिए 0.81 मिलियन) तथा जम्मू व कश्मीर (श्रीनगर में हालिडे होम को पुनः स्थापित करने के लिए 40.000 रु.) का अतिरिक्त अनुदान सर्किल कल्याण कोष के लिए अनुमोदित किया गया। इन अनुदानों की कुल राशि 3.9 मिलियन रु. थी। केरल (2 लाख रु.), दिल्ली (2 लाख रु.) असम (एक लाख रु.) तथा तमिलनाडु (3 लाख रु.) के सर्किल खेल कूद कोष में अतिरिक्त आबंटन किया गया। इस अनुदान में प्रदान की गई कुल राशि 8 लाख रु. है।

हॉलिडे होम

15.6 कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित के लिए देश के विभिन्न स्थानों में 30 हॉलिडे होम काम कर रहे हैं।

खेल

15.7 01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 की अवधि के दौरान विभिन्न खेलों पर अखिल भारतीय डाक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें भारोत्तोलन/पावर लिफ्टिंग/सर्वश्रेष्ठ शारीरिक सौष्ठव/एथलेटिक्स और साइक्लिंग, बैडमिंटन तथा वालीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय डाक टीमों ने निम्नलिखित राष्ट्रीय मुकाबलों में भाग लिया:-

- (क) 5वीं लाल बहादुर शास्त्री स्मारक अंतर संस्था कैरम प्रतियोगिता दिनांक 7.6.2005 से 10.6.2005 तक नई दिल्ली में।
- (ख) राष्ट्रीय बैंच प्रेस/पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता दिनांक 31.7.2005 से 3.8.2005 तक जमशेदपुर में।
- (ग) 43वीं राष्ट्रीय 'बी' शतरंज प्रतियोगिता दिनांक 3.8.2005 से 13.8.2005 तक नई दिल्ली में।
- (घ) 31वीं सीनियर नेशनल ओपन पुरुष चैम्पियनशिप दिनांक 23.8.2005 से 28.8.2005 तक कालीकट में।
- (ङ) 35वां इंटर इंस्टिट्यूशनल टेबल-टेनिस टूर्नामेंट 2005 दिनांक 10.10.2005 से 14.10.2005 तक नई दिल्ली में।

- (च) 52वां सीनियर मेन फ्री स्टाईल एंड ग्रेको रोमन स्टाइल राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप दिनांक 9.1.2006 से 12.1.2006 तक नई दिल्ली में।
- (छ) 35वीं सीनियर राष्ट्रीय कैरम चैम्पियनशिप का दिनांक 20.1.2006 से 25.1.2006 तक पुणे में आयोजन किया गया।
- (ज) 67वीं सीनियर नेशनल टेबिल टेनिस चैम्पियनशिप दिनांक 21.2.2006 से 26.2.2006 तक जयपुर में।

मेघदूत पुरस्कार

15.8 मेघदूत पुरस्कार छह व्यक्तिगत श्रेणियों में दिए गए। पुरस्कार में एक स्क्रोल, लगभग 5000/-रु. का स्वर्ण स्मारक तथा 11,000/-रु. का नकद पुरस्कार होता है। वर्ष 2005 के पुरस्कार 18 अक्टूबर 2005 को, नई दिल्ली में विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा छह कर्मचारियों को प्रदान किए गए।

चिकित्सा

15.9 कल्याण स्कीम के अंतर्गत, देश के विभिन्न भागों में डाक विभाग द्वारा 45 शहरों/कस्बों में लगभग 52 डाक औषधालय चलाए जा रहे हैं। डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के कर्मचारी और पेंशनभोगी डाक औषधालयों की सुविधा, जहां भी उपलब्ध हो, का लाभ उठाने के पात्र हैं। पात्र लाभार्थियों को इन औषधालयों से आउटडोर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है। 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार 2,16,788 लाभार्थियों को कवर करने वाले लगभग 54,000 कार्डधारक हैं जिसमें कर्मचारियों तथा पेंशनरों सहित उन पर आश्रित उनके परिवारों के सदस्य भी शामिल हैं। सेवारत कर्मचारियों को यह सुविधा सी एस (एमए) नियम के एवज में, बिना किसी शुल्क/अंशदान के प्रदान की जाती है जबकि पेंशनरों से 9/- रु. प्रति माह का नाममात्र का अंशदान लिया जाता है। ये औषधालय भारत सरकार के परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी अपना योगदान देते हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान इन औषधालयों पर लगभग 245 मिलियन रुपये खर्च किया गया। अन्य स्थानों पर जहां डाक औषधालय मौजूद नहीं हैं, वहां विभाग के कर्मचारी के.स.स्वा.यो. (सीजीएचएस) औषधालयों या प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेंटों की सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं।

Centres and Crèches, etc. Additional grants to Circles Welfare Funds of Madhya Pradesh (Rs.1.8 Million for granting scholarships to the wards of the employees), Orissa (Rs.1.25 Million to meet expenditure on committee liabilities), Rajasthan (Rs. 0.81 Million for settlement of pending claims) and Jammu and Kashmir (Rs.40,000 for re-establishing holiday home at Srinagar) were approved. The total amount of these grants was Rs.3.9 Million. Additional allocations to Circles Sports Funds of Kerala (Rs. 2 lakh), Delhi (Rs. 2 lakh), Assam (Rs. 1 lakh) and Tamilnadu (Rs. 3 lakh) were approved. The total amount of these grants was Rs. 8 lakh.

Holiday Homes

15.6 30 Holiday Homes are functioning at various places of the country for the benefit of the employees and their families.

Sports

15.7 During the period from 01st April, 2005 to 31st March, 2006, All India Postal Sports Tournaments in various events viz. Weightlifting/Power lifting/ Best Physique, Athletics & Cycling, Badminton and Volleyball were organized. All India Postal Teams participated in the following National Meets.

- (a) 5th Lal Bahadur Shastri Memorial Inter Institutional Carrom Championship from 7.6.05 to 10.6.05 at New Delhi.
- (b) National Bench Press / Power Lifting Meet from 31.7.05 to 3.8.05 at Jamshedpur.
- (c) 43rd National 'B' Chess Championship from 3.8.05 to 13.8.05 at New Delhi.
- (d) 31st Senior National Open Men Championship from 23.8.05 to 28.8.05 at Calicut.
- (e) 35th Inter Institutional Table Tennis Tournament 2005 held from 10.10.05 to 14.10.05 at New Delhi.
- (f) 52nd Senior Men Free Style and Greco Roman Style National Wrestling Championship from 9.1.06 to 12.1.06 at New Delhi.

(g) 35th Senior National Carrom Championship from 20.1.06 to 25.1.06 at Pune.

(h) 67th Senior National Table Tennis Championship w.e.f. 21.2.06 to 26.2.06 at Jaipur.

Meghdoot Awards

15.8 The Meghdoot Awards were given in six individual categories. The award comprises of a scroll, a gold sovereign of about Rs. 5000/- and cash award of Rs. 11,000/-. The awards for the year 2005 were given to six employees by the Hon'ble Minister of Communications and Information Technology on 18th October, 2005 in a function organized by the Department at New Delhi.

Medical

15.9 As a welfare measure, the Department of Posts is running 52 Postal Dispensaries in 45 cities/towns in various parts of the country. These Dispensaries extend out door treatment facilities to the eligible beneficiaries. Employees as well as pensioners of Department of Posts and Department of Telecom are entitled to Postal Dispensary facilities, wherever such facilities are available. As on 31.03.2006 there were about 54,000 Card holders covering approximately 2,16,788 beneficiaries, which include the dependant family members of the employees as well as Pensioners. Serving employees are being provided these facilities free of cost/contribution in lieu of CS (MA) Rules but a nominal contribution of Rupees nine per month is being charged from the Pensioners. These Dispensaries also help in implementation of the family welfare programmes of the Government of India. During the year 2005-2006, an expenditure of about Rs. 245 Million was incurred on these dispensaries. In other places where Postal Dispensaries are not available, the employees of the Department can avail comprehensive health care facilities from CGHS Dispensaries wherever available or from the authorised medical attendant.

डाक भवन

15.10 वर्ष के दौरान, 18 डाकघर भवन, 5 प्रशासनिक कार्यालय भवन और 17 कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

समाचार पत्र

15.11 महानिदेशक के समाचार पत्र जिसमें विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप तथा नीतिगत निर्णयों से संबंधित सूचना मौजूद होती है, का डाक भवन, नई दिल्ली से प्रकाशन किया जा रहा है। संविदा अवधि 10.5.2005 से 10.5.2006 के दौरान इन समाचार पत्रों के मुद्रण पर 59,280/-रु. खर्च किए गए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

15.12 सीधी भर्ती कोटा में 85% तक का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जबकि प्रोन्नति कोटा में 52% तक की लक्ष्य प्राप्ति हुई है। लक्ष्य प्राप्ति की समग्र प्रतिशतता 60 है। जम्मू व कश्मीर सर्किल के आरक्षण रोस्टर की जांच की गई तथा अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा तुरंत किया गया। ग्रुप 'ख' कर्मचारियों का रोस्टर नए सिरे से तैयार किया गया। जन शिकायत, कार्मिक व पेंशन मंत्रालय के अनुसरण में, डाक विभाग में अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित बैकलाग रिक्तियों की रिपोर्ट भेजी गई। इस विभाग में, 31.3.2006 को अन्य पिछड़ा वर्ग की बैकलाग आरक्षित रिक्तियों में 414 थीं जिनमें ग्रुप 'ग' (259) तथा ग्रुप 'घ' (155) है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व

15.13 31.03.2006 तक विभाग में विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जाति के 43,512, अनुसूचित जनजाति के 16531, भूतपूर्व सैनिक 1818, विकलांग भूतपूर्व सैनिक 28 तथा 31,493 महिला कर्मचारी हैं (देखें तालिका 16 व 17)।

कार्य-अध्ययन

15.14 वर्ष के दौरान डाक प्रचालन (पीओ) अनुभाग का कार्य अध्ययन किया गया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

राजभाषा

15.15 केन्द्र सरकार की नीति के अनुसरण में विभाग, सरकारी पत्राचार तथा सभी स्तरों पर दिन-प्रति दिन के प्रशासनिक

कार्यों में हिन्दी के इष्टतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों तथा द्विभाषी रूप या केवल हिन्दी में जारी होने वाले सभी अपेक्षित दस्तावेजों के अनुवाद का दायित्व राजभाषा अनुभाग पर है।

15.16 वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षा पैरा, बजट, मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी तथा सार, संहिताओं तथा नियम पुस्तिकाओं, स्थायी समिति की बैठकों से संबंधित सामग्री, फिलैटलिक विवरणिकाओं व फिलैटलिक समाचार बुलेटिन, संसदीय प्रश्नों, आश्वासनों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भों, विभिन्न विभागीय परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों आदि का अनुवाद कुछ ऐसे मुख्य कार्य हैं जिन्हें इस अवधि के दौरान पूरा किया गया। डाक निदेशालय में किए जाने वाले कार्यों के अनुवाद कार्य के अतिरिक्त विभाग के व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय तथा डाक जीवन बीमा निदेशालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों का भी अनुवाद राजभाषा अनुभाग द्वारा ही किया जाता है।

15.17 विभाग के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुचारु रूप से मॉनीटर करने के लिए मुख्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर रही हैं।

15.18 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के उद्देश्य से राजभाषा शाखा ने विभिन्न प्रोत्साहन स्कीमों का प्रवर्तन तथा प्रचार किया है। इसने हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को नामांकित किया तथा निदेशालय के सभी अनुभागों, सर्किल मुख्यालयों तथा डाक विभाग के अन्य सभी संबंधित कार्यालयों को, राजभाषा अधिनियम के नियमों तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन नियमों के अंतर्गत जारी अनुदेशों के अनुपालन से अवगत कराया।

15.19 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निदेशालय के सभी अनुभागों, सर्किल मुख्यालयों, डाक प्रशिक्षण केन्द्रों, पोस्टल स्टॉफ कालेज, डाक जीवन बीमा निदेशालय तथा व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की पुनरीक्षा भी राजभाषा अनुभाग में की जाती है तथा जहां कहीं भी त्रुटियां पाई गईं उनमें सुधार लाने के लिए आवश्यक उचित उपाय किए गए।

15.20 राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की द्वितीय उप समिति भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को मॉनीटर करती

Postal Buildings

15.10 During the year, the construction of 18 post office buildings, 5 administrative office buildings and 17 staff quarters was completed.

Newsletter

15.11 Director General's Newsletter covering important activities and decisions of the Department is being published from Dak Bhawan, New Delhi. The expenditure incurred for printing of the Newsletters during the contract period 10.5.2005 to 10.5.2006 was Rs.59,280.

Scheduled Castes/Scheduled Tribes

15.12 In Direct Recruitment Quota, 85% of the target has been achieved while in promotional Quota the percentage is 52. The overall percentage of achievement is 60. Reservation Rosters of Jammu and Kashmir Circle were inspected and grievances of the SC/ST Staff settled on the spot. The Roster of Group 'B' was got prepared afresh. In compliance with Ministry of Public Grievances, Personnel and Pensions, a report on the reserved backlog vacancies of OBCs in the Department of Posts was sent. As on 31.03.06, there were 414 backlog-reserved vacancies of OBCs in the Group-C (259) and Group-D (155) in the Department of Posts.

Representation of SC, ST, Ex-Serviceman and Women

15.13 As on 31.03.2006, there were 43,512 SC; 16,531 ST; 1,818 Ex-Servicemen, 28 Disabled Ex-servicemen and 31,493 Women employees in various grades in the Department (see Table 16 & 17).

Work Study

15.14 During the year the work measurement study in respect of Postal Operations (PO) Section has been conducted and the report has been issued.

Official Language (OL)

15.15 In pursuance of the policy of the Central Government, the Department has been making a sustained effort to ensure optimum use of Hindi in official

correspondence and day-to-day administrative work at all levels. The Official Language Branch is responsible for the implementation of Official Languages Act, 1963 and the Rules made there under as well as translation of all kinds of documents required to be issued either in bilingual form or in Hindi only.

15.16 The translation of the Annual Report, Audit Paras, Budget, Cabinet Notes and Summary, Code and Manuals, material in connection with the meetings of the Standing Committee, Philatelic Brochures/ Philatelic News Bulletin, Parliament Questions, Assurances, VIP references and Papers relating to various Departmental Examinations are some of the major works accomplished during the period. In addition to the translation work generated in the Directorate of Posts, translation support has also been provided to the Business Development & Marketing Directorate and PLI Directorate of the Department.

15.17 In order to effectively monitor the progressive use of Hindi in the Offices of the Department, Official Language Implementation Committees are functioning in the headquarters as well as in all the Subordinate Offices.

15.18 OL Branch promoted and propagated various incentive schemes in order to accelerate the use of Hindi. It nominated officials for imparting training under the Hindi teaching scheme and also acquainted all the Sections of the Directorate, Circle Headquarters and other concerned Offices of the Department of Posts with the OL Act, Rules and instructions issued thereunder for their compliance and for achieving the fixed targets.

15.19 The Quarterly Progress Reports received from all the Sections of the Directorate, Circle Headquarters, Postal Training Centres, Postal Staff College, PLI Directorate and Business Development & Marketing Directorate regarding the progressive use of Hindi were also reviewed by the OL Branch and necessary corrective measures were taken in respect of those wherein discrepancies were noticed.

15.20 The Second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language also monitors the implementation of Official Language Policy. During the period, the Second Sub-Committee of the Committee of

है। अवधि के दौरान राजभाषा पर संसदीय समिति की द्वितीय उप समिति ने विभिन्न सर्किलों के आठ कार्यालयों का निरीक्षण किया।

15.21 राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2005-06 में दिए निर्देशों का अनुपालन करते हुए विभाग के अधिकारियों द्वारा दस कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। राजभाषा पर संसदीय समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने विभिन्न सर्किलों में भिन्न स्तरों के आठ कार्यालयों के अध्यक्षों से विचार विमर्श किया।

15.22 दिनांक 14 सितंबर, 2005 को विभाग में हिन्दी दिवस आयोजित किया गया तथा 1 से 15 सितंबर, 2005 को हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़ा में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी बांटे गए। पखवाड़े के दौरान दो कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

जन शिकायतें

15.23 वर्ष 2005-2006 के दौरान, विभाग में 10,24,551 जन शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 9,57,175 मामलों का निपटान किया गया।

15.24 वर्ष के दौरान डाक अदालत तथा पोस्ट फोरम की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की गईं। विभाग ने, वर्ष 2003-04 में आरंभ की गई वेब आधारित प्रणाली का प्रयोग करके शिकायतों के शीघ्र निपटारे के भी प्रयास किए हैं। ग्राहकों को हमारी वेबसाइट www.indiapost.gov.in शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी प्राप्त है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

15.25 वर्ष 2005-06 के दौरान, डाक विभाग ने 15 जून, 2005 को लागू हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कार्यान्वित किया तथा 12 अक्टूबर, 2005 में इसे वैधानिक तौर पर सम्पूर्ण रूप से लागू किया। अधिनियम कार्यान्वित करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए।

(i) कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र (सीसीसीएस) के 629 प्रबंधकों को चिन्हित करके, देश के प्रत्येक जिले में उन्हें केन्द्रीय सहायक जन शिकायत अधिकारी (सीएपीआईओ) के तौर पर नामित किया गया जो मांगी गई सूचना संबंधी

आवेदन पत्रों अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली अपीलों को प्राप्त करके, डाक विभाग के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा अन्य जन प्राधिकारियों के नोडल अधिकारियों को जैसा भी मामला हो, अग्रेषित करते हैं। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) का चयन प्रत्येक स्तर पर किया गया है जैसे कि डाक निदेशालय, डाक जीवन बीमा निदेशालय, व्यवसाय विकास तथा विपणन निदेशालय, सर्किल, रीजन तथा डिवीजन आदि। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) से वरिष्ठ अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर नामित किया गया है।

(ii) धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत यथापेक्षित 17 नियम पुस्तकों का एक सैट समय रहते सूचना देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। केन्द्रीय सूचना आयोग के पारदर्शिता सूचक जो जन माध्यमों द्वारा जनसाधारण को सूचना पहुँचाने के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है, में जानकारी देने के आधार पर डाक विभाग को प्रथम स्थान दिया गया है।

(iii) कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन किया गया तथा पोस्टल स्टाफ कालेज आफ इंडिया तथा डाक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा देशभर में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण दिया गया।

15.26 अपने निकाय में अधिनियम कार्यान्वित करने के वैधानिक दायित्व के अलावा, डाक विभाग को नामोद्दिष्ट किए गए केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारियों (सीएपीआईओ) द्वारा केन्द्र सरकार के अन्य सार्वजनिक प्राधिकारियों को इस संबंध में सहायता प्रदान करने का दायित्व भी सौंपा गया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकारियों को डाक विभाग के नामोद्दिष्ट सीएआईपीओ की सेवाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। अपीलीय प्राधिकारियों, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ), केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारियों (सीएपीआईओ), 17 नियम पुस्तकों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकारियों के नोडल अधिकारियों के पतों की सूची के संबंध में आवश्यक जानकारी विभाग की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है तथा इसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।

Parliament on Official Language inspected eight offices in different Circles.

15.21 In pursuance of the directives laid down in the Annual Programme 2005-06 issued by the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs), ten offices were inspected by the Officers of the Department. The Drafting and Evidence Sub Committee of the Committee of Parliament on Official Language held discussions with the heads of the eight offices of various levels in different Circles.

15.22 Hindi Diwas was observed in the Department on 14th September, 2005 and Hindi Fortnight was observed from 1st to 15th September 2005. Prizes were distributed to the winners of various competitions held during the Hindi Fortnight. Two Hindi Workshops were also organised during the fortnight.

Public Grievances

15.23 During the year 2005-2006, the Department handled 10,24,551 cases of public grievances and a total of 9,57,175 cases were settled.

15.24 The meetings of Dak Adalat and Post Forum were held during the year on a regular basis. The Department has taken steps to resolve grievances faster through the use of a web-based system that was introduced in 2003-04. The customers also have the facility to register their complaints on our web site www.indiapost.gov.in.

Right to Information Act 2005

15.25 During the year 2005-2006, the Department of Posts has implemented the Right to Information Act, 2005 which has come into force from 15th June, 2005 and was statutorily operationalized in toto with effect from 12th October, 2005. To implement the Act the following steps were taken by the Department:

- (i) 629 Managers of Computerized Customer Care Centres (CCCs) have been identified and designated as Central Assistant Public Information

Officers (CAPIOs) in each of the Districts across the country to receive the Applications for information or Appeals under this Act, for forwarding the same to the concerned Central Public Information Officer (CPIOs) in the Department of Posts and Nodal Officers of Other Public Authorities as the case may be. Central Public Information Officers (CPIOs) have been designated at each level i.e. Postal Directorate, PLI Directorate, Business Development and Marketing Directorate, Circle, Region and Division. Officers senior to the Central Public Information Officers (CPIOs) have been designated as Appellate Authority.

- (ii) A set of 17 Manuals as required under Section 4 (1) (b) regarding proactive disclosure of information were got prepared. In the transparency index, prepared by Central Information Commission (CIC) on the basis of an analysis about extent of access to information to the public in the public domain, Department of Posts has been ranked first in terms of disclosure.
- (iii) Workshops and Seminars were got conducted and training imparted on RTI to the officers/officials of the Department all over the country by Postal Staff College India (PSCI) and Postal Training Centres.

15.26 In addition to the statutory responsibility to implement the Act in its own domain, the Department of Posts has also been bestowed with the responsibility to assist other public authorities under the Central Government in implementation of the Act by providing services of its designated Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) on their behalf. In this regard the Public Authorities under Central Government have been requested to utilize the services of designated CAPIOs of Department of Posts. Information regarding Appellate Authorities, CPIOs, CAPIOs, 17 Manuals, List of Addresses of Nodal Officers of other Public Authorities have been uploaded on the website of the Department and are being updated on regular basis.

15.27 वर्ष 2005-06 के दौरान सूचना प्राप्ति के 1209 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा 19259 रु. बतौर आवेदन शुल्क तथा सूचना उपलब्ध कराने की लागत के तौर पर प्राप्त हुए। 82 मामलों में सूचना के आवेदन पत्र अधिनियम की धारा के अंतर्गत नामंजूर कर दिए गए।

प्रास्थिति में बदलाव

15.28 वर्ष के दौरान (क) सहायक अधीक्षक डाकघर (एएसपी) (वेतनमान 6500-10500/-रु.) के पदों को ग्रुप 'ख' राजपत्रित की प्रास्थिति प्रदान की गई। (ख) ग्रुप 'ग' व ग्रुप 'घ' के 4601 पदों को सेना डाक सेवा (से.डा.से.) में प्रतिनियोजित करने के उद्देश्य से सर्किलों में आबंटित किया गया। (ग) झारखण्ड के राजस्व जिलों (जो पहले बिहार सर्किल द्वारा नियंत्रित थे) में आने वाले 47 उप डाकघरों/शाखा डाकघरों को झारखण्ड सर्किल में स्थानांतरित किया गया तथा इसी प्रकार बिहार के राजस्व जिलों में आने वाले 5 शाखा डाकघरों (जो पहले झारखण्ड सर्किल द्वारा नियंत्रित थे) को बिहार सर्किल में स्थानांतरित किया गया। झारखण्ड राजस्व जिले में आने वाले एक डाकघर को (जो पहले पश्चिम बंगाल द्वारा विनियंत्रित किया जाता था) भी झारखण्ड सर्किल में स्थानांतरित किया गया। (घ) हैदराबाद जीपीओ (श्रेणी- II) का दर्जा बढ़ाकर ग्रुप 'क' किया गया। (ङ) गांधीनगर डाक डिवीजन का दर्जा बढ़ाकर ग्रुप 'क' श्रेणी में डाला गया, वहीं दूसरी ओर मेहसाणा डाक डिवीजन का दर्जा घटाकर ग्रुप 'ख' श्रेणी में डाला गया है।

संवर्गों का विलयन

15.29 निरीक्षक मेल मोटर सेवा तथा सहायक प्रबंधक मेल मोटर सेवा के संवर्गों को एक ही ग्रेड में विलयित करके 5500-

9000/- रु. का वेतनमान प्रदान करते हुए 'सहायक प्रबंधक मेल मोटर सेवा' का पदनाम प्रदान किया गया है।

स्थापना

15.30 डा. यू.एस. राघवन (भा.डा.से. 1969) को 1.11.2005 से सचिव, डाक विभाग, महानिदेशक (डाक) तथा पदेन अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड नियुक्त किया गया। श्री आई.एम.जी. खान तथा श्री हरिन्द्र सिंह (भा.डा.से. 1970) को बतौर सदस्य, डाक सेवा बोर्ड पदोन्नत किया गया। तीन उच्च प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों को प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। पांच वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों को वरिष्ठ उप महानिदेशक / मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। सात अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया। भारतीय डाक ग्रुप 'क' के 13 अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में एनएफएसजी में पदस्थापित किया गया। बारह वरिष्ठ समयमान अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया। 24 कनिष्ठ समयमान ग्रुप 'क' अधिकारियों को वरिष्ठ समयमान ग्रेड में पदोन्नत किया गया। भारतीय डाक सेवा ग्रुप 'क' (2003 बैच) के नौ परिवीक्षार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के उपरांत स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत आठ उम्मीदवारों को भारतीय डाक सेवा ग्रुप घकड के कनिष्ठ समयमान में नियुक्त किया गया। एक सौ ग्यारह पी एस ग्रुप 'ख' अधिकारियों को भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में पदोन्नत किया गया। एक सौ दो निरीक्षक लाइन कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पीएस ग्रुप 'ख' के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। पांच सामान्य लाईन कर्मचारियों को पीएस ग्रुप 'ख' में पदोन्नत किया गया, नौ कर्मचारियों को जीसीएस ग्रुप 'ख' ग्रेड में पदोन्नत किया गया।

15.27 During the year 2005-2006, 1209 applications for information and Rs. 19,259 as application fee and cost of providing information were received. In 82 cases applications for information were rejected under the provisions of the Act.

Change in Status

15.28 During the year (a) the post of Assistant Superintendent of Posts (ASP) (Pay Scale Rs. 6500-10500) was conferred Gazetted Group 'B' status (b) 4601 posts of Group 'C' and Group 'D' were distributed amongst circles for deputing to Army Postal Services (APS) (c) The 47 Sub Post Offices/Branch Post Offices falling under revenue districts of Jharkhand (earlier controlled by Bihar Circle) were transferred to Jharkhand Circle and vice-versa 5 Branch Post Offices falling under revenue districts of Bihar (earlier controlled by Jharkhand Circle) were transferred to Bihar Circle. Also one post office falling under revenue district of Jharkhand (earlier controlled by West Bengal Circle) has been transferred to Jharkhand Circle (d) Hyderabad GPO (Class-II) was upgraded to Group 'A' status (e) The Gandhinagar Postal Division has been upgraded to Group 'A' category, while, simultaneously, Mehsana Postal Division has been down graded to Group 'B' category.

Merger of Cadre

15.29 The cadre of Inspector MMS and Assistant Manager MMS has been merged into a single grade with nomenclature of "Assistant Manager MMS" in the pay scale of Rs. 5500-9000.

Establishment

15.30 Dr. U.S.Raghavan (IPoS-1969) was appointed Secretary, Department of Posts, Director General (Posts) and ex-officio Chairman, Postal Services Board w.e.f. 1.11.2005. Shri I.M.G. Khan and Shri Harinder Singh (IPoS-1970) were promoted as Members of the Postal Services Board. Three HAG officers were promoted to the grade of Principal Chief Postmaster General. Five SAG officers were promoted to the grade of Senior Deputy Director General/Chief Postmaster General. Seven officers were promoted to the grade of SAG. Thirteen officers of Indian Postal Group 'A' were placed in the NFSG in JAG grade. Twelve Senior Time Scales officers were promoted to the grade of JAG. Twenty-Four officers of Junior Time Scale Group 'A' were promoted to the grade of Senior Time Scale. Nine probationers of Indian Postal Service Group 'A' (2003 batch) were given independent charge after completion of training. Eight candidates recommended by UPSC were offered appointment in Junior Time Scale of Indian Postal Services Group 'A'. One hundred and eleven PS Group 'B' officers were promoted to Junior Time Scale of Indian Postal Service Group 'A'. One hundred and two Inspector's line officials were promoted to the grade of PS Group 'B' through DPC. Five General Line officials were promoted to the grade of PS Group 'B'. Nine officials were promoted to the GCS Group 'B' grade.



श्री आई.एम.जी. खान, सदस्य (प्रचालन एवं विपणन) 27.12.2006 को अलीगढ़ से मुरादाबाद के लिए मेल मोटर को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए।

Shri I.M.G. Khan, Member (Operations & Marketing) flagging off Mail Motor from Aligarh to Moradabad on 27.12.2006.



गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, एक्सपो' 2005 में भारतीय डाक का स्टॉल।
India Post Stall at International Trade Fair, EXPO' 2005 at Guwahati.



गुजरात सर्किल के राजकोट प्रधान डाकघर का डाक वित्तीय मार्ट।
Postal Financial Mart at Rajkot Head Post Office in Gujarat Circle.



तमिलनाडु सर्किल का डाक वित्तीय मार्ट।
Postal Financial Mart in Tamilnadu Circle.

भाग - II

कार्यकलाप

(अप्रैल-दिसम्बर 2006)

डाक नेटवर्क का विस्तार

1.1 डाक नेटवर्क के यौक्तिकीकरण के संबंध में 10वीं योजना के नीति निर्देशकों के अनुसार नए डाकघर खोलने के लिए कोई योजना लक्ष्य आबंटित नहीं किया गया। परन्तु फिर भी नया डाकघर खोलने का यदि कोई औचित्य पाया जाता है तो उसे, किसी भी ऐसे मौजूदा डाकघर जिसे उसके वर्तमान अवस्थिति पर विभागीय मानदंडों के आधार पर आगे बनाए रखना उचित नहीं पाया जाता है, पुनःअवस्थापित करके खोला जा सकता है। किफायती डाक सेवाएं तथा फ्रैंचाइजिंग के माध्यम से डाक सेवाएं सुलभ करवाने के वैकल्पिक माध्यम भी ढूँढ़े जा रहे हैं।

डाक प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण

1.2 सात मैट्रो शहरों में डाक संचालन तथा प्रेषण कार्य को सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से मेल ट्रे आरंभ किए गए हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान क्रमशः 5.2 मिलियन तथा 34 मिलियन वित्तीय परिव्यय के साथ 10 प्रधान रिकार्ड कार्यालयों तथा 51 रजिस्ट्रेशन छंटाई केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है।

पिक अप सेवा

1.3 इस सेवा के अंतर्गत, डाकिये अपनी बीट के अन्दर जब पत्र वितरित करने के लिए निकलते हैं तो वे स्पीड पोस्ट तथा सामान्य डाक दोनों एकत्रित करते हैं। भारतीय डाक इस स्कीम की प्रगति की मॉनिटरिंग मासिक आधार पर कर रहा है। चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर 2006 तक 305,410 स्पीड पोस्ट मर्दे तथा 2,718,896 साधारण डाक की मर्दे इकट्ठा की गई तथा इसी अवधि में डाक टिकटों/स्टेशनरी की बिक्री के माध्यम से 7.45 मिलियन रु. की राजस्व वसूली हुई।

राखी डाक सेवा

1.4 भारतीय डाक ने 8 अगस्त, 2006 से 'राखी डाक सेवा' के नाम से एक नई सेवा आरंभ की है। इसमें राखी संप्रेषित करने के लिए एक बढ़िया किस्म का लिफाफा जिस पर डिजाइन मुद्रित

होता है, दिया जाता है। 50 ग्राम से अनधिक भार वाली राखी डाक की शुल्क दर 5/-रु. हैं तथा प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम अथवा उसके भागांश पर 3/-रु. डाक शुल्क प्रभारित किया जाता है।

मेल मोटर सेवा (एमएमएस)

1.5 इस अवधि के दौरान, दिल्ली मेल मोटर सेवा बेड़े में 21 सीएनजी चार पहिया वाहन तथा 9 सीएनजी तिपहिया वाहन शामिल किए गए हैं। एमएमएस अहमदाबाद में 4 सीएनजी प्रोपेल्ड वाहन शामिल किए गए हैं। विभाग को देश भर में 145 सीएनजी प्रोपेल्ड वाहन चलाने का गौरव प्राप्त है जिसमें से 111 सीएनजी वाहन तो मेल मोटर सेवा मुम्बई के बेड़े में हैं।

फिलैटली

1.6 अवधि के दौरान 31 स्मारक/विशेष डाक टिकटें जारी की गईं। जारी होने वाली अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सुन्दर डाक-टिकटों में कुछ का उल्लेख इस प्रकार है 3 सिख, राष्ट्रपति द्वारा बेडा पुनरीक्षण (4 डाक-टिकटों का सैट), विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारत-साइप्रस संयुक्त डाक-टिकट (डाक-टिकटों का सैट) संयुक्त डाक-टिकट (4 डाक-टिकटों का सैट) कुरिंजी, वर्षा जल संग्रहण, भारत मंगोलिया संयुक्त डाक टिकट (दो डाक-टिकटों का सैट), लुप्तप्राय पक्षी (4 डाक टिकटों का सैट), हिमालय की झीलें (5 डाक-टिकटों का सैट), लाला दीन दयाल, विश्व एड्स दिवस, प्रथम फील्ड डाकघर, चंदन (भारत की पहली सुगंधित डाक टिकट) तथा बाल श्रम मिटाएं। भारत की प्रथम सुगंधित डाक टिकट 'चंदन' का विमोचन 13.12.2006 को किया गया तथा इसे काफी सराहना मिली है। वर्ष 2007 में जारी होने वाली डाक-टिकटें संस्तुत करने के लिए दिनांक 8.11.2006 को नई दिल्ली में फिलैटली सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

PART-II

ACTIVITIES

(April-December 2006)

Expansion of Postal Network

1.1 In consonance with the policy directives of the 10th Plan regarding rationalization of the Postal Network, no plan targets have been allotted for opening of new post offices. However, if any justification for opening a new post office is found, it can be opened by relocation of an existing post office which is no longer justified on the departmental norms in its present location. Efforts to provide cost effective postal services and alternative means of providing access to postal services such as franchising are also being explored.

Computerization and Modernization of Mail Operations

1.2 In order to streamline the mail processing and dispatch in seven metro cities mail trays have been introduced. During the year 2006-07 it is proposed to computerize 10 Head Record Offices and 51 Registration Sorting Centres with a financial outlay of Rs. 5.2 Million and Rs. 34 Million respectively.

Pick Up Service

1.3 Under this service, Postmen collect both Speed Post and ordinary letters while moving in their beats to deliver letters. India Post has been monitoring the progress of this scheme on a monthly basis. In the current financial year up to December, 2006, 305,410 Speed Post articles and 2,718,896 ordinary mail pieces were picked up, while revenue realized from sale of postage stamps/stationery was to the tune of Rs. 7.45 Million in the same period.

Rakhi Mail Service

1.4 India Post has introduced a new service called “Rakhi Mail Service” w.e.f. 8th August, 2006. It offers

a superior quality envelope with printed design for sending Rakhi. The rates of postages on Rakhi Mail are Rs. 5 for a weight not exceeding 50 grams, and Rs. 3 for every additional 50 grams or fraction thereof.

Mail Motor Service (MMS)

1.5 During the period 21 CNG four –wheeler and 9 CNG three-wheeler vehicles have been inducted in the fleet of the Mail Motor Service, Delhi. 4 CNG propelled vehicles have been inducted in MMS Ahmedabad. The Department is proud of operating 145 CNG propelled vehicles in the country out of which 111 CNG vehicles are in MMS Mumbai.

PHILATELY

1.6 During the period, 31 issues comprising of commemorative/special postage stamps have been released. Among the more significant and beautiful stamps issued, mention may be made of the stamp on 3 Sikh, President’s Fleet Review (set of 4 stamps), World Consumer Rights Day, Indian Agricultural Research Institute, India-Cyprus Joint Issue (set of 4 stamps), Kurinji Flower, Rainwater Harvesting, India-Mongolia Joint Issue (set of two stamps), Endangered Birds of India (set of 4 stamps), Himalayan Lakes of India (set of 5 stamps), Lala Deen Dayal, World Aids Day, First Army Field Post Office, Sandalwood (India’s first fragrant stamp), and Stop Child Labour. India’s first scented stamp on ‘Sandalwood’ was brought out on 13.12.2006 and the stamp has been widely appreciated. The meeting of the Philatelic Advisory Committee (PAC) to recommend on the stamps issues for 2007 was held on 8.11.2006 at New Delhi.

फिलैटलिक प्रदर्शनी

1.7 अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 की अवधि के बीच देशभर में विभिन्न स्थानों पर सात डाक-टिकट प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। देशभर में सर्किलों द्वारा राज्य/रीजनल/जिला स्तर पर आयोजित सात प्रदर्शनियों में, राष्ट्रीय फिलैटलिक संग्रहालय में प्रदर्शित डाक टिकटों में कुछ विशेष डाक-टिकटों को आमंत्रित श्रेणी में प्रदर्शित किया गया।

1.8 9.10.2006 से 20.12.2006 तक राष्ट्रीय फिलैटलिक संग्रहालय में महात्मा गांधी की डाक-टिकटों पर एक विशेष अनुदर्शन आयोजित किया गया था।

1.9 31 मार्च, 2007 तक निम्नलिखित प्रत्याशित कार्यकलाप किए जाने हैं:

- (क) राष्ट्रीय फिलैटलिक संग्रहालय, नई दिल्ली में प्रकृति व पर्यावरण पर डाक-टिकटों की प्रदर्शनी
- (ख) 13.01.2007 से 15.01.2007 तक अजमेर में राष्ट्रीय स्तर की फिलैटलिक प्रदर्शनी 'राजपैक्स-2007'
- (ग) 8-9 जनवरी, 2007 को कायंगुलम, केरल में जिला स्तर की फिलैटलिक प्रदर्शनी 'मावेलीपैक्स-2007'
- (घ) फरवरी, 2007 को अंतर्राष्ट्रीय फिलैटलिक प्रदर्शनी
- (ङ) 10.2.2007 से 16.02.2007 तक ललित कला अकादमी, अलीगंज, लखनऊ में राज्य स्तर की फिलैटलिक प्रदर्शनी
- (च) डाक-टिकटें जारी करना : अवधि के दौरान, भारत के प्रसिद्ध सेतु, भारतीय मेल, भारत के राष्ट्रीय उद्यान पर तीन विषयगत सैट तथा भारतीय गुलाब पर सुगन्धित डाक-टिकटों के सैट सहित लगभग 10 निर्गम जारी करने का प्रस्ताव है।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (एएसईएन)

1.10 सचिव (डाक) और उप महानिदेशक (आईआर) ने 13वीं एएसईएन पोस्टल बिजनेस बैठक में भाग लेने के लिए 27 से 30 अगस्त, 2006 तक यांगोन, म्यांमार का दौरा किया।

पहली बार भारत को जापान, चीन, दक्षिण कोरिया तथा फ्रांस के साथ, एएसईएन पोस्ट की बैठक में बतौर पर्यवेक्षक के लिए आमंत्रित किया गया। बैठक में एएसईएन पोस्ट तथा अन्य डाक प्रशासनों, नये टर्मिनल ड्यूस सिस्टम पर एएसईएन का दृष्टिकोण विकसित करना, किफायती सेवाओं और सूचना का आदान-प्रदान तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाओं के साफ्टवेयर को एएसईएन के भावी वित्तीय नेटवर्क के तौर पर उसकी सफलता तथा सीधे मेल बिजनेस विकसित करने पर विचार विमर्श किया गया।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का डाक प्रचालन परिषद (पीओसी)

1.11 सचिव (डाक), उप महानिदेशक (आईआर) तथा सहायक महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय डाक) के एक तीन सदस्यीय दल ने दिनांक 3 से 20 अक्टूबर, 2006 तक बर्न में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की डाक प्रचालन परिषद (प्रशासन परिषद सत्र 2006) की बैठकों में भाग लिया। प्रचालनात्मक मुद्दों पर समिति 3 का अध्यक्ष होने के नाते भारत ने डाक प्रचालन परिषद की बैठकों में भाग लिया। डाक प्रचालन परिषद की सभी समितियों के अध्यक्ष, यूपीयू के महानिदेशक, यूपीयू के उप महानिदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, प्रबंध समिति के संघटक हैं। इस सत्र के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही, वह थी भारत का डाक प्रचालन परिषद की डाक वित्तीय सेवाओं के ग्रुप के अध्यक्ष के बतौर चुना जाना। जैसा कि विश्व भर में डाक राजस्व एक तेजी से विकसित होने वाला तथा लाभकारी क्षेत्र है इसलिए भारत को इसमें मिलने वाली प्रतिष्ठा से उसकी अहम भूमिका तथा गौरव प्राप्त हुआ है। उप महानिदेशक (आईआर) ने 13 अक्टूबर, 2006 को डाक वित्त सेवा ग्रुप की बैठकों की अध्यक्षता की। इस दल ने कई अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया जिसमें सेवा गुणवत्ता निधि तथा टर्मिनल ड्यूस प्रोजेक्ट ग्रुप के न्यासी बोर्ड की बैठकें भी शामिल हैं। इस सबके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवाओं के साफ्टवेयर तथा भारत में इसके कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए डाक प्रौद्योगिकी केन्द्र के साथ भी एक बैठक आयोजित की गई।

सम्मेलन एवं संगोष्ठियां

1.12 सदस्य (प्रचालन एवं विपणन), डाक सेवा बोर्ड तथा उप महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) ने दिनांक 26 से 28 अप्रैल,

Philatelic Exhibition

1.7 Seven Stamp Exhibitions were held in various places around the country during the period between April, 2006 to December, 2006. Exhibits from the National Philatelic Museum were displayed in the invitee class in seven exhibitions held all over the country by the Circles at State/Regional/District levels.

1.8 A special retrospect of stamps on Mahatma Gandhi was organized in the National Philatelic Museum from 9.10.2006 to 20.12.2006.

1.9 The following activities are anticipated by 31st March, 2007:

- (a) An exhibition of stamps on Nature and Environment at the National Philatelic Museum, New Delhi.
- (b) “Rajpex-2007” State Level Philatelic Exhibition at Ajmer from 13.01.2007 to 15.01.2007.
- (c) “Mavelipex-2007” District Level Philatelic Exhibition at Kayangulam, Kerala from 8-9th January, 2007.
- (d) International Philatelic Exhibition in February, 2007.
- (e) State Level Philatelic Exhibition at Lalit Kala Academy, Aliganj, Lucknow from 10.02.2007 to 16.02.2007.
- (f) Issue of Postage Stamps: About Ten issues, including three thematic sets on Landmark Bridges of India, Fairs of India and National Parks of India and also a set of scented stamps on Roses of India, have been planned for issue during the period.

INTERNATIONAL RELATIONS

Association of South East Asian Nations (ASEAN)

1.10 Secretary (Posts) and Deputy Director General (International Relations) visited Yangon, Myanmar from 27th to 30th August, 2006 to attend the 13th ASEAN Postal Business Meeting. For the first time, India along with Japan, China, South Korea and France was invited to the ASEAN Post meeting as an observer. The topics

of discussion in the meeting included partnership models between ASEANPOST and other Postal Administrations, developing an ASEAN view on the new Terminal Dues system, exchange of information on the cost-effectiveness and success of the International Financial Services (IFS) software as the future financial network for ASEAN and development of Direct Mail business.

Postal Operations Council (POC) of the Universal Postal Union

1.11 A three-member delegation comprising Secretary (Posts), Deputy Director General (International Relations) and Assistant Director General (International Mails) attended meetings of the Postal Operations Council (POC) of the Universal Postal Union (2006 Session of the Council of Administration) held at Berne from 3rd to 20th October, 2006. Being Chairman of Committee 3 on Operational Issues, India Post participated in the meetings of the POC Management Committee. Chairmen of all Committees of the POC, the Director General of UPU, the Deputy Director General of UPU and other senior officials of the International Bureau, constitute the Management Committee. An important development during this session was that India was appointed Chair of the Postal Financial Services Group (PFSG) of the POC. Since financial services comprise one of the most rapidly evolving and remunerative segments of postal revenue across the world, this position assumes even greater role and prestige. Deputy Director General (International Relations) chaired the meetings of the PFSG held on 13th October, 2006. The delegation attended several other important meetings including meetings of the Board of Trustees (BoT) of Quality of Service Fund (QSF) and Terminal Dues Project Group. On the sidelines a meeting was held with Postal Technology Centre to discuss International Financial Services (IFS) software and its implementation in India.

Conferences and Seminars

1.12 Member (Operations & Marketing), Postal Services Board and Deputy Director General (International Relations) participated in the International

2006 को बीजिंग, चीन में डाक विपणन एवं विनियमन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। राज्य पोस्ट ब्यूरो, चीन जन गणराज्य जो इस समय सुधारों के दौर से गुजर रहा है, ने इस संगोष्ठी का आयोजन डाक सुधारों, डाक कानून, बाजार में पहुंच तथा विनियमन, डाक सुरक्षा एवं अभिरक्षा पर अपने अनुभव बांटने के उद्देश्य से किया। भारतीय दल ने संगोष्ठी में इन मुद्दों पर मिलने वाले अनुभवों पर एक प्रस्तुति दी। इस संगोष्ठी में अर्जेन्टीना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, चीन तथा भारत ने भाग लिया।

1.13 सचिव (डाक) ने 28 अप्रैल, 2006 को बर्न, स्विटजरलैंड में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा आयोजित महानिदेशकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों तथा विभिन्न देशों के सरकारी व निजी क्षेत्र के नेताओं के एक वार्षिक उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन, डाक क्षेत्र के निर्णायक गुटों की सामरिक महत्व के विषय की श्रृंखला की पहली कड़ी थी। सचिव (डाक) ने 'क्या प्रत्येक देश एक राष्ट्रीय डाक उद्यम बनाए रख सकता है' के विषय पर संगोष्ठी में भाग लिया। सचिव द्वारा इसमें भाग लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि न केवल यह विषय अपने आप में महत्वपूर्ण था बल्कि चूंकि विश्व में सबसे बड़े डाक नेटवर्क का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था।

1.14 मुख्य महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास) ने संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा 30 जून, 2006 को आयोजित उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का विषय था 'आज और कल के डाक बाजारों को संगठित करना'। यह सम्मेलन यूपीयू द्वारा आयोजित डाक क्षेत्र के निर्णायक गुटों के सामरिक महत्व पर आयोजित उच्च स्तरीय सम्मेलन के श्रृंखला की दूसरी कड़ी थी। सम्मेलन में बदलते डाक परिवेश, नई प्रौद्योगिकियों में तेजी से आने वाले विकास, स्वतंत्र विनियामकों का आविर्भाव, विश्व सेवा प्रदाताओं तथा व्यवसाय व बाजार संघटन का वैश्वीकरण तथा प्रशासनों की नई भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

1.15 सहायक महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) ने 24-28 जुलाई 2006 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित राष्ट्रमंडल डाक प्रशासन के 15वें सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में 'अगले दो

वर्षों के लिए डाक चुनौतियों' पर चर्चा की गई। सम्मेलन में, अगले दो वर्षों के दौरान डाक समुदाय को चुनौती देने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय डाक ने सम्मेलन में डाक वित्त सेवाओं पर एक महत्वपूर्ण निरूपण प्रस्तुत किया।

1.16 महाप्रबंधक (विपणन), व्यवसाय विकास निदेशालय ने एशियाई प्रशान्त डाक यूनियन (एपीपीयू) ब्यूरो द्वारा आयोजित 'डाकघरों में रिटेल व्यवसाय का भविष्य' पर एक सम्मेलन में भाग लिया, जिसे 22 से 24 अगस्त, 2006 तक बैंकाक में ला-पोस्ट फ्रांस के सहयोग से आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एपीपीयू के सदस्यों को लागत एवं राजस्व के आधार पर अपने नेटवर्क के अधिकतम उपयोग तथा अपने डाक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कौन से विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, समझना था।

1.17 सदस्य (प्रचालन एवं विपणन) डाक सेवा बोर्ड ने 14 से 16 नवम्बर, 2006 को दुबई में आयोजित यूपीयू के सामयिक महत्व पर हुए सम्मेलन में भाग लिया। इस बैठक में, पूरे डाक क्षेत्र के वरिष्ठतम नीति निर्धारकों को आपस में विचार विमर्श करने तथा एक तटस्थ एवं यथार्थपरक परिवेश में समझने का अवसर प्राप्त हुआ। बैठक में डाक नेटवर्क तथा सूचना सोसायटी; औद्योगिक बदलावों को समझने, डाक नेटवर्क विकसित करने, बाजार के नए प्रतिस्पर्धियों डाक क्षेत्र के स्थायी विकास आदि जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

प्रतिनिधिमंडल

1.18 सचिव (डाक), उप महानिदेशक (आईआर) तथा सहायक महानिदेशक (आईआर) के तीन सदस्यों का एक दल 9 से 13 मई, 2006 को क्वालालामपुर, मलेशिया में एशियाई प्रशांत डाक यूनियन कार्यकारी परिषद (एपीपीयूईसी) की बैठक में भाग लेने के लिए गया था। भारतीय डाक के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि इसमें भारत ने न केवल कार्यकारी परिषद की उपाध्यक्षता का भार संभाला बल्कि उसे 2007 में होने वाली अगली बैठक भारत में आयोजित करने का दायित्व भी सौंपा गया। सत्र के दौरान इस दल ने एशियाई प्रशांत पोस्टल कालेज, बैंकाक के शासी निकाय की 9 मई 2006 को आयोजित बैठक में भाग लिया। यह निकाय बजट अनुमोदित करता है तथा संचालित कोर्सों की प्रकृति एवं संख्या तथा क्षेत्र के विभिन्न

seminar on Postal Market and Regulation held in Beijing, China from 26th to 28th April, 2006. The State Post Bureau, People's Republic of China, presently at the stage of reform, organized the seminar in order to share the experiences of other postal administrations in terms of postal reform, postal legislation, market access and regulation, postal safety and security. The Indian delegation made a presentation at the Seminar on the experiences gained on these issues. The seminar was attended by Argentina, USA, Germany, Japan, Russia, China and India.

1.13 Secretary (Posts) attended an annual High Level Conference of Directors General, Chief Executive Officers and government and private sector leaders of various countries, organized by the Universal Postal Union, a specialized agency of United Nations at Berne, Switzerland on 28th April, 2006. The conference was the first of a series of annual conferences on the themes of strategic interest of postal sector decision makers. The Secretary (Posts) participated in the session on the topic 'Can every country retain a national postal enterprise?'. The participation of the Secretary assumed immense significance not only because of the inherent importance of the subject of itself but also because he was invited to present his views in his capacity as the head of the largest postal network in the world.

1.14 Chief General Manager (Business Development) attended a High Level Conference organized by the Universal Postal Union (UPU), a specialized agency of United Nations, on 30th June, 2006. The theme of the conference was "Organizing the postal markets of today and tomorrow". This conference was the second in a series of high-level conferences on strategic interest to postal sector decision-makers being organized by UPU. The conference dealt with matters relating to the changing postal environment, rapid development of new technologies, the emergence of independent regulators, universal service operators as well as globalisation of trade & market integration and the new roles for Governments.

1.15 Assistant Director General (International Relations) attended the 15th Conference of

Commonwealth Postal Administrations (CCPA) held in South Africa from 24 – 28 July, 2006. The theme of the Conference was 'Postal challenges for the next two years'. During the Conference key issues that will challenge the postal community over the next two years were discussed. India Post made an important presentation on Postal Financial Services in India at the Conference.

1.16 General Manager (Marketing), Business Development Directorate, attended a seminar on the 'Future on Retail Business in Post Offices' organized by Asian Pacific Postal Union (APPU) Bureau, in collaboration with La Poste, France, from 22nd to 24th August, 2006 at Bangkok. The main objective of the seminar was to help APPU members to optimize their network in terms of cost and revenue and help them to understand the various ways in which these can be established to grow their postal business.

1.17. Member (Operations & Marketing), Postal Services Board, attended the UPU Strategy Conference held in Dubai from 14th to 16th November, 2006. The meeting offered top-level decision makers from the entire postal sector a unique opportunity to meet and network in a neutral and objective setting. The meeting discussed issues such as: the Postal network and the information society; understanding the industry's changes; the evolving postal network; new market players; sustainable development of the postal sector etc.

Delegations

1.18 A three-member delegation comprising Secretary (Posts), Deputy Director General (International Relations) and Assistant Director General (International Relations) attended the meeting of Asian Pacific Postal Union Executive Council (APPU EC) held from 9th to 13th May, 2006 at Kuala Lumpur, Malaysia. The meeting was extremely important for India Post as India not only assumed the Vice – chairmanship of the Executive Council at this meeting but also going to host the next meeting in 2007. During this session, the delegation attended the meeting of the Governing Board of Asian Pacific Postal College, Bangkok on 9th May, 2006. The

देशों को आर्बटित होने वाली सीटों पर भी निर्णय लेता है। भारत एशियाई प्रशांत डाक सहकारिता का न केवल सदस्य है बल्कि इसके प्रबंधन बोर्ड में भी शामिल है। प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड बैठकों के साथ-साथ कोआपरेटिव जेनरल असेम्बली में भाग लिया जिनमें महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कोआपरेटिव और इसके बिजनेस प्लान के भविष्य पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने टर्मिनल शुल्क कार्य दल, डाक सुरक्षा कार्य दल तथा वित्त समिति, जिसका भारत भी एक सदस्य है, की बैठकों में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने 8 मई, 2006 को 'डाक कुरियर एवं एक्सप्रेस डिलीवरी सेवाओं के वर्गीकरण' पर एक संगोष्ठी में भाग लिया जिसमें डब्ल्यूटीओ के गैट्स में वर्गीकरण विषय पर भिन्न-भिन्न विचार-विन्दुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

1.19 एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका आर.गोपालन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग नेतृत्व कर रहे थे तथा जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, दूरसंचार विभाग एवं डाक विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे, ने जेनेवा में 15 मई से 24 मई, 2006 तक आयोजित गैट्स वार्तालाप के अंतर्गत सेवा समूह पर बहुपक्षीय वार्ता के दूसरे दौर की बैठकों में भाग लिया। उप महानिदेशक, (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) ने डाक विभाग का प्रतिनिधित्व किया तथा 23 मई, 2006 को एक्सप्रेस डिलीवरी के सहित डाक एवं कुरियर सेवाओं से संबंधित बैठक में भाग लिया। बैठक में भारतीय डाक को प्राप्त हुए बहुपक्षीय अनुरोधों पर विचार-विमर्श किया गया। यूएसए इसके समन्वयकों में से एक था तथा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के मसौदा संशोधन विधेयक के कुछेक उपबंधों के बारे में सेवा उद्योग समूह (यूएसए) से एक अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ था। भारतीय प्रतिनिधि ने इस विषय पर भारत के दृष्टिकोण को पुरजोर तरीके से पेश किया।

विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का भारत दौरा

1.20 नई दिल्ली में 18.09.2006 को तीन सदस्यीय कोरियाई प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व कोरिया पोस्ट के अध्यक्ष मि. जूंग येओन ह्वांग कर रहे थे और भारतीय डाक के अधिकारियों, जिसका नेतृत्व सचिव (डाक) कर रहे थे, के बीच बैठक हुई। धन अंतरण सेवाओं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान साधनों (आरएफआईडी) और मानव संसाधन विकास आदि में सहयोग के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

1.21 महानिदेशक, सोनापोस्ट बुरकीना फासो पोस्ट के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु 20-22 नवम्बर, 2006 को भारत का दौरा किया। चर्चा मुख्यतया भारत सरकार की सहायता से ओरुगाडोगू (बुरकीना फासो) में विनिमय कार्यालय/ छंटाई केन्द्र स्थापित करने की परियोजना पर केन्द्रित रही। विदेश मंत्रालय ने बुरकीना फासो द्वारा प्रस्तावित 65%-35% की संशोधित ऋण नीति पर सहमति जतलाई। जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें हार्डवेयर की आपूर्ति, साफ्टवेयर विकास और कर्मचारियों का प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग करना शामिल थे।

1.22 डा. अहमद अल हेफनावी, अध्यक्ष, नीतिगत नियोजन, मिस्त्र डाक की अध्यक्षता में 13 दिसम्बर, 2006 को एक तीन सदस्यीय मिस्त्री प्रतिनिधिमंडल सचिव (डाक) श्रीमती ज्योत्सना धीश से मिला। यह बैठक दोनों देशों के बीच नवम्बर, 2006 में हस्ताक्षरित सहमति पत्र की रूपरेखा के अधीन आयोजित की जा रही थी। इस बैठक में परस्पर सहयोग के संभव मुद्दों जैसे आईएफएस सिस्टम, काउंटर स्वचलीकरण, मानव संसाधन विकास, विनियामक विषयों और फिलैटली पर विचार-विमर्श किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं (आईपीएस) पर प्रशिक्षण

1.23 पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत, गाजियाबाद में 4 से 7 सितम्बर, 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय प्रतिभागियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपीयू के तकनीकी विशेषज्ञ, मि. क्लाउडे गिलेमेन ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन किया। इस कार्य में उन्हें यूपीयू के एशिया एवं प्रशांत के लिए रीजनल सहायता केन्द्र (आरएससीएपी) के मि. सिंग चान हो ने सहायता प्रदान की। प्रशिक्षण में 15 भारतीय प्रतिभागियों के साथ सात विदेशी प्रतिभागियों ने भाग लिया। भारतीय डाक अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डरों के लिए यूपीयू की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा साफ्टवेयर का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए विचार-विमर्श/ प्रस्तुतीकरण देने हेतु एक यूपीयू विशेषज्ञ ने भारत का दौरा किया। चूंकि, भारतीय डाक नेपाल और भूटान के साथ मनीआर्डरों का सबसे अधिक आदान-प्रदान करता है इसलिए, इन देशों के डाक प्रशासनों के महानिदेशकों को भी इस मामले और आपसी सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने हेतु 7.9.2006 को भारत का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

Board approves the budget and takes decisions about nature and number of courses conducted and seats allocated to the various countries of the region. India is a member of the Asia Pacific Post Cooperative and is also on the Management Board of the same. The Board meetings as well as the Co-operative's General Assembly were attended by the delegation where important issues such as the future of the Cooperative and its Business Plan were deliberated. The delegation attended the meetings of the Terminal Dues Working Group, Postal Security Working Group and Finance Committee of which India is a member. The delegation also attended a seminar on 'Classification of Postal, Courier and Express Delivery Services' on 8th May, 2006 where the classification issue in GATS of the WTO was discussed in detail from different standpoints

1.19 An Indian delegation led by Shri R. Gopalan, Joint Secretary, Department of Commerce, consisting of representatives of Ministry of Environment and Forests, Department of Economic Affairs, Department of Telecommunications and Department of Posts attended the meetings of the second round of plurilateral negotiations during services clusters under GATS negotiations at Geneva from 15th May to 24th May, 2006. Deputy Director General (International Relations) represented the Department of Posts and attended the meeting pertaining to the postal and courier services including express delivery on 23rd May, 2006. The meeting discussed the plurilateral requests received by India Post, USA being the coordinator of one of them as well as a representation received from the Coalition of Services Industry (USA) pertaining to some of the provisions of the draft Amendment Bill to the Indian Post Office Act, 1898. The Indian representative put forth India Post's viewpoint on the subject strongly.

Visits of Foreign Delegations

1.20 A meeting between three-member Korean delegation, led by Mr. Joong Yeon Hwang, President, Korea Post and India Post Officers, led by Secretary (Posts), was held in New Delhi on 18.09.2006. Discussions were held on Cooperation in Money Transfer

Services, Radio Frequency Identification Devices (RFID), & Development of Human Resources etc.

1.21 A five-member delegation headed by the DG, SONAPOST Burkina Faso Post visited India from 20-22 November, 2006 to discuss issues of mutual interest. The main topic of discussion centered around the project for setting up an exchange office/sorting center in Ouagadougou (Burkina Faso) with the assistance of the Govt. of India. The Ministry of External Affairs indicated agreement to the revised line of credit of 65%-35% proposed by Burkina Faso. Other issues discussed included co-operation in the fields of supply of hardware, software development and training of officials.

1.22 A three-member Egyptian delegation headed by Dr. Ahmed El Hefnawy, Vice Chairman for Strategic Planning, Egypt Post met Secretary (Post), Ms. Jyotsna Diesh on 13th December, 2006. The meeting was held within the framework of the MoU between the 2 countries signed in November, 2006. In this meeting, issues of possible mutual cooperation such as IFS System, Counter automation HRD, regulatory issues and Philately were discussed.

Training on International Postal Services (IPS)

1.23 A training course on International Postal Services (IPS) software for International as well as Indian participants was organized at Postal Staff College India, Ghazibad from 4th to 7th September, 2006. The UPU technical expert, Mr. Claude Guillemain conducted the training course who was assisted by Mr. Sing Chan Ho from UPU's Regional Support Centre for Asia and Pacific (RSCAP). The training was attended by seven foreign participants along with 15 Indian participants. India Post is considering the induction of UPU's International Financial Services (IFS) software for international money orders. A UPU expert visited India for site survey and discussion / presentation on the same. Since India Post exchanges highest number of money orders with Nepal and Bhutan, the Directors General of postal administrations of these countries were also invited to visit India on 7.09.2006 for discussions on this matter and other areas of mutual cooperation.

टर्मिनल शुल्क परियोजना

1.24 उप महानिदेशक (आईआर) ने 15 से 17 नवम्बर, 2006 तक रबात, मोरक्को में टर्मिनल शुल्क परियोजना दल (टीडीपीजी) के को-चेयर, परियोजना दल-1 (पार्ट-1) तथा इसके कार्यदल की बैठक में भाग लिया। टर्मिनल शुल्क परियोजना दल टर्मिनल शुल्क की वर्तमान प्रणाली से टर्मिनल शुल्क की नई प्रणाली में होने वाले बदलाव के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन कर रहा है। भारतीय डाक ग्रेट ब्रिटेन के साथ परियोजना दल के कार्य दल 13 का सह-अध्यक्ष है। मोरक्को में आयोजित बैठक में को-चेयरों (सह अध्यक्षों) ने लागत, प्रशुल्क, बाजार की परिस्थितियों, विकासपरक सूचकों, सेवा संयोजकता की गुणवत्ता आदि पर किए गए भिन्न-भिन्न अध्ययनों पर अंतिम रिपोर्टें तैयार कीं।

काउंटर स्वचलीकरण परियोजना:

1.25 भारतीय डाक ने यूपीयू की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बांगलादेश, म्यान्मार और नेपाल में जीपीओ के काउंटर स्वचलीकरण की परियोजना शुरू की और पूरी की। इस परियोजना के अंतर्गत इन तीनों देशों के चुने हुए डाकघरों में भारतीय डाक का काउंटर स्वचलीकरण साफ्टवेयर संस्थापित किया गया है और संबंधित स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। परियोजना की कुल लागत यूएस 96,500 डालर है जिसका यूपीयू भारत को भुगतान कर रही है। इसके अतिरिक्त, भारतीय डाक को यूएस 35,600 डालर भी मिलेंगे। यह भारतीय डाक की तरफ से खर्च की गई अतिरिक्त धनराशि थी।

पत्र लेखन प्रतियोगिता

1.26 डाक विभाग विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में साहित्यिक रचना की क्षमता में अभिवृद्धि करने और संचार सुविधाएं प्रदान करने में डाकघर की भूमिका के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कालांतर में यूपीयू पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करता रहा है। इस श्रृंखला में 36वीं यूपीयू पत्र लेखन प्रतियोगिता 7 जनवरी, 2007 को देशभर में आयोजित की गई।

प्रौद्योगिकी

1.27 चालू वर्ष में दिसम्बर, 2006 तक 1979 डाकघर कम्प्यूटरीकृत किए गए। इस तरह, 10वीं पंचवर्षीय योजना के

दौरान डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण की योजना स्कीम के अंतर्गत अब तक 8163 डाकघर कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। इन डाकघरों के लिए जेनरेटर सेटों का प्रापण करने के लिए सर्किलों को धनराशि भी आबंटित की गई है। प्रचालक/कार्यरत प्रणालियों के आधुनिकीकरण की योजना स्कीम के अंतर्गत 270 डाकघरों का आधुनिकीकरण करने के लिए सर्किलों को चालू वर्ष के दौरान 50 मिलियन रु. की धनराशि आबंटित की गई थी।

1.28 दिसम्बर, 2006 में एनआईसी- मुख्यालय, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र स्थापित करने के लिए हार्डवेयर संस्थापित कर दिए गए हैं। इस इन्फ्रास्ट्रक्चर से विभाग को ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्य-वर्धित और प्रीमियम ई-सेवाएं उपलब्ध कराने तथा सुविचारित बिजनेस निर्णय लेने के लिए एमआईएस रिपोर्टें तैयार करने हेतु संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिलेगी। बिजनेस की निरंतरता के लिए एनआईसी सेंटर, हैदराबाद में एक आपदा समाधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जिससे कि मार्च, 2007 तक 1318 कम्प्यूटरीकृत आपरेटिव और प्रशासनिक एवं लेखा कार्यालयों का नेटवर्क स्थापित हो सके। यह नेटवर्क अंतिम छोर तक निकनेट और बीएसएनएल नेटवर्क पर आधारित होगा।

1.29 दिल्ली और कोलकाता में स्वचालित मेल प्रोसेसिंग प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन, प्रचालनारंभ और रख-रखाव के लिए अगस्त, 2006 में विश्व निविदा जारी की गई।

व्यवसाय विकास और विपणन निदेशालय

स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा

1.30 स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा एक ग्राहकोनूकूल स्पीड पोस्ट और रिटेल पोस्ट पैकेज है। विदेश मंत्रालय के सहयोग से डाक विभाग ने 9 मार्च, 2001 से इस सार्वजनिक सेवा को 226 डाकघरों में शुरू किया है। सेवा को 28 सितम्बर, 2006 को और विस्तार दिया गया तथा अब यह देशभर के 1093 स्पीड पोस्ट केन्द्रों/डाकघरों में उपलब्ध है। विदेश मंत्रालय डाकघर में स्वीकार किए गए प्रति आवेदन पत्र 100 रुपये, जो कि ग्राहक द्वारा पहले भुगतान किया जा चुका है, को वापिस अदा करने के लिए सहमत हो गया है।

Terminal Dues Project

1.24 DDG (IR), participated in the meeting of Co-chairs of the Terminal Dues Project Group, (TDPG), Project Team-I (PT-1) and its Working Groups in Rabat, Morocco from 15th to 17th November, 2006. The Terminal Dues Project Group is looking into various aspects of the change over from the current Terminal Dues system to a new system of the Terminal Dues. India Post is Co-chair along with Great Britain of Working Group 13 of the PT-1. In the meeting held in Morocco, the Co-chairs prepared final reports on the different studies carried out on costs, tariffs, market conditions, development indicators, quality of service link etc.

Counter Automation Project

1.25 India Post has undertaken and completed a project of Counter Automation of GPOs in Bangladesh, Myanmar and Nepal under the technical assistance programme of the UPU. Under this project, India Post's counter automation software has been installed in selected Post Offices in these three countries and training has been imparted to the concerned staff. The total cost of the project is US\$ 96,500, which is being paid to India by UPU. In addition to this India Post will also get US\$ 35,600 that was additional expenditure incurred by India Post.

Letter Writing Competition

1.26 The Department of Posts has been conducting the UPU Letter Writing competition over the years in order to enhance the capability of school going children in literary composition and to improve their awareness about the role of Post Office in providing communication facilities. In this series, the 36th UPU Letter Writing competition was held on 7th January, 2007 throughout the country.

Technology

1.27 In the current year, upto December, 2006, 1979 Post Offices were computerized. Thus so far 8163 Post Offices have been computerized under the Plan scheme

of computerization of Post Offices during the 10th Five Year Plan. Funds have also been allotted to the Circles for procurement of Generator sets in these post offices. Funds to the tune of Rs. 50 Million were allotted to the Circles for modernizing 270 Post Offices under the Plan scheme of Modernisation of Operative/Working systems in Post Offices during the current year.

1.28 Hardware for establishment of National Data Centre (NDC) has been installed at NIC-HQ New Delhi in December, 2006. This infrastructure will help the Department to roll out various value-added and premium e-services to the customers and utilize the resources for generation of MIS reports for taking informed business decisions. A Disaster Recovery Centre for business continuity is proposed to be set up at NIC Centre, Hyderabad so as to establish a network of 1318 computerised operative as well as administrative and accounts offices by March, 2007. The network would be based on the NICNET and BSNL Network for the last mile connectivity.

1.29 A Global Tender was floated in August, 2006 for supply, installation, commissioning and maintenance of the Automated Mail Processing Systems at Delhi and Kolkata.

BUSINESS DEVELOPMENT & MARKETING DIRECTORATE

Speed Post Passport Service

1.30 Speed Post Passport Service is a customized package of Speed Post and Retail Post. Department of Posts in alliance with Ministry of External Affairs (MEA) launched this public service with effect from March 9, 2001 in 226 Post Offices. The service was further extended on 28th September 2006 and it is now available in 1093 Speed Post Centres/ Post Offices all over the country. MEA has agreed to reimburse Rs. 100 per application accepted in Post Office, which was earlier paid by the customers.

स्पीड पोस्ट- सम्पूर्ण भारत में एक दर

1.31 स्पीड पोस्ट की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर 21.8.2006 से स्पीड पोस्ट-सम्पूर्ण भारत में एक दर के लिए नई घरेलू प्रशुल्क संरचना शुरू की गई। 1 जनवरी, 2007 को राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 186 कर दी गई।

संगोष्ठी एवं सम्मेलन

1.32 समग्र व्यवसाय समाधान पर भारतीय डाक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में 18 अक्टूबर, 2006 को किया गया। सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक, आईसीआईसीआई, बीएसएनएल, आईएमसी, रीडर्स डाइजेस्ट, भारतीय स्टेट बैंक, यूटीआई और अन्य कई संगठनों ने भाग लिया।

1.33 सामान्य सेवा केन्द्र तथा ई-कामर्स की स्थापना के लिए 18 नवम्बर, 2006 को जयपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें उत्तरी और पश्चिमी सर्किलों के अध्यक्षों ने भाग लिया। सचिव (डाक) और सदस्य (प्रचालन एवं विपणन) ने डाकघरों को ई-गवर्नेंस के लिए एक ही स्थान पर समग्र समाधान के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। अब तक देहरादून (उत्तरांचल), जयपुर (राजस्थान) तथा गुवाहाटी (असम) में तीन सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। देशभर में इस प्रकार सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने के प्रयास जारी हैं।

1.34 डाक प्रचालन संबंधी सभी कार्यों को शामिल करते हुए डाक विभाग और बीएसएनएल के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर 28 दिसम्बर, 2006 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

1.35 रिटेल पोस्ट कार्यकलापों के एक भाग के रूप में डाक विभाग ने 26.7.2006 से 1879 डाकघरों के माध्यम से आयकर विवरणी भरने के लिए वित्त मंत्रालय से गठजोड़ किया है। डाकघरों के माध्यम से 31 अक्टूबर, 2006 तक भरी गई आयकर विवरणियों की कुल संख्या 4,12,278 है। दिल्ली में डाकघरों के माध्यम से सेवा कर आवेदनपत्र/विवरणियां भी एकत्र की जा रही हैं। इस स्कीम का अन्य सर्किलों में भी विस्तार करने की योजना है। खूबसूरती से डिजाइन किए गए राखी के लिफाफे भी डिजाइन और निर्मित किए गए तथा 14 जुलाई, 2006 से देशभर में बेचे गए। इससे भारतीय डाक को काफी प्रशंसा और व्यवसाय के अवसर मिले।

1.36 भारतीय डाक ने त्यौहारों के अवसर के लिए ई-पोस्ट बधाई की नई श्रृंखला का शुभारंभ किया है। क्रिसमस, नव वर्ष, ईद, पोंगल, मकर संक्रान्ति और गणतंत्र दिवस के लिए ई-कार्डों की व्यापक श्रृंखला जारी की गई। ई-भुगतान साफ्टवेयर भी प्रारंभ किया गया और बड़े सर्किलों में संस्थापित किया गया।

आंतरिक कार्य अध्ययन

1.37 डाकियों के लिए नए मानदंड विकसित करने तथा बचत बैंक नेटवर्क के लिए कम्प्यूटरीकृत मानदंड बनाए जाने के संबंध में अध्ययन पूर्ण कर लिया गया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुभाग का 12 से 16 जून, 2006 तक कार्य-मापन अध्ययन किया गया और रिपोर्ट जारी कर दी गई। डीएए अनुभाग का भी कार्य-मापन अध्ययन किया गया तथा अनुमोदित रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। उप डाकघरों तथा डाक एवं तार औषधालयों में आरडी एवं एमआईएस कार्य के विकेन्द्रीकरण के कार्य-अध्ययन को मार्च, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा। डीएए अनुभाग की कार्य-अध्ययन रिपोर्ट इस वित्त वर्ष में जारी कर दी जाएगी।

वित्तीय सेवाएं

तत्काल मनीआर्डर

1.38 तत्काल मनीआर्डर (आई.एम.ओ.) सेवा देश के 24 डाकघरों में 20 जनवरी, 2006 को शुरू की गई थी। यह स्कीम 60 डाकघरों में उपलब्ध है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक 500 डाकघरों में इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है।

सामाजिक लाभ योजना

1.39 डाक विभाग ने आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में बचत बैंक खातों के माध्यम से भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान करने के कार्य में पहल की है। 15 जनवरी, 2007 तक इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 3.4 मिलियन डाकघर बचत बैंक खाते खोले जा चुके हैं।

डाक वित्त मार्ट और बचत बैंक कम्प्यूटरीकरण

1.40 डाक वित्त मार्ट के अंतर्गत प्रतिष्ठित बैंकिंग संस्थाओं के समान प्रौद्योगिकी चालित पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत कार्यालय में वित्तीय सेवाओं के लिए वन-स्टॉप-शॉप यानि एक ही स्थान पर विभाग के सभी वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान किए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष में सभी सर्किलों को 162 डाक वित्त मार्ट का लक्ष्य आबंटित किया गया। 5.0 संचय पोस्ट साफ्टवेयर का उन्नत रूपांतरण उन सभी डाकघरों में प्रचालित करने का प्रस्ताव है जहाँ इसका पूर्व रूपांतरण पहले से प्रयोग में है। इसके अलावा नए वित्त वर्ष के प्रारंभ से इस 5.0 रूपांतरण को 4000 और नए डाकघरों में शुरू करने का प्रस्ताव है।

Speed Post-One India One Rate

1.31 On the occasion of 20th anniversary of Speed Post the new domestic tariff structure for Speed Post-One India One Rate has been introduced w.e.f. 21.08.2006. As on 1st January, 2007 the number of National Speed Post Centres has been increased to 186.

Summits and Conferences

1.32 India Post summit on Total Business solutions was held at Mumbai on 18th October 2006. The Summit was attended by representatives from RBI, ICICI, BSNL, IMC, Readers Digest, SBI, UTI, and host of other organizations.

1.33 A conference on setting up of Common Service Centres and e-commerce was held at Jaipur on 18th November 2006, in which Heads of Northern and Western Circles participated. Secretary (Posts) and Member (O & M) emphasized the need for making Post Offices as one stop solution for e-governance. So far, three Common Service Centres (CSCs) have been established at Dehradun (Uttaranchal), Jaipur (Rajasthan) and Guwahati (Assam). Efforts are being made to establish such CSCs across the country.

1.34 A Memorandum of Understanding (MOU) was signed between Department of Posts and BSNL on 28th December 2006 on bilateral issues covering the entire gamut of Postal operations.

1.35 As part of Retail Post activities, Department of Posts has tied up with Ministry of Finance for filing of Income Tax (IT) Returns through 1879 Post Offices with effect from 26.07.2006. Total number of IT Returns filed through Post Offices till 31st October 2006 were 4,12,278. Service Tax applications/ returns are also being collected through Post Offices in Delhi. Plans for extending this scheme to other Circles is on the anvil. Aesthetically designed Rakhi envelopes were designed, produced and sold across the country from 14th July 2006, which has created favourable response and business opportunity for India Post.

1.36 India Post has launched new range of e-Post greetings for festive occasions. Wide range of e-cards for Christmas, New Year, Eid, Pongal, Makar Sankranti, and Republic Day have been issued. e-Payment software has been launched and installed in major Circles.

Internal Work Study

1.37 The study of evolution of new norms for Postmen and the study for evolution of computerized norms for Savings Bank Network has been completed and the report is submitted. The work measurement study of IR Section was conducted from 12th to 16th June, 2006 and report has been issued. Work measurement study of DAA Section has been completed and the approved report would be issued. The work-study of decentralization of RD & MIS work in sub post offices and P & T Dispensaries would be completed by March, 2007. The work-study report of DAA Section would be issued in this financial year.

FINANCIAL SERVICES

Instant Money Order (iMO)

1.38 Instant Money Order (iMO), service was introduced on 20th January, 2006 in 24 Post Office locations in the country. The scheme is available in 60 post offices and to be extended to 500 post offices by the end of the current financial year.

Social Benefit Scheme

1.39 The Department of Post has taken an initiative to implement National Rural Employment Guarantee Scheme of Government of India by way of payment of wages through Savings Bank account in the states of Andhra Pradesh, Jharkhand, Karnataka and West Bengal. Till January 15, 2007, about 3.4 Million Post Office Saving Bank accounts have been opened under this scheme.

Postal Finance Mart and Saving Bank Computerisation

1.40 The Postal Finance Mart (PFM) seeks to offer all the financial products and services of the Department under one roof – “One Stop Shop for Financial Services” in a fully computerized office supported by technology at par with reputed banking institutions. In the current financial year, a target of 162 PFMs has been allotted to all the Circles. The upgraded version of 5.0 Sanchay Post Software is proposed to be made operational in offices where its earlier versions were in use. Apart from this, it is proposed to roll out this 5.0 version in 4000 more new post offices from start of the new financial year.

डाक जीवन बीमा

1.41 वर्ष 2006-07 के लिए व्यवसाय लक्ष्य तथा अप्रैल से दिसम्बर, 2006 तक प्राप्त किया गया व्यवसाय नीचे दिया गया है।

तालिका-14			
डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यवसाय : 2006-2007			
श्रेणी	लक्ष्य (मिलियन रु. में)	उपलब्धि (दिसम्बर 2006 तक)	
		पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (मिलियन रु. में)
डाक जीवन बीमा	73,550	183,909	23988.8
ग्रामीण डाक जीवन बीमा	145,850	459,946	31770.6

कर्मचारी संबंध

1.42 इस अवधि के दौरान विभाग ने अपने कर्मचारियों के परिसंघों एवं यूनियनों/संघों के साथ सार्थक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का प्रयत्न किया है। विभागीय परिषद की एक बैठक डाक विभाग में 1 जून, 2006 को आयोजित की गई। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में की गई जहाँ कार्यसूची की सभी मदों पर सूक्ष्मता एवं कर्मचारी पक्ष की सहमति से चर्चा की गई। बैठक में हुई सहमतियों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। नकदी संचालन भत्ते पर माध्यस्थम बोर्ड के अधिनिर्णय पर चर्चा हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सुझाव पर विभागीय परिषद की एक विशेष बैठक 19.07.2006 को आयोजित की गई जिसमें डाक स्टाफ (i) जो नियमित कार्य के रूप में नकदी संचालन की काउन्टर ड्यूटी करता है (ii) जो नियमित रूप से वेतन/बिल/पेंशन के वितरण का कार्य करते हैं (कोषाध्यक्ष/सहायक कोषाध्यक्ष को छोड़कर) के संबंध में नकदी संचालन भत्ते पर चर्चा की गई।

1.43 विभाग ने स्टाफ पक्ष के साथ 10.04.2006 को एक बैठक की जिसमें उन्हें 'डाक आउटलेटों की फ्रैंचाइजिंग की योजना की शुरुआत' के प्रस्ताव की जानकारी दी गई। 03.11.2006 को आयोजित अगली बैठक में यूनियन द्वारा अभिव्यक्त की गई आशंकाओं पर स्पष्टीकरण दिया गया।

1.44 1999-2000 में शुरु की गई सत्यापन प्रक्रिया के परिणाम

जारी करने के संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (1999 को अधिरोपित) के रद्द करने के क्रम में विभाग ने 30.06.2006 को सेवा संघों की सीसीएस (आरएसए) नियमावली 1993 तथा ईडीए (आरए) नियमावली 1995 के अनुसार मान्यता हेतु आदेश जारी किए। ऐसे प्रदान की गई मान्यता 2 वर्षों के लिए वैध होगी।

1.45 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 की उपधारा (i) के अनुसार राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ तथा उसकी संबद्ध यूनियनों ने 14.12.2006 को एक दिन की सामान्य हड़ताल के लिए एक नोटिस दिया। हड़ताल का नोटिस 14 दिसम्बर, 2006 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एक भाग था जिसके लिए ट्रेड यूनियनों की प्रायोजक समिति ने केन्द्र सरकार की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में तथा अपनी 16 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए आह्वाहन किया था। अन्य दो परिसंघों राष्ट्रीय डाक संगठन परिसंघ तथा भारतीय डाक कर्मचारी परिसंघ ने इस हड़ताल में भाग नहीं लिया।

1.46 राष्ट्रीय डाक कर्मचारी परिसंघ, राष्ट्रीय डाक संगठन परिसंघ तथा उनकी संबद्ध यूनियनों की सचिव (डाक) के साथ अगली आवधिक बैठक फरवरी 2007 के माह में आयोजित होना अपेक्षित है। डाक विभाग में परिसंघों को मान्यता देने की प्रक्रिया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से विचाराधीन है जिसके मार्च 2007 तक पूरा होने की संभावना है। विभागीय परिषद की अगली बैठक अप्रैल/मई 2007 में होनी प्रस्तावित है।

Postal Life Insurance

1.41 The Business targets for the year 2006-07 and business secured from April to December, 2006 are detailed below: -

Table 14			
PLI/RPLI BUSINESS: 2006-07			
Category	Target (Rs. in Million)	Achievement (Up to December, 2006)	
		No. of Policies	Sum Assured (Rs. in Million)
PLI	73,550	183,909	23988.8
RPLI	145,850	459,946	31770.6

Staff Relations

1.42 During the period, the Department endeavoured to maintain harmonious and meaningful relations with the federations and Unions/Associations of its employees. A meeting of Department Council in the Department of Posts was held on 1st June, 2006. The meeting was held in a congenial atmosphere wherein all agenda items were discussed threadbare and in mutual agreement with the Staff Side, as per spirit of the scheme. Necessary follow up action is being taken on the agreements reached in the meeting. A special meeting of Departmental Council, on the advice of Department of Personnel and Training, was held on 19-07-2006 to discuss the Board of Arbitration Award dealing with cash handling allowance to postal staff: (i) who attend counter duties to handle cash as regular measure; (ii) those engaged in disbursing salaries/bills/pension as a regular measure (excluding treasurer/assistant treasurer).

1.43 The Department had a meeting with the staff side on 10-04-2006 to apprise them of the proposal for "Initial Launch of a Scheme for Franchising Postal Outlets". In the next meeting held on 3-11-2006 the reservations expressed by Union were clarified.

1.44 As a sequel to the vacation of a stay order (imposed in 1999) by Hon'ble High Court of Madras regarding release of results of the verification process

initiated in 1999-2000, the Department issued orders on 30-06-2006 for recognition of Service Associations in terms of CCS (RSA) Rules, 1993 and EDA (RA) Rules, 1995. The recognition so granted will be valid for 2 years.

1.45 National Federation of Postal Employees (NFPE) and its affiliated unions gave a notice for observing a one-day general strike on 14-12-2006 in terms of sub section (1) of Section 22 of Industrial Disputes Act, 1947. The strike notice was a part of nation wide general strike on December 14, 2006, which was called by Sponsoring Committee of Trade Unions in protest against the alleged anti-working class policies of the Union Government and to press for their 16 points charter of demands. The other two federations, namely Federation of National Postal Organisation and Bharatiya Postal Employees Federation, did not participate in the strike.

1.46 The next periodical meeting of National Federation of Postal Employees, Federation of National Postal Organisation and their affiliated Unions with Secretary (Posts) is expected to be held in the month of February, 2007. The recognition of Federations in the Department of Posts is under active consideration in consultation with Department of Personnel & Training, which is likely to be finalised by March, 2007. The next meeting of the Departmental Council is proposed to be held in April/May, 2007.

मेघदूत पुरस्कार

1.47 वर्ष 2006 के लिए 7 एकल वर्गों में मेघदूत पुरस्कार देने का निर्णय किया गया है। पुरस्कार में एक स्कॉल, करीब 5000 रु. का एक स्वर्ण स्मारक तथा 11,000 रु. का एक नकदी पुरस्कार सम्मिलित है।

खेलकूद

1.48 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2006 तक की अवधि के लिए 7 खेलों में अखिल भारतीय डाक टूर्नामेंट आयोजित किया गया अर्थात् शतरंज, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, फुटबॉल तथा कैरम। 01.01.2007 से 31.03.2007 की अवधि में 7 वर्गों में अखिल भारतीय डाक टूर्नामेंट आयोजित करने का प्रस्ताव है अर्थात् बैडमिंटन, क्रिकेट, एथलेटिक्स/साइक्लिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम/भारोतोलन/ पावर लिफ्टिंग/सर्वश्रेष्ठ शारीरिक सौष्ठव, वालीबॉल एवं कुश्ती।

चिकित्सा सुविधाएं

1.49 कल्याण कार्य के तौर पर डाक विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में 45 शहरों/कस्बों में 52 डाक औषधालय चला रहा है। पात्र लाभार्थियों को ये औषधालय बाह्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। जहां कहीं भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां डाक विभाग तथा दूरसंचार विभाग के कर्मचारी व पेंशनर डाक औषधालय सुविधाओं के हकदार हैं।

जन शिकायतें

1.50 सितम्बर, 2006 तक 4,71,098 कुल जन शिकायतें प्राप्त हुईं तथा 4,13,495 कुल मामले निपटाए गए। विभाग ने अपने पूरे नेटवर्क में सेवा की गुणवत्ता तथा ग्राहक सेवा में व्यवस्थित सुधार लाने के लिए शुरुआत की है। विभाग ने 'सेवोत्तम' अपनाया है जो कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित एक 'सेवा वितरण उत्कृष्टता मॉडल' है जो सिटिजन चार्टर, जन शिकायत व्यवस्था तथा सेवा वितरण क्षमताओं के क्षेत्र में सुधार करने पर बल देता है। यह शुरुआत मई 2006 से नई दिल्ली प्रधान डाकघर तथा अलवर प्रधान डाकघर में मौजूदा सेवा मानकों की ग्राहक की आशाओं के साथ तुलना के गहन अध्ययन से हुई। जुलाई 2006 में 600 से अधिक यूनिटें पूरे देश में 'सेवोत्तम' के कार्यान्वयन के

लिए पहचानी गईं। एक विस्तृत कार्य योजना विकसित की गई है तथा जिन क्षेत्रों पर सेवोत्तम मॉडल में अधिक बल दिया गया है, उन पर तथा विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों की दक्षता को बढ़ाया जा रहा है। इन शुरुआतों से विभाग ग्राहक की आवश्यकताओं को एक बड़ी सीमा तक संतुष्ट करने की आशा करता है। विभाग सेवा वितरण में सुव्यवस्थित सुधार लाने वाला एक अग्रणी संगठन हो गया है जो कि वर्तमान में सरकार द्वारा महत्व दिए जा रहे प्रमुख क्षेत्रों में से है।

मानव संसाधन विकास

पोस्टल स्टाफ कालेज

1.51 पोस्टल स्टाफ कालेज ने 9 प्रवेशकालीन प्रशिक्षण तथा 18 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 409 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 182 अधिकारियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्याशित है कि 25 और अधिकारियों को प्रवेशकालीन प्रशिक्षण तथा 01.01.2007 से 31.03.2007 तक विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 90 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

1.52 दिनांक 04.09.2006 से 06.09.2006 तक अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रणाली सॉफ्टवेयर पर यूपीयू द्वारा प्रायोजित एक पाठ्यक्रम (कोर्स) का आयोजन किया गया। पाठ्यक्रम में 20 अधिकारियों ने भाग लिया जिनमें भूटान, श्रीलंका, थाइलैंड, जापान, कंबोडिया से एक तथा मालदीव से दो अधिकारी शामिल हुए। ई-प्रशासन और प्रौद्योगिकी प्रबंधन में एक सप्ताह के पाठ्यक्रम को आयोजित किया गया। भागीदारों में से एक भागीदार वियतनाम डाक विभाग से था।

विदेश में प्रशिक्षण

1.53 01.04.2006 से 31.12.2006 तक एशियाई प्रशांत कालेज बैंकाक में विभिन्न विषयों पर 11 भारतीय डाक सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 01.01.2007 से 31.03.2007 तक और 4 अधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने के लिए विदेश भेजा जाना है।

डाक प्रशिक्षण केन्द्र

1.54 संदर्भित अवधि के दौरान छह डाक प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल 7,985 और 9,452 कर्मचारियों को सेवाकालीन/प्रवेशकालीन

Meghdoot Awards

1.47 It has been decided to give the Meghdoot Awards for the year 2006 in seven individual categories. The award comprises of a scroll, a gold sovereign of about Rs. 5000/- and cash award of Rs. 11,000/-.

Sports

1.48 During the period from 1st April to 31st December, 2006, All India Postal Tournaments in 7 events viz. Chess, Hockey, Basketball, Kabaddi, Table Tennis, Football, and Carrom were organized. In the period from 1.1.2007 to 31.3.2007 it is proposed to organize All India Postal Tournaments in 7 events viz. Badminton, Cricket, Athletics/Cycling, Cultural, Weighlifting/Powerlifting/Best Physique, Volleyball and Wrestling.

Medical Facilities

1.49 As a welfare measure, Department of Posts is running 52 Postal Dispensaries in 45 cities/towns in various parts of the country. These dispensaries extend out-door treatment facilities to the eligible beneficiaries. All employees and pensioners of the Department of Posts and Department of Telecom are entitled to Postal Dispensary facilities, wherever such facilities are available.

Public Grievances

1.50 Up to September, 2006, total 4,71,098 cases of public grievances were handled and a total of 4,13,495 cases were settled. The Department has taken up an initiative to bring about systematic improvement in quality of service and customer care through out its network. It has adopted “Sevottam” – a Service Delivery Excellence Model developed by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, which stresses upon improvement in the areas of Citizens Charter, Public Grievance Mechanism and Service Delivery Capabilities. The initiative started with an intensive study of existing service standards vis-à-vis customer expectations, in New Delhi Head Post Office and Alwar Head Post

Office from May, 2006 onwards. In July, 2006 more than 600 units have been identified all over the country for implementation of “Sevottam”. A detailed Action Plan has been developed and the skills of the personnel at various levels are being enhanced with a special focus on the areas stressed in the “Sevottam” model. Through these initiatives, the Department hopes to satisfy customer needs to a great extent. The Department has become a pioneer in bringing about systematic improvement in delivery of service, which is a thrust area of the Government today.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Postal Staff College

1.51 The Postal Staff College conducted 9 Induction and 18 in-service training programmes, in which 409 officers participated. Besides, 182 officers were imparted computer training during the period. It is anticipated that an additional 25 officers would be imparted induction training and 90 officers would be trained on various computer-training programmes from 01.01.2007 to 31.03.2007.

1.52 A UPU sponsored course on International Postal System software was conducted from 4.09.2006 to 6.09.2006. 20 officers participated in the course, including one each from Bhutan, Srilanka, Thailand, Japan, Combdia and two from Maldives. A one week course on e-governance and Technology Management was conducted. Among the participants, one participant was from Vietnam Post.

Training Abroad

1.53 11 Indian Postal Service Officers were trained on various subjects at Asia Pacific Postal College Bangkok from 1.4.2006 to 31.12.2006 and 4 more officers are likely to be sent for training abroad during 1.1.2007 to 31.3.2007.

Postal Training Centres

1.54 A total number of 7,985 officials were imparted in-service/induction training and 9,452 officials were

प्रशिक्षण व कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 2343 कर्मचारियों को प्रवेश तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 2260 कर्मचारियों को चालू वित्त वर्ष के शेष भाग में कम्प्यूटर में प्रशिक्षित किया जाएगा।

कार्यस्थल पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधाएं (डब्ल्यू सीटीसी)

1.55 दिसम्बर, 2006 तक 60 डब्ल्यूसीटीसी द्वारा कुल 15,563 कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया। आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान और 7,500 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्थापना

1.56 श्रीमती ज्योत्सना धीश (भा. डा. सेवा-1969) को 30.06.2006 के अपराह्न से सचिव डाक विभाग, महानिदेशक (डाक) और पदेन अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड नियुक्त किया गया। श्रीमती ज्योत्सना धीश के सेवानिवृत्त होने के बाद श्री आई.एम.जी. खान (भा. डा. सेवा-1970) को दिनांक 31.12.2006 के अपराह्न से सचिव, डाक विभाग, महानिदेशक (डाक) और पदेन अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड नियुक्त किया गया। श्रीमती वत्सला रघु (भा. डा. सेवा-1970) और श्री डी. कैलासा प्रसाद (भा. डा. सेवा-1971) को सदस्य, डाक सेवा बोर्ड के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। तीन उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों को प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। 6 वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों को वरिष्ठ उप महानिदेशक/ मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। सात कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया। 10 एसटीएस अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत किया गया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित चौदह उम्मीदवारों को भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में नियुक्ति, प्रदान की गई। भारतीय डाक सेवा समूह 'क' (2004 बैच) के सात परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर स्वतंत्र प्रभार दिया गया। निरीक्षक

लाइन के 133 अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पीएस समूह ख के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। सेना डाक सेवा में कार्यरत 11 अधिकारी कर्नल के रैंक में पदोन्नत किए गए। 14 पीएस समूह ख अधिकारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई। एक सामान्य लाइन अधिकारी को पीएस समूह ख में पदोन्नत किया गया। 9 अधिकारियों को जीसीएस समूह ख ग्रेड में पदोन्नत किया गया था।

राजभाषा

1.57 दिसम्बर 2006 तक संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने कोड्डाईकोनाल, कसौली और कालका के डाकघरों तथा वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर कोटा एवं पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, कोच्चि का निरीक्षण किया।

1.58 राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2006-07 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसरण में विभाग के अधिकारियों द्वारा 10 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। राजभाषा पर संसदीय समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने विभाग के सात विभिन्न कार्यालयों के अध्यक्षों के साथ विचार विमर्श किया।

1.59 विभाग में 14 सितम्बर, 2006 को हिन्दी दिवस मनाया गया और 14 से 28 सितम्बर, 2006 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए।

सामग्री प्रबंधन

1.60 चमड़े के नकदी थैले, हैसियन गनी थैले, स्वतः- सूचक वजन तोलने की मशीनें, काली निरसन स्याही और विभिन्न प्रकार के थैलों की अधिप्राप्ति को डाक सर्किलों में विकेन्द्रीकृत किया गया। तथापि, अधिप्राप्ति, जहाँ भी उपलब्ध हो, डीजीएसएंडडी/दर संविदा के माध्यम से की जा रही है, अन्यथा डीएफआर, डीएफपीआर, डाक मैन्यूअल खण्ड-1। में तथा समय-समय पर जारी अन्य संगत अनुदेशों में यथानिर्दिष्ट औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है।

imparted computer training by the six Postal Training Centers during the reference period. It is anticipated that an additional number of 2,343 officials would also be imparted Induction and In-service training and 2,260 officials will be trained on computer skills during the remaining period of current financial year.

Work Place Computer Training Facilities (WCTCs)

1.55 By December, 2006, a total number of about 15,563 officials were imparted training on computers by 60 WCTCs. It is anticipated that an additional number of about 7,500 officials would be imparted training during the current financial year.

Establishment

1.56 Smt. Jyotsna Diesh (IPoS-1969) was appointed Secretary, Department of Posts, Director General (Posts) and ex-officio Chairman, Postal Services Board in the after noon of 30.06.2006. After the retirement of Smt. Jyotsna Diesh, Shri I.M.G. Khan (IPoS-1970) was appointed Secretary, Department of Posts, Director General (Posts) and ex-officio Chairman, Postal Services Board in the after noon of 31.12.2006. Smt. Vatsala Raghu (IPoS-1970) and Shri D. Kailasa Prasad (IPoS-1971) were promoted to the grade of Member, Postal Services Board. Three HAG officers were promoted to the grade of Principal CPMG. Six SAG officers were promoted to the grade of Sr.DDG/CPMG. Seven JAG officers were promoted to the grade of SAG. Ten STS officers were promoted to the grade of JAG. Fourteen candidates recommended by UPSC were offered appointment in Junior Time Scale of Indian Postal Service Group 'A'. Seven probationers of Indian Postal Service Group 'A' (2004 batch) were given independent charge after completion of training. 133 Inspector's line officials were promoted to the grade of PS Group 'B' through DPC. Eleven Officers serving in Army Postal Service were

promoted to the rank of Colonel. Fourteen PS Group 'B' officers were given proforma promotion. One General Line Official was promoted to the grade of PS Group 'B'. Nine officials were promoted to the GCS Group 'B' grade,

Official Language

1.57 Up to December, 2006, the second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language carried out inspections in Post Offices of Kodaikanal, Kasauli and Kalka; Senior Superintendent of Post Office, Kota and Postmaster General Office, Kochi.

1.58 In pursuance of the directives laid down in the Annual Programme 2006-07 issued by the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs), ten offices have been inspected by the officers of the Department. The Drafting and Evidence Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language held discussions with the heads of the seven different offices of the Department.

1.59 Hindi Diwas was observed in the Department on 14th September, 2006 and Hindi Fortnight was observed from 14th to 28th September, 2006. Prizes were distributed to the winners of various competitions held during the Hindi Fortnight.

Material Management

1.60 Procurement of Leather Cash Bags, Hessian Gunny Bags, Self-indicating Weighing Scales, Black Cancellation Ink and Different Types of Bags was decentralized to the Postal Circles. However, procurement is being made through DGS&D/Rate Contract, wherever available, otherwise formalities as laid down in DFR, DFPR, Postal Manual Volume II and other relevant instructions issued from time to time are being followed.

अनुबंध

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

डाक विभाग के कार्यकरण पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है:-

1. **रसीदी डाक टिकटों की खरीद पर कमीशन की कटौती न होना** – 13 डाक सर्किलों के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल रसीदी डाक टिकटों की खरीद पर राज्य सरकारों से 3.85 करोड़ रुपए का कमीशन काटने में विफल रहे।

(2006 की रिपोर्ट सं. 2)

2. **डाक जीवन बीमा पालिसियों पर बोनस का अधिक भुगतान** – परिपक्वता पूर्व अभ्यर्पित की गई डाक जीवन बीमा पालिसियों पर बोनस के भुगतान के संबंध में अनुदेशों के कार्यान्वयन न होने के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 2)

3. **डाक प्रभारों की कम वसूली** – दिल्ली डाक सर्किल के अंतर्गत एक प्रधान डाकघर, कर्नाटक डाक सर्किल के अंतर्गत दो डाकघर और उत्तर प्रदेश डाक सर्किल के अंतर्गत एक मुख्य डाकघर ने अपठनीय प्रकाशनों

को रियायती प्रशुल्क प्रदान किया जिसके परिणामस्वरूप 31.58 लाख रुपये के डाक प्रभार की कम वसूली हुई।

(2006 की रिपोर्ट सं. 2)

4. **ब्याज का अनियमित भुगतान** – उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में डाकघर तथा मुंबई में एक प्रधान डाकघर मासिक आय योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में निर्धारित मौद्रिक सीमा सुनिश्चित करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा में तीन डाकघरों ने ऐसे खाते खोलने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों को अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप 21 लाख रुपये के ब्याज, बोनस और कमीशन का अनियमित भुगतान हुआ।

(2006 की रिपोर्ट सं. 2)

5. **निष्क्रिय खातों पर सेवा प्रभार की कटौती न होना** – असम, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल डाक सर्किलों के अंतर्गत एक मुख्य डाकघर और 10 प्रधान डाकघरों द्वारा मार्च 2002 से पूर्व निष्क्रिय खातों के तौर पर माने गए खातों पर सेवा प्रभार लागू करने में विफल होने के परिणामस्वरूप 15.74 लाख रुपए के सेवा प्रभार की कटौती हुई।

(2006 की रिपोर्ट सं. 2)

ANNEXURE

AUDIT OBSERVATIONS OF C&AG

Summary of audit observations on the working of Department of Posts provided by C&AG is as follows:-

1. Non-deduction of commission on purchase of revenue stamps: The Chief Postmasters General of 13 Postal Circles failed to deduct commission amounting to Rs. 3.85 crores on purchase of revenue stamps from State Governments.

(Report No. 2 of 2006)

2. Overpayment of bonus on Postal Life Insurance policies: Non-implementation of instructions in respect of payment of bonus on Postal Life Insurance policies surrendered before maturity resulted in overpayment of Rs.1.01 crore.

(Report No. 2 of 2006)

3. Short realization of postal charges: A Head Post Office under the Delhi Postal Circle, two Post Offices under the Karnataka Postal Circle and one General Post Office under the Uttar Pradesh Postal Circle authorized concessional tariffs to ineligible

publications, resulting in short realization of postage charges of Rs. 31.58 lakh.

(Report No. 2 of 2006)

4. Irregular payment of interest: Post Offices in Orissa and Uttar Pradesh and one Head Post Office in Mumbai failed to ensure the prescribed monetary ceiling in the accounts opened under the Monthly Income Scheme. Besides, three Post offices in Orissa allowed unauthorized agencies to open such accounts. This resulted in irregular payment of interest, bonus and commission amounting to Rs. 21 lakhs.

(Report No. 2 of 2006)

5. Non-deduction of service charges on silent accounts: Failure of one General Post Office and 10 Head Post Offices under the Assam, Karnataka, Rajasthan and West Bengal Postal Circles to levy service charges on accounts treated as silent accounts prior to March 2002 resulted in non-deduction of service charges to the tune of Rs. 15.74 lakh.

(Report No. 2 of 2006)

तालिका - 15

कार्मिक - 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार वास्तविक संख्या

(विभाग के बाहर प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण पर गए कर्मचारियों को मिलाकर)

क. विभागीय राजपत्रित	समूह 'क'	समूह 'ख'	कुल
भारतीय डाक सेवा समूह 'क'			
सचिव (डाक),	1	-	1
सदस्य, डाक सेवा बोर्ड	2	-	2
प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल	3	-	3
वरिष्ठ उपमहानिदेशक/मुख्य पोस्टमास्टर जनरल	23	-	23
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	60	-	60
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	140	-	140
वरिष्ठ समयमान	74	-	74
कनिष्ठ समयमान	204	-	204
डाक सेवा समूह 'ख'	-	755	755
सहायक अधीक्षक	-	1708	1708
डाक तार लेखा एवं वित्तीय सेवा			
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	4	-	4
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	22	-	22
वरिष्ठ समयमान	25	-	25
कनिष्ठ समयमान	19	-	19
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी	-	248	248
सहायक लेखा अधिकारी	-	617	617
केन्द्रीय सचिवालय सेवा	25	68	93
सिविल विंग			
मुख्य अभियंता	2	-	2
अन्य	49	130	179
अन्य सामान्य केन्द्रीय सेवा	127	83	210
कुल (राजपत्रित)	780	3609	4389
ख. समूह 'ख' (अराजपत्रित)	-	3496	3496
ग. अराजपत्रित	समूह "ग"	समूह "घ"	कुल
निदेशालय	265	138	403
डाकघर (सर्किल कार्यालय, लेखा, स्टांप डिपो एवं कैंटिन स्टाफ सहित)	160776	26683	187459
रेल मेल सेवा	18987	13194	32181
मेल मोटर सेवा	1601	403	2004
अन्य (आरएलओ, औषधालय, भंडार, प्रशिक्षण सिविल डाक जीवन बीमा एवं प्रेस)	2440	1815	4255
कुल (अराजपत्रित)	184069	42233	226302
कुल विभागीय (क+ख+ग)			234187
घ. ग्रामीण डाक सेवक			286004
कुल योग (क+ख+ग+घ)			520191

Table 15
Personnel: Actual strength as on 31.3.2006
(including those on deputation and training outside the Department)

DEPARTMENTAL			
A. GAZETTED	GROUP "A"	GROUP "B"	TOTAL
INDIAN POSTAL SERVICE GROUP "A"			
Secretary (Posts)	1	-	1
Member, Postal Services Board	2	-	2
Principal Chief Postmaster General	3	-	3
Sr.DDG/Chief PMG	23	-	23
Senior Administrative Grade	60	-	60
Junior Administrative Grade	140	-	140
Senior Time Scale	74	-	74
Junior Time Scale	204	-	204
POSTAL SERVICE GROUP "B"	-	755	755
Assistant Supdt.	-	1708	1708
P & T ACCOUNTS & FINANCE SERVICE			
Senior Administrative Grade	4	-	4
Junior Administrative Grade	22	-	22
Senior Time Scale	25	-	25
Junior Time Scale	19	-	19
Senior Accounts Officer/Accounts Officer	-	248	248
Asstt. Accounts Officer	-	617	617
CENTRAL SECRETARIAT SERVICE	25	68	93
CIVIL WING			
Chief Engineer	2	-	2
Others	49	130	179
OTHER GENERAL CENTRAL SERVICE	127	83	210
TOTAL(GAZETTED)	780	3609	4389
B. Group 'B' (NON GAZETTED)	-	3496	3496
C. NON GAZETTED	GROUP "C"	GROUP "D"	TOTAL
Directorate	265	138	403
Post Offices (including Circle Office, Accounts, Stamp Depot & Canteen Staff)	160776	26683	187459
Railway Mail Service	18987	13194	32181
Mail Motor Service	1601	403	2004
Others(RLO, Disp., Store, Trg., Civil, PLI & Press)	2440	1815	4255
TOTAL(NON GAZETTED)	184069	42233	226302
TOTAL DEPARTMENTAL(A+B+C)			234187
D. GRAMIN DAK SEWAK			286004
GRAND TOTAL(A+B+C+D)			520191

तालिका 16

31.3.2006 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

समूह	अनुसूचित जाति	कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत
समूह 'क'	89	11.41	54	6.92
समूह 'ख' (राजपत्रित)	399	11.06	177	4.90
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	436	12.47	269	7.69
समूह 'ग'	33,807	18.37	12,998	7.06
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	8,107	19.58	2,987	7.21
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	674	82.00	46	5.60
योग	43,512	18.58	16,531	7.06

तालिका 17

31.3.2006 को भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और महिला कर्मचारियों की संख्या

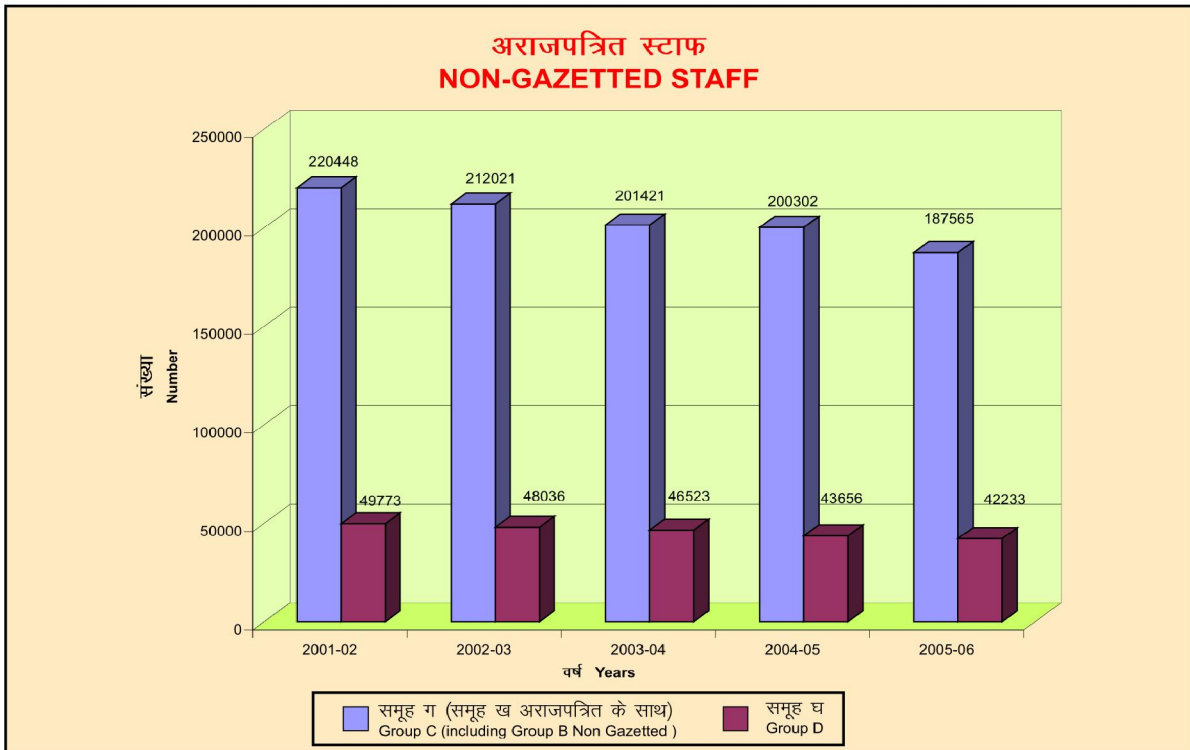
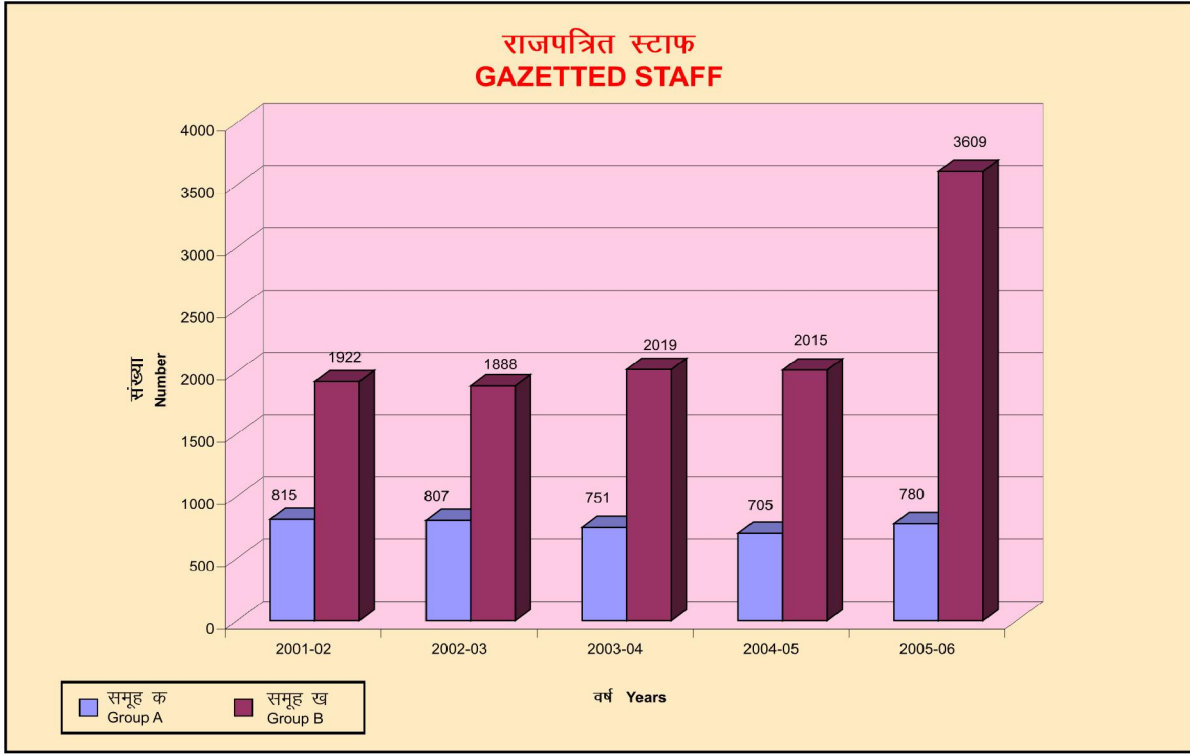
समूह	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग भूतपूर्व सैनिक	महिला
समूह 'क'	0	0	96
समूह 'ख' (राजपत्रित)	0	1	85
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	1	1	211
समूह 'ग'	1,562	21	26,638
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	253	4	4,183
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	2	1	280
योग	1,818	28	31,493

TABLE 16
NUMBER OF EMPLOYEES: SCHEDULED CASTES/TRIBES AS ON 31.3.2006

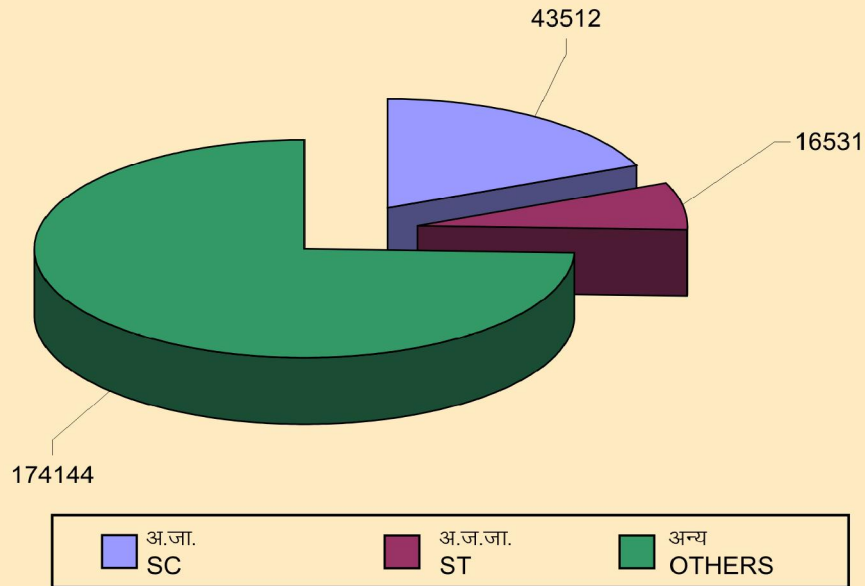
Group	Scheduled Castes	Percentage to Total no. of employees	Scheduled Tribes	Percentage to total no. of employees
Group 'A'	89	11.41	54	6.92
Group 'B'(Gazetted)	399	11.06	177	4.90
Group 'B'(Non Gazetted)	436	12.47	269	7.69
Group 'C'	33,807	18.37	12,998	7.06
Group 'D' (Excl. Sweeper)	8,107	19.58	2,987	7.21
Group 'D' (Sweeper)	674	82.00	46	5.60
Total	43,512	18.58	16,531	7.06

TABLE 17
NUMBER OF EMPLOYEES : EX-SERVICEMEN, DISABLED EX-SERVICEMEN AND WOMEN AS ON 31.3.2006

Group	Ex-Servicemen	Disabled Ex-Servicemen	Women
Group 'A'	0	0	96
Group 'B'(Gazetted)	0	1	85
Group 'B'(Non Gazetted)	1	1	211
Group 'C'	1,562	21	26,638
Group 'D' (Excl. Sweeper)	253	4	4,183
Group 'D' (Sweeper)	2	1	280
Total	1,818	28	31,493



**31.03.2006 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी (विभागीय)
SC/ST EMPLOYEES AS ON 31.03.2006 (DEPARTMENTAL)**



**31.03.2006 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारी (विभागीय)
WOMEN EMPLOYEES AS ON 31.03.2006 (DEPARTMENTAL)**

